3 राजधानी
युवाओं को दृश्य कला से जोड़ने के लिए नया कोर्स

6 अभिमत
एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

11 विदेश
ब्रिटेन में सैनिक पर हथियार से हमला

12 स्पोर्ट्स
फिर आईओसी सदस्य चुनी गईं नीता अंबानी

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 272
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए धन का आवंटन
राष्ट्रीय-10

बजट पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

बजट में किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं हुई : सीतारमण

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद के अंदर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गुट से जुड़े सांसदों ने दिन के दौरान संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्यसभा से भी वॉकआउट किया, जबकि अनुच्छेद 356 की तरह, आपातकाल लागू होने पर सत्तारूढ़ बेंच के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों के आरोपों को 'अपमानजनक' बताया और कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले बजटों सहित सभी राज्यों का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट 'भारत के संघीय ढांचे की पवित्रता पर हमला' है। सत्तारूढ़ भाजपा ने केंद्रीय बजट के विपक्षी शासित राज्यों के प्रति 'भेदभावपूर्ण' होने के कांग्रेस के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि मोदी सरकार ने हर राज्य और वर्ग का ख्याल रखा है।

संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख

नई दिल्ली में सोमवार को बजट में कथित भेदभाव के विरोध में इंडिया गुट के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वाम दलों के कई सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, आज इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ, संसद भवन परिसर में एनडीए के 'कुर्सी बचाओ बजट' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, विरोध जारी रखने के लिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों के गैर-भाजपा नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा नियम 267 के तहत नोटिस को खारिज करने के बाद, जिसमें इस मुद्दे को उठाने के लिए सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित करने का आह्वान किया गया था। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए केंद्रीय बजट केवल दो राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश - के लिए धन और योजनाएँ प्रदान की गईं। जैसे ही धनखड़ ने सीतारमण को जवाब देने के लिए मंच दिया, खड़गे ने विपक्षी दल को यह कहते हुए सदन से बाहर कर दिया कि वे विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उन्होंने आम चुनाव से पहले फरवरी में पेश (शेष पेज 9)

केंद्र का सख्त संदेश, आतंकियों का अंतिम ठिकाना जेल या जहन्नुम

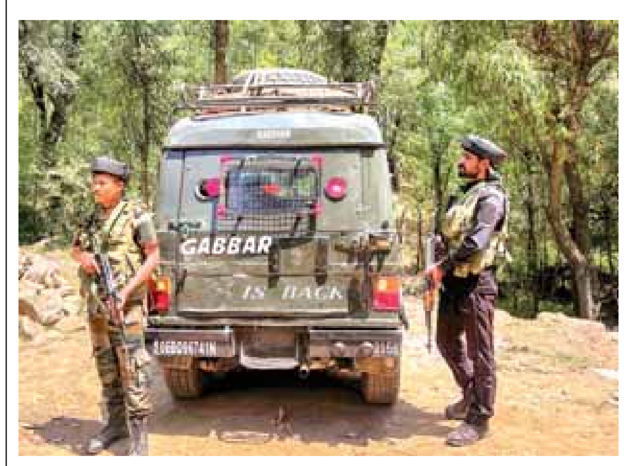

उत्तर कश्मीर के सोपोर स्थित त्रिमुखा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा में तैनात जवान।

● उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर, एक जवान शहीद

मोहित कंडारी। जम्मू/नई दिल्ली

केंद्र ने बुधवार को एक सख्त संदेश भेजा कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को या तो जेल में डाल दिया जाएगा या 'जहन्नुम' (नरक) में भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी रक्षा कोर टीम द्वारा हाल के दिनों में लगातार जम्मू आतंकी हमलों के लिए समीक्षा बैठक की श्रृंखला के कुछ दिनों बाद, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति है। इस बीच, बुधवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, जबकि भारतीय सेना के एक और जवान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहादुर की पहचान नायक (जीएनआर) दिलवर खान के रूप में की गई है। जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में आतंकवादी हिंसा की यह तीसरी घटना है। सोमवार को राजौरी की खवास तहसील में आतंकवादियों ने शौर्य चक्र विजेता के घर को निशाना बनाया, जबकि मंगलवार को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए सेना के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। .

राय ने संसद में कहा, 'मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करती। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। वे (आतंकवादी) या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में... मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हाल ही में देखी गई आतंकवादी गतिविधियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। वे (आतंकवादी) सफल नहीं होंगे। राजौरी ताजा घटना में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक सैनिक घायल हो गया, जिसने बाद में दम तोड़ दिया। चिनार कोर के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर 23 जुलाई को कुपवाड़ा के कोवुत के सामान्य क्षेत्र में भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था। 24 जुलाई को, संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई। जिसके जवाब में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले कुछ (शेष पेज 9)

बिहार विधानसभा में पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पारित

पायनियर समाचार सेवा। पटना

बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए कानून का लक्ष्य राज्य में प्रश्नपत्रों के लीक होने सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है, जो संयोग से, नीट 2024 पेपर लीक विवाद के केंद्र में भी रहा है। विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। चौधरी ने सदन को बताया कि सेवा प्रदाता, इस तरह के परीक्षण करने वाली एजेंसियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने (शेष पेज 9)

शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें: सुप्रीम कोर्ट

पीएनएस। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की एमएसपी को कानूनी रूप देने सहित विभिन्न मांगों का समाधान तलाशने के लिए उनसे बातचीत करने के वास्ते प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का बुधवार को प्रस्ताव दिया और कहा कि किसानों तथा सरकार के बीच विश्वास की कमी है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को समिति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एक तटस्थ अंपायर की आवश्यकता है जो किसानों तथा सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल

भुइयां भी शामिल रहे। इसने कहा, आपको किसानों से बातचीत करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अन्यथा वे दिल्ली क्यों आएंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके नेक इरादों के बावजूद विश्वास की कमी है। न्यायालय ने कहा, एक सप्ताह के अंदर उचित निर्देश दिए जाएं। तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी पक्षकारों को प्रदर्शन स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने दें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले स्पताह तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों को हटाने का निर्देश दिया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कें अवरुद्ध की गईं और अब उनकी नई मांगें हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को कल्याणकारी राज्य के रूप में किसानों की मांगों की पर विचार करना होगा। पीठ ने कहा, कुछ मांगें वाजिब हो सकती हैं, (शेष पेज 9)

काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत और बचाव कार्य।

काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हादसे में 18 लोगों की मौत

●पायलट गंभीर रूप से घायल, मृतकों में एक विदेशी भी

पीटीआई। काठमांडू

काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में एक विदेशी समेत 18 यात्रियों की मौत हो गई तथा उसका पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। सौर्य एयरलाइंस का नेपाल का घरेलू विमान एन9एएमई नियमित रखरखाव कार्य के लिए पोखरा जा रहा था जब पूर्वाह्न 11 बजकर 11 मिनट पर यह हादसा हुआ। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के खोज व बचाव केंद्र ने एक बयान में बताया कि बमबॉर्डियर सीआरजे-200 विमान रनवे पर फिसल गया और उसमें तुरंत आग लग गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में विमान में आग लगते और धुआं उठते देखा जा सकता है। हादसे के बाद दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। मृतकों की पहचान सह-पायलट एस. कतुवाल और सौर्य एयरलाइंस के 17 कर्मचारियों के रूप में की गई है जिनमें नेपाल की एक महिला और यमन का एक नागरिक शामिल है। पायलट कैप्टन मनीष शाक्य (37) का काठमांडू मॉडल हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। प्राधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार लोगों में से 15 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीन की एक स्थानीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद काठमांडू हवाई अड्डे पर सेवाएं थोड़ी देर के लिए रोक दी गईं लेकिन बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। (शेष पेज 9)

बाधा मुक्त टोलिंग के लिए लाएंगे जीएनएसएस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध और बाधा मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस)-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। जहां फास्टैग वाले वाहनों की लंबी कतारों की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं, शुरुआत के लिए जीपीएस पर आधारित प्रणाली का उपयोग पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाएगा।

आमतौर पर सिस्टम फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर को जियो फेंस करेगा और लागू होने वाले टोल टैरिफ को डेबिट किया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा के माध्यम से आसान पहुंच हो जाएगी। इससे समय और वाहन बैकलॉग की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में पायलट अध्ययन कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर किया गया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से एक हितधारक परामर्श आयोजित किया था, जिसके लिए इस संबंध में व्यापक औद्योगिक परामर्श के लिए वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोलिंग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की एक बाधा मुक्त विधि है जिसमें सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल राजमार्ग पर तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। एनएचएआई ने मौजूदा फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में एक हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा जहां आरएफआईडी-आधारित (शेष पेज 9)

आईएनएस ब्रह्मपुत्र हादसे में लापता नाविक का शव मिला

पीटीआई। नई दिल्ली

मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में भारत के प्रमुख युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी भीषण आग के बाद लापता हुए मुख्य नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार शाम को आग लगने के बाद युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक ओर झुक गया। नौसेना के

आईएनएस ब्रह्मपुत्र हादसे की फाइल फोटो

प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, गहन अभियान के बाद आज मुख्य नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और भारतीय नौसेना के सभी कर्मी सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मधवाल ने कहा कि नौसेना प्रमुख ने आईएनएस ब्रह्मपुत्र को फिर से समुद्री अभियानों में सक्षम बनाने और लड़ाकू भूमिका के लिए तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिरल त्रिपाठी ने आईएनएस ब्रह्मपुत्र के चालक दल से पोत के शीघ्र परिचालन की दिशा में काम करने का आह्वान किया। नौसेना ने एक बयान में कहा, नौसेना प्रमुख ने निर्देश दिया है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को समुद्री अभियानों के लिए समक्ष बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के वास्ते कमान और नौसेना मुख्यालय द्वारा सभी कार्वाई तत्काल शुरू की जाए। (शेष पेज 9)

कार के बोनट पर स्टंट कर रहा था स्पाइडरमैन, हजारों का कटा चालान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सोशल मीडिया के दौर में रील बनाकर मिनटों में शोहरत पाने की चाह का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई युवा इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोअर्स को लुभाने के लिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर खुद के साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी कड़ी में स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर स्कार्पियो कार के बोनट पर बैठकर दिल्ली में घूमना एक युवक को महंगा पड़ा। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर उसका 26 हजार रुपए का चालान किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए शिकायत मिली कि द्वारका की सड़कों पर एक युवक स्पाइडरमैन की वेशभूषा में स्कॉर्पियो कार के बोनट पर बैठकर घूम रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार का पीछा किया और द्वारका के रामफल चौक के नजदीक उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन की वेशभूषा वाले व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ निवासी आदित्य के रूप में हुई जबकि कार महावीर एन्क्लेव निवासी गौरव सिंह चला रहा था।

अधिकारी ने बताया कि वाहन के मालिक और चालक को खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने, सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने के आरोप में चालान काटा गिया है जिसमें अधिकतम 26 हजार रुपए जुर्माना या कारावास या दोनों सजा का प्रावधान है। दिल्ली यातायात पुलिस सभी नागरिकों के लिए सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। अधिकारी

पुलिस की गिरफ्त में स्पाइडरमैन बना युवक।

ने कहा कि सड़क पर इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस युवक ने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के मकसद से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। इससे पहले, उसे दक्षिण पश्चि दिल्ली के द्वारका में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद, ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और उसे स्पाइडरवुमन की पोशाक पहने एक अन्य महिला के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान जारी किया। खुद को नजफगढ़ का स्पाइडरमैन कहने वाला यह युवक कई बार सुपरहीरो की पोशाक पहनकर दिल्ली की सड़कों पर निकल चुका है। वह इंडियन स्पाइडी ऑफिशियल नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है, जहां वह अपने स्टंट के वीडियो पोस्ट करता है।

लड़के के डीपी में लिखा है योर फ्रेंडली नेबरहुड इंडियन स्पाइडी और अकाउंट के 12,500 से ज्यादा फॉलोअर हैं। वायरल वीडियो को एक लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। उसके इंस्टाग्राम पेज पर एक सरसरी नजर डालने पर इंडियन स्पाइडी बैडमिंटन खेलता, ट्रैक्टर चलाता और ट्रेंडिंग गानों पर नाचता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से सड़कों पर इस तरह से खतरनाक स्टंट नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई इस तरह की हरकत करना पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों से खतरनाक ड्राइविंग या यातायात नियमों के किसी तरह के उल्लंघन करने की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा बनाए रखने और शहर में यातायात के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है।

अयोध्या को जल्द मिल सकती है 110 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थ विकास परिषद की बैठक कर योजनाओं को दे सकते है हरी झंडी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

भले ही अयोध्या में मां सरयू प्रवाहमान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार रामनगरी में विकास की गंगा का अवतरण कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हाल ही में गठित हुए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद भी योजनाओं का पिटारा खोलने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर 110 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं।

रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से कई योजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के पास 11 प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। 110 करोड़ की इन परियोजनाओं पर परिषद की बैठक में मंजूरी

मिलना तय है। इसी महीने सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तीर्थ विकास परिषद की बैठक संभावित है। बता दें कि अयोध्या में 32 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू करने तैयारी हो रही है। रामनगरी की पौराणिकता की गवाह मणिपर्वत का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मणिपर्वत भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यहां हर साल सावन माह में मेला लगता है। रामनगरी में झूलनोत्सव का शुभारंभ मणिपर्वत मेले के साथ ही होता है।

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के सीईओ संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अयोध्या के नियोजित विकास के लिए विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के प्रस्ताव तीर्थ विकास परिषद को मिले हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के 8 और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 3 प्रस्ताव हैं। इन सभी योजनाओं की कुल कीमत करीब 110 करोड़ होगी। इन योजनाओं के मूर्त रूप लेने से रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इन परियोजनाओं को मिलेगी स्वीकृति

- सभी प्रमुख स्थलों पर साइनेज लगवाने की योजना
- सरयू तट पर शिल्पकला एवं फाउंटेन व सौंदर्यीकरण का कार्य
- आचार्य नरेंद्र देव विवि के परिक्षेत्र में स्थित गुलाबबाड़ी का सौंदर्यीकरण
- राम की पैड़ी कैनाल से एनएच-27 तक सोतिया नाला का निर्माण
- मणि पर्वत के चारों तरफ एएसआई क्षेत्र छोड़ कर पाथवे का निर्माण
- फ्लोरिंग, बेच, साइनेज, लाइट एवं लेजर, पारदर्शी स्क्रीन, फूड क्योस्क का निर्माण
- अयोध्या के विभिन्न स्थलों का सौंदर्यीकरण
यात्रियों के रुकने व विश्राम की व्यवस्था का कार्य
- अयोध्या के कौशलेश सदन के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण
- संत निवास का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण

फिटनेस प्रमाण पत्र न देने पर आरआई निलंबित एआरटीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी का एक्शन जारी है। ताजा घटनाक्रम में योगी सरकार ने जनपद चित्रकूट के अंतर्गत स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लेते हुए जिले के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली न की जाए। खासतौर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों पर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दरअसल, मंगलवार 23 जुलाई को जनपद चित्रकूट के श्रीजी इंटर कॉलेज, खोह के छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आ रही दो बसों को वाहन की फिटनेस समाप्त हो जाने के कारण सहायक संभागीय परिहन अधिकारी (प्रवर्तन) चित्रकूट की टीम द्वारा सीज कर बच्चों सहित 10 किमी दूर पुलिस लाइन ले जाया गया था। वाहन को 11.15 बजे सीज कर फायर सर्विस परिसर पुलिस लाइन में दाखिल किया गया व 13.05 बजे छोड़ा गया। इसके चलते करीब दो घंटे तक बस को खड़ा रखा गया। जानकारी के अनुसार, चित्रकूट जनपद के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को संबंधित स्कूलों में जाकर स्कूली बसों के फिटनेस चेक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई, जिसके कारण दोनों वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाया। ऐसे में वाहनों को सीज करना पड़ा, जिससे बच्चों को भी तकलीफ हुई।

बुधवार को मामला संज्ञान में आने के बाद योगी सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विवेक कुमार शुक्ला के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। साथ ही, प्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़े समस्त कर्मियों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के पहले वाहन परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र का उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को लखनऊ में वाहन परीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र का उद्घाटन किया गया। उक्त केन्द्र पर वाहनों की फिटनेस के साथ-साथ चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा मुहैया होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि चालकों के स्वास्थ्य परिक्षण से बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुचने में मदद होगी। साथ ही चालक भी सुरक्षित होगें। परिवहन मंत्री ने बताया कि उक्त फिट्नेस सेन्टर के खुलने से लखनऊ में और अधिक संख्या में वाहनों की जांच हो सकेगी। साथ ही चालकों की सामान्य बीमारियां जैसे- ब्लड प्रेशर, सुगर आदी के साथ उनका नेत्र परीक्षण भी हो सकेगा। चालकों को निशुल्क चश्मा भी मुहैया कराया जायेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि जांचोंपरान्त चालकों की कॉउन्सलिंग भी की जायेगी। चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ में इस तरह का पहला केन्द्र खोला गया है जहां नियमित जांच की सुविधा उपलब्ध होगी।

भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गयाः अखिलेश यादव

● सपा अध्यक्ष ने कहा, केन्द्र सरकार ने यूपी को बजट में कुछ विशेष देना तो छोड़िए उसका नाम तक नहीं लिया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने दस साल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है। जनता का शोषण किया है। यह बजट नहीं चपत है। इस बजट ने लोगों को चपत लगा दिया। बजट से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है। डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश की आस पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पास नौकरी का संकट है। यह सरकार युवाओं को सम्मान जनक रोजगार नहीं दे सकती है। भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया।

जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है उसके साथ भेदभाव हुआ। यादव ने कहा कि सरकार को जानकारी है कि कैंसर की बीमारी बढ़ रही है लेकिन भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के दौरान लखनऊ में बनाये गये कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे रही। सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं चला पा रही है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार से बजट में कुछ मांगा ही नहीं। केन्द्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ विशेष देना तो छोड़िए उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जहां तक बनाया था आज भी वहीं तक रह गया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को गाजीपुर बलिया से बक्सर तक जोड़ दिया जाता तो देश में भागलपुर से दिल्ली तक पूरा एक्सप्रेस-वे मार्ग मिल जाता लेकिन सरकार ने उसके लिए बजट नहीं दिया। यादव ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले को लेकर शीर्ष कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि सौहार्द की जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है। जनता नफरत के खिलाफ एकजुट है। भाजपा अब नफरत फैलाने में सफल नहीं होगी। भाजपा का कम्युनल मुद्दा खत्म हो गया है। सम्प्रदायिकता का दिया आखिरी समय में फड़फड़ा रहा है।

यादव ने कहा कि केन्द्र की सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। यह बहुमत की सरकार नहीं है।

गरीबों के पक्के मकान का सपना होगा पूराः केशव

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहा कि गरीब कल्याण व समग्र विकास पर केंद्रित केन्द्रीय बजट में ग्रामीण विकास व ग्रामोन्मुखी योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोला गया है।

बजट में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में दो करोड़ आवास आवंटित करने का प्राविधान किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में पहले से चिन्हित 60 हजार से अधिक पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जायेंगे, उसके बाद भी सर्वे कराया जायेगा, सर्वे के आधार पर जो पात्र पाये जायेंगे, उन्हें आवास आवंटित कराने की व्यवस्था की जायेगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यूपी के लिए 2020 करोड़ रूपए की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

सूचित हो कि मेरी पुत्री अस्काह खान (Asqah Khan) के विद्यालय के अभिलेखों में मेरे पति का नाम अजहर खान (Ajahar Khan) अंकित है जोकि गलत है। मेरे पति का सही व वास्तविक नाम स्व० मो० अज़हर खान (Late Mohd Azhar Khan) है जो कि अंकित किया जाना आवश्यक है। अंजुम नसीम पत्नी स्व० मो० अज़हर खान निवासिनी-337/55क, मंसूर नगर पुलिस चौकी के सामने, कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ

सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरा नाम शरिता यादव था, जो कि गलत है। मेरा सही नाम सरिता यादव है। मुझे अब इसी नाम से जाना पहचाना जाये। सरिता यादव पत्नी अखिलेश यादव ग्राम राघोपुर, पोस्ट कंधरापुर, जिला आजमगढ़।

सूचना

मैंन अपने पुत्र मुकेश कुमार चौहान व उसकी पत्नी निधि सिंह चौहान को उनके गलत आचरण, चाल चलन, आये दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने व कहना न मानने के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। पुत्र मुकेश कुमार चौहान व उसकी पत्नी निधि सिंह चौहान द्वारा किये गये किसी भी कार्य में शपथी तथा परिवार के किसी भी सदस्य का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा। गंगा राम चौहान पुत्र स्व० जय करन चौहान निवासी-536/2/78- न्यू मदेहगंज, खदरा, लखनऊ

सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आदित्य कुमार यादव था, जो कि गलत है। उसे अब आदित्य यादव के नाम से जाना पहचाना जाये। अखिलेश यादव पुत्र सतिराम यादव ग्राम राघोपुर, पोस्ट कंधरापुर, जिला आजमगढ़।

NOTICE

I have changed my name from SHAMBHAVI KESHARWANI TO SHAMBHAVI KESARWANI for all future purposes, Shambhavi Kesarwani D/o Uttam Prasad Kesarwani R/o 7/181, Bungalow No.6, Exotica, Swaroop Nagar Kanpur.

सूचना

सर्व विदित हो कि मैंने अपने पुत्र का नाम अभिनव रंजन से बदलकर रोहित रंजन कर दिया है अतः आज से मेरे पुत्र को समस्त अभिलेखों में रोहित रंजन (ROHIT RANJAN) पढ़ा लिखा एवं समझा जाये तारा पत्नी स्व. सौरभ रंजन 16/998 इंदिरा नगर लखनऊ

सूचना

मेरी पुत्री ओजस्वी के स्कूल रिकार्ड में जया चौरसिया लिखा है जो कि गलत है। मेरा सही नाम जया (JAYA) है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। जया W/O श्री आशुतोष निवासी- 19/636 इन्दिरा नगर लखनऊ।

सूचना

सूच्य हो कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 217657533 में मेरा नाम हिमांशू शुक्ला दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व मार्कशीट में मेरा नाम अक्षय कुमार शुक्ल दर्ज है। हिमांशू शुक्ला और अक्षय कुमार शुक्ल दोनों ही नाम मेरे हैं।मुझे दोना. नामों से जाना व पहचाना जाता है। हिमांशू शुक्ला उर्फ अक्षय कुमार शुक्ल पुत्र मुकेश चंद्र शुक्ल निवासी-ग्राम व परगना-पसगवां,तहसील-मोहम्मदी,जिला-खीरी (उ.प्र.)

किसानों को मिलेगी 12 घंटे निर्बाध बिजली

● ऊर्जा मंत्री ने कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में की दो घंटे की बढ़ोत्तरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किसानों को और सुविधायें देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कृषि पोषकों (एग्रीकल्चर फीडर) पर 10 घण्टे के स्थान पर अब 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की रोपाई, सिचाई और अन्य कृषि कार्यों में कोई समस्या न हो, इसके लिए कृषि फीडरों के निर्धारित 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के शिड्यूल में 2 घंटे और बढ़ाकर अब 12 घंटे बिजली दी जायेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कम

वर्षा होने से किसानों को धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्यों को करने तथा फसल को सूखने से बचाने के लिए परेशानी हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में जहां फसलों की सिंचाई के लिए नहरे नहीं हैं तथा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, वहां पर किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कृषि पोषकों को मिल रही बिजली में 2 घंटे की बढ़ोत्तरी की गयी है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये है कि प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फीडरों को 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। साथ ही सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता (वितरण) व मुख्य अभियन्ता (पीएमसी) द्वारा नियमित इसकी मॉनीटरिंग की जाए। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति सामान्य होने पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सिंचाई की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों की ओर से कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी की लगातार मांग की जा रही थी।

दुबई में फंसे यूपी के नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए मंत्री एके शर्मा ने पीएम को दिया धन्यवाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) में फंसे उप्र के नागरिकों की मदद की है। उन्होंने यूएई में फंसे प्रदेश के मऊ एवं कानपुर देहात के 2 नागरिकों की त्वरित सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से सम्पर्क कर उनकी सुरक्षा और शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री के आदेश पर उनके कार्यालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय काउंसलेट को निर्देश दिये गये। इस पर भारतीय काउंसलेट ने वहां फंसे इन भारतीय नागरिकों से तुरंत संपर्क किया और उनसे उस स्थान पर जाकर मुलाकात की। जहां पर उन्हें रखा गया था। इस त्वरित कार्यवाही से संदिग्ध ट्रवेल एजेंटों के चंगुल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को काफी राहत मिली है। जिसकी मऊ और कानपुर जिलों में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही।

शर्मा ने बताया कि मऊ जिले के रहने वाले विशाल सिंह पुत्र संजय सिंह और कानपुर देहात ज़िले की सर्वेश कुमारी पत्नी मनोज यादव अच्छे और बेहतर जीवन की तलाश में दुबई गए। लेकिन उनके एजेंटों एवं संभावित नियोक्ता द्वारा धोखा दिया गया। इतना ही नहीं उनके नियोक्ता ने भारतीय नागरिकों पर दबाव डालकर उनसे ऋण के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और उनके नाम पर स्वयं ऋण प्राप्त कर लिया। इस कारण यह लोग दुबई में कानूनी एवं आर्थिक मामलों के केस में फंस गए और उनको कोई नौकरी भी नहीं मिली। ऋण न चुका पाने के कारण उनके दुबई छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अतः वह भारत वापस भी नहीं आ सकते थे। उन्होंने बताया कि अब से कुछ दिन पहले मऊ निवासी विशाल के पिताजी ने मुझसे इस विषय में संपर्क किया।

उन्होंने बताया कि दुबई में उनके बेटे और एक महिला का जीवन संकट में है। इस समस्या को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके उनसे इस मामले में सहायता करने का आग्रह किया। शर्मा ने बताया कि भारतीय काउंसलेट ने इन भारतीय नागरिकों को अपने एजेंट एवं नियोक्ता के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने में भी सहायता की। भारतीय काउंसलेट ने इस मामले को विदेशी मामलों के मंत्रालय, दुबई, के समक्ष भी रखा है और इस संबंध में उनके सामने औपचारिक निवेदन भी प्रस्तुत किया है।

बजट में चीन को आयात शुल्क में भारी कटौती दिए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

● देशवासी जानना चाहते हैं, आरएसएस, बीजेपी और एनडीए सरकार का चाइना के साथ क्या रिश्ताः डॉ. सीपी राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मीडिया विभाग चेयरमैन पूर्व मंत्री डा.सी पी राय ने कहा कि 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' का शिगूफा छोड़ने वाली मोदी सरकार ने बेतहासा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दौर में पेश किये गये बजट में चीन के साथ अत्यंत नरमी बरतते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट पर 'आयात शुल्क' या तो समाप्त कर दिया है या ना के बराबर कर दिया है। डॉ. राय ने कहा कि देशवासी जानना चाहते हैं मौजूदा 'भारत चाइना सीमा विवाद' के बीच आरएसएस, बीजेपी और एनडीए सरकार का चाइना के साथ क्या रिश्ता है? एनडीए सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. राय ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि इस आर्थिक लाभ का प्रयोग चीन भारत के ही खिलाफ हमारी सीमाओं पर कब्जे और षड्यंत्र के लिए कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2023-24 में भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118 अरब डॉलर के करीब है। जिसमें भारत से चीन को होने वाला निर्यात सिर्फ तकरीबन 17 अरब डॉलर का है। इस तरह से भारतीय व्यापार घाटा 84 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। वहीं आज चीन हमारी भारतीय सीमाओं के अंदर करीब 6000 किलोमीटर जमीनों पर जबरन कब्जा भी कर चुका है, जहां पर चीन पुल सड़क बना रहा है और बस्तियां बसाने के साथ ही अपनी फौजी छावनी बनाने में लगा हुआ है। डा. राय ने कहा कि मौजूदा बजट में चीन को आयात शुल्क में भारी कटौती दे कर भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया गया है।

गुड गवर्नेंस को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम व तहसीलदार

● मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है। संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें। सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे।

हाथरस हादसे से सबक लेकर डीजीपी ने भीड़ प्रबंधन को लेकर जारी की एसओपी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीते दिनों हाथरस जिले में प्रवचन के दौरान भगदड़ मचने से हुई हृदयविदारक घटना में सौ से अधिक लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। हाथरस से पहले भी लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी और प्रयागराज (इलाहाबाद रेलवे स्टेशन) आदि जिलों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेते हुए राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ऐसे कार्यक्रमों के दौरान भीड़ नियंत्रण और पुलिस व्यवस्थापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित कर दी है। डीजीपी ने बुधवार को फील्ड में तैनात पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एसओपी जारी करते हुए इसमें निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः पालन करने के आदेश दिए हैं।

एसओपी में जिन प्रमुख बिन्दुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं उनमें किसी भी भीड़ जनित आपदा

के दृष्टिगत जनपद/ कमिश्नरेट/ परिक्षेत्र और जोन स्तर पर एक एकीकृत प्रणाली विकसित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों तथा स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से उसे विकसित व अपडेट किया जाए। आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त विभागों को सम्मिलित करते हुए नियमित पूर्वाभ्यास किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों का समावेश करते हुए उक्त योजना को नियमित रूप से प्रतिवर्ष अपडेट/ अपग्रेड किया जाए।

जनपद की पुलिस लाइन में विशेष आयोजनों में सुरक्षा, भीड़ नियन्त्रण तथा सुव्यवस्थित यातायात संचरण के दृष्टिगत आवश्यक संसाधनों व उपकरणों की नियमित देखरेख व कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। सभी स्तरों पर समस्त राजकीय व निजी अस्पतालों को चिन्हित कर लिया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट व अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमतिकर्ता अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा यह पूर्णरूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार का कोई खतरा विद्यमान नहीं है तथा उस स्थल पर आगन्तुकों का सुरक्षित आवागमन सम्भव है। विशिष्ट अतिथियों के आगमन का मार्ग, जोन सेक्टर स्कीम प्रबन्धन तथा कन्टिनजेन्सी प्लान के सम्बन्ध में कार्ययोजना पहले से बना ली जाए। कार्यक्रम से सम्बन्धित थ्रेट प्रेसकेप्शन के अनुसार अन्य सम्भावित खतरों यथा-अग्निजनित दुर्घटना, विद्युत जनित दुर्घटना, मार्ग दुर्घटना, श्वास अवरोध आदि के सम्बन्ध में समुचित आकंलन करते हुए आपात कालीन योजना के अनुसार यथोचित व्यवस्थापन हो। समस्त सम्बन्धित विभागों यथा- नोडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेन्सी, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, एयरपोर्ट सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त एजेन्सी तथा प्रोटोकॉल / जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाए। आयोजन के दौरान प्रबन्धन व व्यवस्थापन एसओपी में जिन बिन्दुओं को इंगित किया गया है उनमें राजपत्रित अधिकारी व स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभ्ररी नियुक्त किया जाना। ड्यूटी पर लगाये गये समस्त पुलिस, पीएसी, सीएपीएफ, अग्निशमन अधिकारियों की समुचित ब्रीफिंग व डीब्रीफिंग। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यथा- लाउड हेलर, आदि का प्रयोग करते हुए ड्यूटी पर लगाये गये समस्त बल को सक्रिय किया जाना।

अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करना। अफवाह फैलाने वाले तथा असामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखा जाना। आवश्यकतानुसार पुलिस बल के साथ-साथ विभिन्न अनुपूरक बलों यथा- सिविल डिफेन्स, एसपीओ, होमगार्ड, ग्राम चौकीदार, पुलिस मित्र, एस-10 सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मियों व सी-प्लान ऐप के सदस्यों आदि का भी समुचित प्रयोग। भीड़ नियंत्रण योजना के अनुरूप व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन तथा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त तथा विशिष्ट अतिथियों के आवागमन का मार्ग आम जनमानस के मार्ग से पृथक रखा जाना अथवा उनके आवागमन का समय अलग- अलग रखा जाना। जनपदीय अभिसूचना तन्त्र, सोशल मीडिया सेल तथा कण्ट्रोल रूम को सतर्क करते हुए सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखा जाना। इस संबंध में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना।

कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

// ई-प्रोक्ययोरमेंट निविदा सूचना //

क्रं./802/लो.क.वि./न.पा./2024 कुम्हारी, दिनांक 23/07/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	अनु. ला. (लाख में)	निविदा डालने की अंतिम तिथि
156551	स्वच्छता विभाग हेतु कुशल एवं अकुशल 81 श्रमिकों की आपूर्ति बाबत्।	123.78	14.08.2024

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, कुम्हारी

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंच से देंगी एकेटीयू के छात्रों को स्टार्टअप अवार्ड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय 13 अगस्त को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में अपने छात्रों को इस बार सात श्रेणियों में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड देगा। मंच से राज्यपाल सहकुलाधिपति आनंदीबेन पटेल छात्रों को अवार्ड देकर सम्मानित करेंगी। पिछले साल पहली बार शुरू किया गया यह अवार्ड तीन श्रेणियों में दिया गया था। स्टार्टअप अवार्ड पाने के लिए छात्रों को 5 अगस्त तक आवेदन करना होगा।

कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के निर्देशन में इस अवार्ड की परिकल्पना इनोवेशन हब ने की है। इसके तहत सात विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिया जाएगा। इनमें एक अवार्ड वूमेन लेड स्टार्टअप अवार्ड, दूसरा बेस्ट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप अवार्ड और तीसरा बेस्ट टेक इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड, चौथा एक्सेसिबिलिटी अवार्ड, पांचवां एग्रीकल्चर स्टार्टअप अवार्ड, छठा सस्टेनेबिलिटी चैंपियन और सातवां हेल्थ इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड है। बेस्ट वूमेन लेड स्टार्टअप अवार्ड के लिए स्टार्टअप कंपनी में एक महिला डायरेक्टर का 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ होना जरूरी है। वहीं, बेस्ट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड का चयन स्वास्थ्य, भारतीय भाषा, शिक्षा, जीवनशैली जैसे सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्टार्टअप कंपनी को दिया जाएगा। बेस्ट टेक इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड इनोवेटिव पेटेंट तकनीकी विकसित कर वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र और डिजिटल मंच पर कार्य करने वाली स्टार्टअप कंपनी को मिलेगा। इसी तरह दिव्यांगों की सुविधा प्रदान करने वाले स्टार्टअप को एक्सेसिबिलिटी अवार्ड दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में नवाचार सहित अन्य नए स्टार्टअप को एग्रीकल्चर अवार्ड मिलेगा। जलवायु परिवर्तन, कूड़ा प्रबंधन, नवीकरणीय एनर्जी से जुड़े स्टार्टअप को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड दिया जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़े स्टार्टअप को हेल्थ इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड मंच से दिया जाएगा। यह अवार्ड विश्वविद्यालय के किसी छात्र या छात्रा की स्टार्टअप कंपनी को ही दिया जाएगा। संस्थान या छात्र अवार्ड के लिए 5 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं।

यह है उद्देश्य

पहली बार विश्वविद्यालय की ओर से दिए जा रहे स्टार्टअप अवार्ड का मकसद विश्वविद्यालय के छात्रों में स्टार्टअप और इनोवेशन के प्रति रूझान पैदा करना है। इस पहल से अन्य छात्र भी स्टार्टअप के लिए प्रेरित होंगे।

केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं : जस्टिस राजीव कुमार

● **नेशनल पीजी कालेज के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया स्थापना दिवस**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को नेशनल पीजी कालेज का स्थापना दिवस उत्सव की तरह मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव कुमार माननीय न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर संस्था के पूर्व प्राचार्य, प्रो एसपी सिंह थे।

कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो देवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में हमें मिली सफलताओं का जश्न मनाने और भविष्य के लिए हमारी योजनाओं को साझा करने के लिए उत्साहित हैं। हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हमारे साथ शामिल होने के लिए आभार प्रकट करते है। यह समारोह महाविद्यालय के शानदार इतिहास और उन सभी लोगों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने इसकी सफलता में योगदान दिया है। प्रो डीके सिंह ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और पचास साल की लंबी यात्रा के के सफर पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे एक शैक्षणिक संस्थान में क्या सीखते हैं - कोई बात कहाँ कही जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि आज की दुनिया में इसका प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं देती, बल्कि समाज में कैसे जीवित रहना है और कैसे आचरण करना है, यह भी प्रदान करती है। एक पौराणिक कहानी का उदाहरण लेते हुए उन्होंने छात्रों को समाज को रहने लायक स्थान में बदलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'अभिव्यक्ति' का विमोचन किया।

विशिष्ट अतिथि प्रो. एस पी सिंह कहा कि यदि किसी को आसमान तक पहुंचना है तो एक निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य के साथ लगातार सही दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर देना होगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 48 साल लंबे जुड़ाव के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर 2024 के मेधावी छात्र-छात्रों को नकद पुरस्कार के साथ स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों के 2024 के 60 टॉपर छात्रों को मेडल, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी -बी काम के प्रफुल्ल सिंह, सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट बीएससी की नेहा यादव, सर्वश्रेष्ठ वक्ता मृणाली दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ रोवर्स स्काउट गाइड बीए के उदय सिंह, सर्वश्रेष्ठ रेंजर्स/ गाइड बीकाम की शालिनी सिंह, सर्वश्रेष्ठ एनएसएस बीसीए के प्रिंस मिश्रा सहित कुछ अन्य छात्र थे जिन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक प्रो रामकृष्ण जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया और मंच का संचालन डॉ. नेहाश्री श्रीवास्तव ने किया।

शोध और जीवन के सार को समझना आवश्यक

● **बीबीएयू में हुआ व्यास पूजा एवं शोध आनंद शाला कार्यक्रम का आयोजन**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बुधवार को गृह विज्ञान विद्यापीठ, बीबीएयू एवं भारतीय शिक्षण मंडल, अवध प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में व्यास पूजा एवं शोध आनंद शाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. एम. पी. वर्मा के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आईक्यूएसी डायरेक्टर प्रो. राम चन्द्रा ने की।

प्रो. राम चन्द्रा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शोध और जीवन के सार को हम सभी को समझना आवश्यक है। हमारे जीवन में राष्ट्र की महत्पूर्ण भूमिका है। हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए एवं राष्ट्र की प्रगति हेतु दिन-रात अथक प्रयास करने चाहिए। मुख्य वक्ता प्रो. प्रीति सक्सेना ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में समय प्रबंधन करना आना चाहिए। शोधकार्य एक खोज की यात्रा के समान है, क्योंकि वह नए ज्ञान की खोज या किसी विषय को गहराई से समझने का एक गंभीर प्रयास है। साथ ही इन्होंने शोधपत्र लेखन विषय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। अमित रावत ने गुरु ज्ञान की महत्ता बताते हुए भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यों का विवरण दिया। साथ ही विकसित भारत के लिए शोध को महत्वपूर्ण बताते हुए विद्यार्थियों को शोध कार्यों में बढ़- चढकर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। प्रो. गौरव कैथवास ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। जो अपनी जिज्ञासा के फलस्वरूप ज्ञान की खोज में सदैव तत्पर रहता है। कार्यक्रम के दौरान सभी को गुरु शिष्य परंपरा के महत्व के बारे में बताया गया एवं शोध पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गयी।

समस्त कार्यक्रम के दौरान प्रो.डी. आर. मोदी, प्रो. विपिन सक्सेना, प्रो. दीपा. एच. द्विवेदी, प्रो. संगीता सक्सेना, प्रो. नवीन कुमार अरोरा, , डॉ. रवि शंकर वर्मा, डॉ. बलजीत श्रीवास्तव, डॉ. प्रियंका शंकर, डॉ. के. शर्मिला, डॉ. नरेंद्र, डॉ शिव शंकर सहित अन्य शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।

युवाओं को दृश्य कला से जोड़ने के लिए नया कोर्स प्रारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

संस्कृति विभाग की ओर से उप्र राज्य ललित कला अकादमी ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर युवाओं को दृश्यकला से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट (बीवीए चित्रकला) की नियमित 4 वर्षीय कोर्स को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से 15 अगस्त 2024 तक है।

राज्य ललित कला अकादमी की निदेशक डॉ. श्रद्धा शुक्ला के अनुसार बीवीए (चित्रकला) में 20 सीटें हैं। इसमें प्रवेश लेने के लिए पंजीकरण शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्लूएस एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए निर्धारित हैं। आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं ने किसी भी मान्यता प्राप्त इण्टर कॉलेज से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। निदेशक ने बताया कि प्रति सेमेस्टर शुल्क 6000 रुपए एवं परीक्षा शुल्क 800 रुपए अतिरिक्त देय होगा। अकादमी द्वारा बीवीए शैक्षणिक सत्र के दौरान लखनऊ की प्रसिद्ध वॉश तकनीकी जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्रचलित होकर लखनऊ की पहचान बनी, इस तकनीकी का ज्ञान एवं संवर्धन अध्ययनरत छात्रों को कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न लोक चित्रशैली की तकनीकी का शिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्र-छात्राओं में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा।

केजीएमयू में चला वृहत वृक्षारोपण अभियान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद , प्रो. जिलेदार रावत (प्रोवोस्ट), प्रो. अनित परिहार (एडिशनल प्रोवोस्ट), डॉ अभिषेक बहादुर सिंह (असिस्टेंट प्रोवोस्ट), प्रो. क्षितिज श्रीवास्तव (चीफ प्रॉक्टर), प्रो. आर.ए.एस. कुशवाहा (अधिष्ठाता छात्र कल्याण), प्रो. बी. के. ओझा (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक), प्रो. परवेज अहमद (प्रभारी, पर्यावरण विभाग) द्वारा रेजीडेन्ट छात्रावास में नवीनीकृत मेस का उदघाटन किया गया। साथ ही साथ छात्रावास में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में छात्रावास में निवासित लगभग 50 छात्र छात्राएं एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान कुलपति द्वारा मेस के खाने की गुणवत्ता एवं साफ सफाई का निरीक्षण किया गया।

एलयू में राजस्व कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर शोध

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग मे राजस्व कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर शोध किया गया। शोध का विषय था राजस्व कर्मियों के बीच पनप रहे समृद्धि के मनोसामाजिक सहसंबंध। जिसे मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना शुक्ला की मार्गदर्शन में शोध छात्रा, गरिमा सिंह द्वारा पूर्ण किया गया। यह शोध सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य उत्थान और समृद्धि में योगदान देने वाले कारकों और राजस्व कर्मियों के व्यापक कल्याण के अन्य पहलुओं को समझने पर केंद्रित है। शोध में क्लास 2 श्रेणी के कुल 150 राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गया। समृद्धि से आशय है, सुखी और सार्थक जीवन जीना। शोध में यह पाया गया की दोनों महिला एवं पुरुष अधिकारियों द्वारा समृद्धि की अनुभूति की गयी। अध्ययन में महिला राजस्व कर्मियों ने समृद्धि की व्याख्या खुशी और संतुष्टि के संदर्भ में की है। जबकि पुरुष कर्मियों ने इसे सफलता और क्षमता के संदर्भ में बताया है। महिला अधिकारियो द्वारा परिवार को अपना सबसे बड़ा सहारा बताया गया। जबकि पुरुष अधिकारियो ने अपने मित्रो को बड़ा सहारा बताया। राजस्व कर्मियो में आत्मस्वीकृति एवं कार्य के प्रति लगन भी अधिक देखी गयी।

राजस्व कर्मियों का देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। यह शोध राजस्व कर्मियों के सकरात्मक मानसिक स्वस्थ्य को समझने में मदद करती हैं एवं भविष्य में इससे और अच्छा कैसे किया जाय ये जानने में मदद करती हैं। शोध द्वारा वैयक्तिक और सामाजिक उत्कर्ष, एवं समग्र विकास के विषय में गहन जानकारी मिलती हैं। शोधार्थी गरिमा सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में राज्य कर अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

अब निडिल बतायेगी सही जा रही या गलत

● **पीजीआई द्वारा निडिल पर किये गये शोध को मिला पेटेंट**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अब सेंट्रल वेनस में लगने वाली निडिल (सुई) बतायेगी कि वह सही स्थान पर इंजेक्ट हो रही है या नहीं। इसको लेकर पीजीआई द्वारा निडिल पर किये गये शोध को पेटेंट मिल गया है। पेटेंट वर्ष 2016 में किया गया था।

क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सेंट्रल वेनस कैन्युलेशन (सीवीसी) का उपयोग कई गुना है। इसका उपयोग वॉल्यूम पुनर्जीवन, कुल पैरेंट्रल पोषण, रक्त उत्पाद चढ़ाने, शिरापरक दबाव की निगरानी और कार्डियक पेसिंग के लिए किया जाता है। ब्लाइंड सेंट्रल वेनस कैन्युलेशन की आईट्रोजेनिक जटिलताओं की घटना अत्यधिक है। केंद्रीय शिरा को ढूंढने मे और कैन्युलेशन के लिए अल्ट्रासाउंड के उपयोग ने इन आईट्रोजेनिक जटिलताओं को काफी कम कर दिया है; इतना कि अल्ट्रासाउंड निर्देशित केंद्रीय शिरा कैनुलेशन अब एक अनुशंसित अभ्यास बन गया है। इस सुई का उपयोग केंद्रीय शिरा के पंचर के लिए किया जाता है और यह ब्लाइंड और अल्ट्रासाउंड निर्देशित केंद्रीय शिरा कैनुलेशन दोनों के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में एक आवश्यक कदम है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. तन्मय घटक ने कताया कि अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन का उपयोग करने पर भी सुई की नोक को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। चूंकि केंद्रीय धमनी या फेफड़े के फुस्फुस का आवरण जैसी महत्वपूर्ण शारीरिक संरचनाये अत्यंत निकटता में स्थित होती हैं, यहां तक कि अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के बावजूद ब्लाइंड टिप के कुछ मिलीमीटर हरकतो से आकस्मिक परेशानियां पैदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इंटेंसिविस्ट पूरी तरह से अचिह्नित लगभग 6 सेमी लंबी तारकीय सुई का उपयोग करते हैं। मौजूदा अचिह्नित सुई वर्तमान में सेंट्रल लाइन सेट में उपलब्ध है।

डाक्टर तन्मय घटक: एसोसिएट प्रोफेसर, आपातकालीन चिकित्सा विभाग, प्रोफेसर आरके सिंह एचओडी आपातकालीन चिकित्सा विभाग और प्रोफेसर ए के बैरोनिया, पूर्व विभागाध्यक्ष, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग एसजीपीजीआई) ने प्रस्ताव रखा और निडिल पर 0.5 सेमी की दूरी पर इंडेंटेशन बनाया। प्रत्येक 0.5 सेमी को एकल अंकन के साथ चिह्नित किया गया है। प्रत्येक एक सेंटीमीटर को डबल मार्किंग के रूप में चिह्नित किया जाता है। जिससे यह पता लगाने में आसानी होती है कि निडिल सही जगह जा रही है या गलत।

आंखों या मुंह में सूखापन परेशान कर रहा है तो सतर्क हो जाएं

लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लीनिक इम्यूनोलॉजी एंड रिम्यूटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. पुनीत कुमार ने कहा कि थोड़ा सा चलने या शारीरिक श्रम करने पर थकान महसूस हो। जोड़ों में दर्द। आंखों या मुंह में सूखापन परेशान कर रहा है तो इन लक्षणों को कतई नजरअंदाज न करें। यह ऑटोइम्यून संबंधी गंभीर बीमारी है। डॉ. पुनीत कुमार बुधवार को क्लीनिक इम्यूनोलॉजी एंड रिम्यूटोलॉजी विभाग के प्रेक्षाग्रह में शोग्रेन्स सिंड्रोम डे पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डॉ. पुनीत कुमार ने कहा कि शोग्रेन्स सिंड्रोम प्रभावित अगला मरीज में लार व आंसू बनाने वाली ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर लेख हैं। नतीजतन मरीज का हमेशा मुंह सूखा महसूस होता है। आंखों में सूखापन लगता है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली होती है। आंखों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि मरीज को थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए।

एलएमए व टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय के बीच एमओयू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ मैनेजमेण्ट एसोसिएशन व टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय, के बीच बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर कपिल मिश्रा, वाइस चांसलर डॉ. प्रशांत त्रिवेदी, डीन डॉ. हेमेन्द्र शर्मा सहित अन्य शिक्षकगण तथा एसोसिएशन की ओर से सचिव राहुल दत्त, ट्रेज़रार राजीव प्रधान एवं जनरल मैनेजर रेनू चौधरी, मौजूद थे।

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक उल्लेखनीय पहल में टीएस मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस ने लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन (एलएमए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से एक ऐसा वातावरण स्थापित होगा जहाँ छात्रों के विचारों को पंख लग सकें । उन्हें उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और समर्थन से लैस करना है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय तथा एलएमए के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। यह विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख अनुसंधान और नवाचार-संचालित निजी विश्वविद्यालय है, जो लखनऊ में एक अत्याधुनिक उच्च तकनीक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों की सहयोग से ऐसी पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना है जो वर्तमान उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप हो। छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं लाइव कार्यक्रमों में भी शामिल कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि समझौता ज्ञापन सभी के विकास का समर्थन करते हुए परियोजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

उप्र राजकीय आयुर्वेद नर्सेज संघ का चुनाव 27 जुलाई को

लखनऊ। उप्र राजकीय आयुर्वेद नर्सेज संघ का चुनाव 27 जुलाई को टूड़ियागंज अस्पताल परिसर में होगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य एवं चुनाव अधिकारी डॉ. माखनलाल ने बताया कि 26 जुलाई को नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव होगा। इस चुनाव में प्रदेश भर से आयुर्वेद नर्स हिस्सा लेंगी।

नौबस्ता में सीएमओ की टीम ने 168 घरों का किया सर्वे, तीन डायरिया के मरीज मिले

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के निर्देशानुसार नग.सामु.स्वा.केन्द्र अलीगंज की चिकित्सीय टीम द्वारा बुधवार को नौबस्ता क्षेत्र में 168 घरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे के दौरान 3 हल्के डायरिया के रोगी मिले। जिन्हें ओआरएस पैकेट एवं जिंक टैबलेट देकर उपचार प्रदान किया गया। इससे पूर्व 22 जुलाई को फैजुल्लागंज के नौबस्ता क्षेत्र में वाटर सप्लाई में गंदे पानी और बीमारी फैलने की सूचना प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार जनपदीय टीम एवं नग.सामु.स्वा.केन्द्र अलीगंज, लखनऊ की चिकित्सीय टीम द्वारा 275 घरों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 2 हल्के डायरिया के रोगी पाये गये। क्षेत्र में कैम्प लगाकर क्षेत्र वासियो कों चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से भी जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। क्षेत्र में जलकल विभाग द्वारा शुद्धपेय जल की आपूर्ति हेतु पानी के टैकर उपलब्ध करा दिये गये है।

'अंतरा' बनी महिलाओं की पहली पसंद

● **राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13.60 लाख महिलाओं ने अपनाया अंतरा**

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन 'अंतरा' को अपनाकर दम्पति खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिसका नतीजा है कि पिछले चार सालों से अंतरा इंजेक्शन का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13.60 लाख महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन अपनाया है।

जबकि 2022-23 में 9.65 लाख महिलाओं नें अंतरा का चुनाव किया। 2021-22 में छह लाख महिलाओं ने इसे लगवाया। वहीं वर्ष 2020-21 में 3.40 लाख महिलाओं ने अंतरा अपनाया। महाप्रबंधक, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डा. सूर्यांशु ओझा बताते हैं कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार लाने को गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा को महिलाओं ने विकल्प के रूप में चुना है। अंतरा इंजेक्शन अनचाहे गर्भ को रोकने और दो बच्चों के बीच अंतर रखने का सुरक्षित और प्रभावी अस्थायी गर्भनिरोधक विकल्प है। तीन माह के अंतराल पर लगने वाला यह इंजेक्शन जिला महिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उपकेन्द्रों पर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का सीधे तौर पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण से गहरा सम्बन्ध है। यह दंपति के गुणवत्तापरक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए त्रैमासिक गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा बेहतर विकल्प है। इसकी पहली डोज़ चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) या प्रशिक्षित एएनएम द्वारा लाभार्थी की स्क्रीनिंग के बाद ही लगाई जाती है।

यह कहते हैं लाभार्थी

सआदतगंज के रुस्तमनगर की 35 वर्षीय निशा बताती हैं कि वह पांच सालों से हर तीन महीने के अंतराल में अब तक बीस अंतरा गर्भनिरोधक लगवा चुकी हैं। पहली बार अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर बहुत झिझक थी पर रोज़ गर्भनिरोधक गोली खाने से बेहतर तीन माह पर इंजेक्शन की सुविधा ज्यादा बेहतर लगी। तब से डफरिन अस्पताल में जाकर हर तीसरे महीने इसे लगवा रही हूँ और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यह इंजेक्शन लगवाना आसान और सुरक्षित है।

प्रोत्साहन राशि भी मिलती है

अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर प्रत्येक लाभार्थी महिला को हर तीन महीने पर 100 रुपए प्रति डोज दिए जाते हैं। साथ ही अंतरा गर्भनिरोधक से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 के जरिए ली जा सकती है।

12075.69 लाख करोड़ की 30 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

प्रयागराज महाकुंभ

● मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की दशम बैठक में लिए गए अहम निर्णय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 की शीर्ष समिति की दशम बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी महाकुंभ-2025 क्लीन और ग्रीन होना चाहिये। मेला क्षेत्र में स्थापित शौचालय साफ होने चाहिये। शौचालयों की प्रतिदिन सफाई हो रही है या नहीं, यह सुनिश्चित कराने के लिये थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाये। दूषित जल गंगा जी में प्रवाहित नहीं होना चाहिये। शत-प्रतिशत घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि शहर के परिदृश्य को नया रूप देने के लिए भित्ति चित्र, साइनेज, जंक्शन डिजाइन, सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना आदि का कार्य महाकुम्भ से पूर्व कराना सुनिश्चित किया जाये। बागवानी के माध्यम से भी सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जायें, इससे शहर की सुंदरता और बढ़ जाएगी। वहां पर स्थापित होने वाले शौचालयों को साफ-सुथरा रखा जाए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। प्लान कर सुरक्षा एवं यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। बैठक में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की 2584.12 लाख रुपये लागत की 2 परियोजनाओं, स्वास्थ्य विभाग की 5823.02 लाख रुपये लागत की 19 परियोजनाओं, पर्यटन विभाग की 351 लाख रुपये लागत की 1 परियोजना, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 789.34 लाख रुपये लागत की 1 परियोजना, उद्यान विभाग की 755.18 रुपये लागत की 3 परियोजनाओं, सीएण्डडीएस की 1249.79 लाख रुपये लागत की 2 परियोजनाओं, उप्र जल निगम की 523.24 करोड़ रुपये लागत की 1 परियोजना व सिंचाई विभाग की एक परियोजना इस प्रकार कुल 12075.69 लाख रुपये लागत की 30 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। महाकुम्भ में आने श्रद्धालुओं को को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 2247.52 लाख रुपये की लागत से मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हेल्थ प्लान के तहत 336.60 लाख रुपये की लागत से चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों का क्रय किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1425.02 लाख रुपये की लागत से अस्थाई सेण्ट्रल हॉस्पिटल्स, 10 सेक्टर हॉस्पिटल्स और 2 सब सेक्टर हॉस्पिटल का निर्माण मेला क्षेत्र में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में 21.24 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूनिटी हेल्थ सेण्टरों व प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों के जीर्णोद्धार तथा महाकुंभ मेला क्षेत्र के समीप वेयरहाउस तेलियरगंज का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

इसी प्रकार महाकुम्भ के अवसर पर आने वाले विदेशी पर्यटकों एवं वीआईपी अतिथिगणों आदि को सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 351 लाख रुपये की लागत से मेला क्षेत्र के परेड ग्राउण्ड में 55 प्रीमियम टेण्ट लगाये जायेंगे। आईईआरटी पुलिया (पीपल के पेड़ के पास) से गंगा नदी तट तक सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य 789.34 लाख रुपये की लागत से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा।

साधारण मिट्टी के खनन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 माह और परमिट 6 माह तक होगा मान्य

● बिना परमिट खनन को माना जाएगा अवैध खनन, सुसंगत धाराओं में होगी कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है। इसके अनुसार, 100 घन मीटर मिट्टी के खनन एवं परिवहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 माह तक, जबकि 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए परमिट 6 माह तक वैलिड होगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस शासनादेश की प्रतिलिपि समस्त विधानसभा सदस्यों एवं विधान परिषद सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में तहसील व थाने के कर्मियों से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया था।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में 2020 का जीओ भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ ही साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूरा विवरण और परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार एवं अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। इसके लिए अलग से ईएमएम की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो महीने या मात्रा की निकासी पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए मान्य होगा। गलत जानकारी देने पर पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है।

100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से परमिट लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसमें भी नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, क्षेत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच के बाद स्वीकृति या अस्वीकृत संबंधी सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। परमिट भी ऑनलाइन ही निर्गत किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 7 दिन के अंदर यह कार्यवाही की जाएगी। परमिट लेटर जारी होने के बाद साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए ईएमएम 11 जेनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। परमिट की अवधि अधिकतम 6 माह होगी, जो स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पार्क का अवैध कब्जा हटाने के लिए दें पुलिस फोर्सः हाईकोर्ट

● एल्डिको उद्यान टू के पार्क पर अवैध कब्जे का मामला

विधि संवाददाता। लखनऊ

रायबरेली रोड स्थित एल्डिको उद्यान टू के एक पार्क पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने जिलाधिकारी व सम्बंधित पुलिस अधिकारी को आदेश दिया है कि वो नगर आयुक्त व नगर निगम के उद्यान अधीक्षक को पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मुहैया कराएं। ताकि वो उक्त अवैध कब्जे को हटाने के लिए यथोचित कार्रवाई कर सकें। पीठ ने इसके साथ ही नगर आयुक्त और उद्यान अधीक्षक को छह हफ्ते में कार्रवाई का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवम जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूरे पार्क पर अवैध निर्माण कर अवधेश प्रताप सिंह व उसकी पत्नी ने कब्जा कर लिया है। वो पार्क के गेट पर ताला लगाकर रखते हैं और अपनी सुविधानुसार ही उसे खोलते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त पार्क में बच्चों तक को खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त और उद्यान अधीक्षक की ओर से वकील अमित कुमार द्विवेदी पेश हुए। उनका कहना था कि उक्त अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। पीठ ने इस पर उपरोक्त आदेश पारित किया।

वृक्षारोपण महाभियान के दौरान रोपित एक भी पौधा सूखना नहीं चाहिएः डॉ. अरुण कुमार सक्सेना

लखनऊ। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरूण कुमार सक्सेना ने दिनांक 20 जुलाई को रोपित हुए 36.50 करोड़ से अधिक पौधों के स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपर्याप्त वर्षा के कारण पौधों की सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही रोपण स्थलों की सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया जाये। विभागीय अधिकारी रोपित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करते रहें। डॉ. सक्सेना बुधवार को वन विभाग के मुख्यालय स्थित पारिजात हॉल में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाभियान के दौरान रोपित पौधे हर हाल में जीवित रखे जाने चाहिए। यदि कोई पौधा सूखता है तो उसके स्थान पर दूसरे पौधे का रोपण कराया जाये। सड़कों के किनारे जो पौधे रोपित हुए हैं उनकी सुरक्षा और सिंचाई का नियमित प्रबंध होना चाहिए।

डिजिटल ज्ञान आने वाले समय के लिए अपरिहार्यः राजेश्वर सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

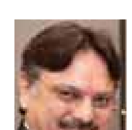

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बुधवार को चौक स्थित खुन खुन जी गर्ल्स पी जी कॉलेज में सीएसआर फण्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। साथ ही पूर्व में स्थापित कराये गये तारा शक्ति केंद्र (सिलाई सेंटर) का अवलोकन किया। विधायक ने कॉलेज की 5 मेधावी छात्राओं- अंचल पटेल , शिवानी द्विवेदी, फरहत शरिन , सरित साहू एवं भूमि सक्सेना को लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित भी किया। साथ ही पराग चौराहा, आशियाना स्थित कार्यालय पर सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के 20 मेधावी छात्र - छात्राओं

महाविद्यालय की उन्नत व्यवस्थाओं को देखकर बेटियों के उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बेटियों को डिजिटल शिक्षा तथा उत्तम स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध कराने के संकल्प क्रम में महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास पैनल और ओपेन एयर जिम स्थापित कराने हेतु आश्वस्त किया। डिजिटल शिक्षा का महत्व बताते हुए डॉ. राजेश्वर सिंह के कहा कि डिजिटल ज्ञान आने वाले समय के लिए अपरिहार्य है, भविष्य में ऑफिस पेपरलेस होंगे, नौकरियां ऑनलाइन होंगी, इसी लक्ष्य के अनुरूप सरोजनीनगर में 25 कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी, 10 कॉलेज में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये गए। डॉ. सिंह ने जोड़ा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कंपीटिशन अब लोकल न रह कर ग्लोबल हो गया है, यूपी के सीएम योगी अदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल शिक्षा को बढावा देने के लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सोनभद्र के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि सोनभद्र में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी गयी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आईयूसीएन के डायरेक्टर टिम बैडमैन के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया जा रहा है। उनके सुझावों को धरातल पर उतारने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। सोनभद्र स्थित सलखन जीवाश्म पार्क 1400 मिलियन वर्ष पुराना है। अमेरिका के एलोस्टोन पार्क को अब तक विश्व का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क माना जाता है। टिम इस समय दिल्ली में चल रही 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करता है। 1948 में स्थापित आईयूसीएन प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण बन गया है। जयवीर सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रकृति संरक्षण पर अधिक प्रतिनिधित्व और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। समिति विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए संभावित स्थलों पर विचार-विमर्श करेगी।

अल्पसंख्यक कांग्रेस ने फल के ठेलों पर लगाया संविधान की प्रस्तावना का फोटो

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अल्पसंख्यक कांग्रेस ने लखनऊ के चौक रोड और टेढ़ी पुलिया पर फल विक्रेताओं के ठेलों पर संविधान की प्रस्तावना की फोटो लगाकर देश की एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। अल्पसंख्यक विभाग का यह प्रदेश व्यापी अभियान है।

अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने कहा कि योगी सरकार का फल के ठेले वालों से धार्मिक पहचान उजागर करने का आदेश संविधान विरोधी था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यह संविधान के सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला फैसला था। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या भाजपा को उन्हें हटा देना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने संविधान विरोधी होने के कारण उन्हें नहीं हटाया। इस कार्यक्रम में लखनऊ शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ शहज़ाद आलम, अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शमीम खान, अल्पसंख्यक कांग्रेस शहर अध्यक्ष शावेज़ अहमद, जिला अध्यक्ष ज़ुबैर खान, अजय वर्मा, नोमान, मनीष जायसवाल, प्रमोद दुबे, सुरेंद्र सक्सेना, डॉ. मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नईम, तौकीर अहमद समीर खान, मोहम्मद शान गनी, काशिफ सिद्दीकी. शमशेर मलिक आरिफ मिज्जन, अल्ताफ, उस्मान आदि मौजूद रहे।

व्यापारी नेता संदीप बंसल का किया गया स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अलीगंज स्थित एक कैफे में आयोजित समारोह में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का स्वागत किया गया। इस मौके पर निशा अग्रवाल ने बंसल को पुष्प गुच्छ देकर भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। समारोह में मुख्य तौर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, संगठन मंत्री जावेद, महामंत्री कक्कड़, उपाध्यक्ष सुबोध निगम, कोषाध्यक्ष नीरज वर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे।

यूपी का पचास हजार का ईनामी अपराधी पंजाब से गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने यूपी के पचास हजार के ईनामी अपराधी रमेश यादव को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। गोरखपुर के बेलाघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला रमेश यादव मऊ जिले से वांछित चल रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ को ज्ञात हुआ कि 19 दिसंबर 2016 को मेसर्स किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) काठतरॉव थाना मधुबन जनपद मऊ का कर्मी प्रमोद कुमार पेट्रोल पम्प का पैसा जमा करने के लिए बैंक जा रहा था। इसी दौरान थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत बॉस तराव प्राइमरी स्कूल के पास बदमाशों द्वारा पिस्टल की दिखाकर सनसनीखेज तरीके से दिन-दहाड़े लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना मधुबन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में स्थानीय पुलिस की विवेचना में कुख्यात लुटेरा रमेश यादव एवं उसके साथी विनोद चौबे का नाम प्रकाश में आया था। अभियुक्त विनोद चौबे की गिरफ्तारी हो जाने के उपरान्त से ही रमेश यादव लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पचास हजार रुपए का ईनाम घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रमेश यादव ने बताया कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गोरखपुर, मऊ, देवरिया एवं आजमगढ में ताबडतोड़ लूट की कई घटनाओं सहित मादक पदार्थों आदि की तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मेहरवान, लुधियान में दाखिल कर न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अंतरराज्यीय गिरोह के दो असलहा तस्कर पारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार

लखनऊ। एसटीएफ ने अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को लखनऊ कमिश्नरेट के पारा थानान्तर्गत लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से .32 बोर की आठ पिस्टल, 14 मैग्जीन और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मनीष गुप्ता निवासी भैरवपुर, थाना-अकबरपुर, अम्बेडकरनगर औन शैलेन्द्र शमा निवासी सीपी कालोनी, जनपद मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश शामिल है। अभियुक्त मनीष ने पूछताछ में बताया कि कादीपुर (सुलतानपुर) निवासी प्रमोद श्रीवास्तव उर्फ गुरुजी उसके बड़े भाई के दोस्त हैं। जो मध्य प्रदेश से असलहा तस्करी करता था। लगभग 4 वर्ष पूर्व उसने ही इसकी मुलाकात मप्र के असलहा तस्करों से कराया था। तभी से यह भी अवैध असलहे की तस्करी में लिप्त है। मध्य प्रदेश के खण्डवा, खरगौन व बुरहानपुर में अवैध असलहे बनते है, जहाँ से विभिन्न प्रदेशो में सप्लाई होती है। यह पिस्टल की क्वालिटी के हिसाब से लगभग 10-15 हजार रुपए में मध्य प्रदेश से पिस्टल खरीदकर 20-25 हजार में सप्लाई करता है।

व्यापार मंडल पदाधिकारियों संग बैठक कर जानीं समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह के साथ लखनऊ व्यापार मण्डल कार्यालय में बुधवार को व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से शिष्टाचार भेंट एवं परिचय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्ष लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र और संचालन वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने किया। सहायक आयुक्त ने व्यापारियों को जागरूक करते हुए कहा कि बिल पक्का ही लेना चाहिए। खाद्य से जुड़े व्यापारियों ने अपनी-अपनी समस्या बताई। जिसमें फूड लाइसेन्स पंजीकरण एवं रिजीवल में आ रही दिक्कतों को अवगत कराया। ऑनलाइन प्रक्रिया और सरल होनी चाहिए। पंजीकरण नंम्बर जनरेट करने का समय अवधि 15 दिवस से घटाकर 7 दिवस की जाए। अलग-अलग स्थान के लिए अलग-अलग पंजीयन लेना पड़ता है, जिसको जीएसटी की भांति एक ही पंजीकरण नम्बर पर गोदाम दुकान को जोड़ने की सुविधा होनी चाहिए। जिससे व्यापारी को बिल पर अलग अलग नम्बर नहीं डालना पड़ेगा। पवन मनोचा ने कहा कि व्यापार मण्डल सदैव सर्वे छापे का विरोध नहीं किया है परन्तु अधिकारियों के उत्पीड़न का विरोध किया है।

प्लॉटिंग साइटों पर धड़ल्ले से खड़े हो रहे पोल, मूकदर्शक बने अफसर

● प्लॉट बेचने के लिए मनमाने तौर पर पोल खड़े कर रहे कई प्रॉपर्टी डीलर

संवाददाता। मोहनलालगंज

लोगों को जल्द प्लॉट बेचने के लालच में राजधानी के मोहनलालगंज तहसील में कई प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग साइटों पर मनमाने ढंग से पोल खड़े कर रहे हैं। जिसके जरिए रियल एस्टेट कारोबारी खरीदारों को जल्द बिजली पहुंचाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। जबकि मोटी कीमत चुकाकर प्लॉट खरीदने के बावजूद भी खरीदारों को बाद में बिजली कनेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग के अफसर ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई करने में हाथ खड़े कर रहे हैं। राजधानी में आशियाना बनाने की चाहत में गैर जिलों के लोग मोहनलालगंज तहसील में प्रॉपर्टी डीलरों से प्लॉट खरीद रहे हैं। प्लॉट बेचने के लिए प्राइवेट डेवलपर खरीदारों को रोड बिजली और पानी निकासी की सुविधा देने का भरोसा दे रहे हैं। जिसके लिए डेवलपर बाजार से पोल खरीदकर प्लॉटिंग साइटों पर मनमाने तौर पर पोल खड़े कर लोगों को जल्द बिजली पहुंचाने का खोखला भरोसा भी दे रहे हैं। लेकिन विद्युत विभाग से लोड सैंक्शन नही कराए जाने से प्लॉट खरीदने के कुछ माह बाद ही लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता है। विभाग जहां बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लागत जमा करने की बात कहता है। वहीं डेवलपर बिजली के लिए इंतजार करने की तारीख बढ़ाता जाता है। इस सबके बीच प्लॉट खरीदार और उसका परिवार खुद को ठगा सा महसूस करता है। मोहनलालगंज तहसील के गोसाईगंज समेसी पूरनपुर अमेठी निगोहा और मोहनलालगंज क्षेत्र में इन दिनों लोड सैंक्शन कराए बिना अधिकांश प्लॉटिंग साइटों पर धडल्ले से पोल खड़े कर लोगों को गुमराह करने का धंधा फल फूल रहा है। लेकिन विभाग नियमों में कार्रवाई का प्राविधान न होने की बात कहकर सबकुछ देखकर भी मूकदर्शक बना हुआ है। लिहाजा भोले भाले लोग प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गवां रहे हैं।

यह कहते हैं अधिकारीः अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने बताया लोड सैंक्शन कराए बिना प्लॉटिंग साइट पर पोल खड़े करना नैतिक रूप से सही नही कहा जा सकता है। इस तरह लोग गुमराह होते हैं। इससे बचने के लिए लोगों को विभाग से पूरी जानकारी करनी चाहिए। हालांकि विभाग के सिस्टम से जुड़े नही होने की वजह से प्लॉटर के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का प्राविधान नही है।

छात्र का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

मोहनलालगंज। आठवीं के छात्र का अवैध असलहा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की भनक लगते ही पुलिस ने छात्र से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी किशोर महिला ग्राम प्रधान का बेटा बताया जा रहा है। मोहनलालगंज के एक गांव की महिला ग्राम प्रधान के नाबालिग बेटे का एक वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में किशोर हाथ में असलहा लिए नजर आ रहा है।

हालांकि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नही हो सकी है। उधर सोशल मीडिया के जरिए मामले की भनक लगते ही पुलिस ने फौरन गांव पहुंचकर किशोर से पूछताछ शुरू कर दी है। एसएचओ आलोक राव ने बताया वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। यदि वीडियो सही पाया गया तो नाबालिग को असलहा किसने दिया इस बारे में भी पड़ताल कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

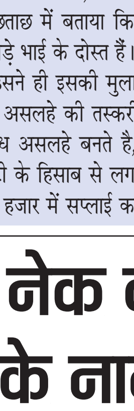

कारगिल विजय दिवस रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेंद्र नगर, लखनऊ की 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी विंग द्वारा महाविद्यालय सभागार में याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान हेलीकॉप्टर यूनिट से जवानों को ऊंची चोटियों तक पहुंचाने तथा रसद की आपूर्ति बहाल रखने में अहम भूमिका निभाने वाले आर्मी एविएशन के कर्नल जीपीएस कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो मंजुला उपाध्याय ने की तथा संयोजन व संचालन एनसीसी अधिकारी मेजर (डॉ.) मनमीत कौर सोढी ने किया। 19 बटालियन से सूबेदार मेजर ताजबर सिंह , सूबेदार दीपेंद्र राई, बीएचएम संदीप, हवलदार दीपक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि, प्राचार्य एवं एनसीसी अधिकारी द्वारा कारगिल युद्ध के शहीदों के चित्र पर सैनिक सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित करके हुआ। इस अवसर पर कैडेट साक्षी सोनकर, एवं जिया थापा ने देशभक्ति पर आधारित एकल नृत्य प्रस्तुत किए ह्न एक बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करते हुए कैडेट पूजा गौतम, जुल्फी राजपूत, महिमा, बुशरा हामिद, खुशी सिंह, जिया , प्रिया सिंह, सरिका , प्रज्ञा , वैष्णवी,तनु, पूर्णिमा ,ज्योति गौतम ने देशभक्ति पर आधारित पिरामिड नृत्य की जोश पूर्ण प्रस्तुति दी। कैडेट अंजलि वाजपेई ने कारगिल युद्ध का वर्णन एक कविता के माध्यम से किया। कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कठिन परिस्थितियों में अत्यंत बहादुर के साथ थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने साहस का परिचय दिया ह्न यह युद्ध आसान नहीं था। क्योंकि दुनिया के सबसे उंचे रण क्षेत्र में लड़ा गया। कर्नल कौशिक और उनकी टीम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को रणभूमि के उसे हिस्से तक पहुंचाया, जहां से युद्ध की पूरी प्लानिंग की गई। अपने चीता हेलीकॉप्टर से आयुध और रसद की आपूर्ति बहाल रखने में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई।

उन्नत किस्मों की पहचान कर किया जा रहा मानकीकरणः डॉ. संजय सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) द्वारा बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिसमें महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियो को परिषद की हालिया उपलब्धियों और आगामी रणनितियों पर प्रकाश डाला। डॉ. सिंह ने विश्व बैंक पोषित सोडिक लैण्ड परियोजना और कृषि विविधीकरण परियोजना के प्रभावी परिणामों का उल्लेख किया, जो उपकार के माध्यम से संचालित की गई थीं। उन्होंने बाह्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित आत्मा परियोजना, मैक्रोमोड परियोजना और आर.के.वी.वाई. की गतिविधियों पर भी चर्चा की। राज्य औद्यानिक मिशन परियोजनाओं के संचालन में उपकार के योगदान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद की स्थापना जून 1989 में द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत की गई थी। अनुसंधान के क्षेत्र में उपकार द्वारा किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर क्षेत्र विशेष की शोध प्राथमिकताओं पर परियोजनाओं का सतत वित्त पोषण किया जा रहा है। उन्होंने काला नमक चावल की दो नवीन प्रजातियों का विकास और विभिन्न कृषि यंत्रों के विकास की जानकारी दी, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के सहयोग से किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में 18 गुना बढ़ा रेलवे का बजटः रेलमंत्री

- पीएम मोदी के कार्यकाल में हुई बढ़ोतरी
- महाकुंभ पर बड़ी संख्या में चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें
- यूपी में पिछले दस सालों में 4900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए
- यूपी के सभी रेलवे ट्रैकों का सौ फीसदी हो चुका है विद्युतीकरण
- 157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में किया जाएगा विकसित

संवाददाता। प्रयागराज

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल 92 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यूपीए के कार्यकाल 2009 से 2014 में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 1109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 19 हजार 848 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले दस सालों में 4900 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं जो कि पूरे स्विटजरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे ट्रैकों का सौ फीसदी विद्युतीकरण हो चुका हैं। केंद्रीय रेलमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में 1490 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण हुआ है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन सुगम हुआ है और एक्सीडेंटस की संख्या कम हुई है।

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुंभ सुगम रूप से चले और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए चालीस से भी अधिक प्रोजेक्टस को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट कई फेस में होगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। कहीं कोई कमी न रहें इसके लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जा रहा है।

अधिक से अधिक ट्रेन चलाने की योजनाः जीएम एनसीआर

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने बुधवार को पत्रकारों से आगामी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने मीडिया को बताया कि महाकुंभ को लेकर उत्तर मध्य रेलवे प्रदेश की योगी सरकार के साथ मिलाकर बेहतर से बेहतर योजना बना रहा है। महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार से रेलवे को भारी बजट भी आवंटित किया है। दो लाख 62 हजार करोड़ रुपए बजट दिया गया है। कुम्भ के लिए 750 करोड़ रुपए पहले ही दिया जा चुका है। अगर और भी जरूरत होगी तो बजट को बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेशन को डेवलप करने के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। जहां भी कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कार्य रणनीति के आधार पर किए जा रहे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मौनी अमावस्या में आने वाली भीड़ को लेकर जीएम एनसीआर उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। मौनी को देखते हुए लोगों की सुरक्षा और संरक्षा दोनों पर ख्याल रखा जाएगा। 2019 के कुंभ में 600 ट्रेन चलाई गई थी इस बार और अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बार केंद्र सरकार ने रेलवे को पर्याप्त बजट आवंटित किया है। इसके आधार पर रेलवे महाकुंभ को लेकर अच्छी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से कार्य हो चुके हैं और भी कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

राज्यमंत्री ने 1001 पौधरोपण अभियान का किया शुभारंभ, अधिकारियों ने लगाए पौधे

- एक पेड़ मां के नाम वाले सपने को साकार करने का लिया संकल्प

संवाददाता सोनभद्र

प्रकृति के दोहन से जलवायु में लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। इसके प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होते जा रही है, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है।

ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारा एक पेड़ मां के नाम वाले सपने को साकार करते हुए धरातल पर हम सबको उतरना है। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड ने एमईआई एल अनपरा पावर के तहत कार्य करने वाली कंपनी साई सूर्या प्रोफेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बेलवादह ऐश डाइक के पास 1001 वृक्ष लगाने के अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया था। जिसकी शुरुआत फीता काटकर मंत्री द्वारा किया गया।

अतिथि का स्वागत कंपनी के कृष्णा नारा सत्यम, वेंकटेश के द्वारा अंग वस्त्र फूल माला के साथ नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों के द्वारा पुष्प से किया गया। स्वागत के बाद मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ एक पेड़ मां के नाम के तर्ज पर नगर वासियों से अपने-अपने घरों के आसपास कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील की। साई सूर्या कंपनी के एमडी रविंद्र बाबू नारा के निर्देशन में कृष्णा नारा के संयोजन में पिपरी गांव के आदिवासी बनवासियों के बच्चों को पठन-पाठन साइकिल का भी वितरण किया गया। उनका कहना है सोशल वेलफेयर के तहत गांव के बच्चों को चयन कर आर्थिक सहायता, साइकिल भी दिया जाएगा। गरीब बच्चों के उत्थान के लिए अतिरिक्त राशि एसएसपीएस के द्वारा दिया जा रहा है। ग्रामीण के जीवन स्तर को उठाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर एमईआईएल पावर अनपरा के उप महा प्रबंधक सुधीर श्रीवास्तव, डिप्टी मैनेजर सच्चिदानंद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलड़ोमरी वालकेश्वर सिंह, सत्यम वेंकटेश, मनीष सूद धर्मेंद्र सिंह ,ओमप्रकाश शर्मा ,अंकुश जायसवाल के साथ ही अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

एक समान आरोप और सबूत तो आपराधिक कार्यवाही के साथ नहीं चल सकती विभागीय कार्यवाही

- कोर्ट ने लगाई विभागीय कार्यवाही पर रोक, किया जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद अदालत में जानलेवा हमले के आरोपी बंदी नौशाद के फरार होने के मामले में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक केस और विभागीय कार्यवाही एक साथ चलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

पीठासीन अधिकारी सहायक पुलिस कमिश्नर वेब सिटी गाजियाबाद के आदेश पर याची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही थी।साथ ही आपराधिक केस भी कायम किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने शहनवाज की याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है। याची का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने एम पाल एंथोनी केस में कहा है कि तथ्य व सबूत आपराधिक व विभागीय कार्यवाही में एक व समान हो तो विभागीय कार्यवाही नहीं चलेगी। हालांकि आपराधिक व विभागीय कार्यवाही एक साथ चल सकती है बशर्ते तथ्य व साक्ष्य एक व समान न हो।

इसके आधार पर याची ने विभागीय कार्यवाही को रोकने की मांग की है। क्योंकि एक ही तथ्य व सबूतों पर दोनों केसों में आरोप साबित किया जायेगा। याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और विभागीय कार्यवाही में अप्रैल 24 में चार्जशीट दी गई है। दोनों में आरोप एक ही है। याची पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा हेतु भारतीय नौसेना एवं तटीय देशों की होगी विशेष भूमिकाः विकास कुमार

संवाददाता। गाज़ीपुर

जनपद के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व शोध प्रबंध प्रस्तुत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी महाविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ तथा विभागीय शोध समिति के तत्वावधान में सेमिनार हाल में सम्पन्न हुई जिसमें, महाविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी व छात्र - छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

संगोष्ठी में कला संकाय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी विकास कुमार ने अपने शोध शीर्षक शीत युद्ध के पश्चात् हिन्द महासागर में महाशक्तियों की स्थिति एवं भारत की सुरक्षा नीति नामक विषय पर अपना शोध प्रबंध व उसकी विषय- वस्तु प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान में हिन्द महासागर क्षेत्र विश्व का ऐसा क्षेत्र है जो अस्थिर और अशांत है। राजनीतिक हलचल और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता इस क्षेत्र की मूल विशेषता है। नौसैनिक महत्व विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र तनाव, संघर्ष एवं टकराव का केंद्र बन गया है। अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए महाशक्तियां विशेषकर अमेरिका, रूस, चीन व फ्रांस अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। हिन्द महासागर भारत के लिए केन्द्रीय महत्व का बिन्दु है।

इस महासागर की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियां प्रारम्भिक काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी है। हिन्द महासागर में भारत के लगभग 1152 द्वीप है, जिनकी सुरक्षा और विकास का दायित्व भारत पर ही है।

इसके अतिरिक्त भारत का 98 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिन्द महासागर से ही होता है। पूर्व की ही भांति आगे के वर्षो में भी हिन्द महासागर जल क्षेत्र भारतीय विकास व प्रतिष्ठा का मुख्य आधार बना रहेगा। भारत को आगे विकास व सुरक्षा के लिए हिन्द महासागर जल क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि भारत के आर्थिक विकास तथा सुरक्षा में हिन्द महासागरीय संसाधनों तथा परिवहन माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अत: यह स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी में भारतीय सुरक्षा व विकास मुख्य रूप से हिन्द महासागर पर निर्भर करेगा।

ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना की विशेष भूमिका होगी ताकि शांन्ति व संकट दोनों के समय में भारतीय हितों की सुरक्षा कर सकें तथा इसके साथ ही भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय देशों (सार्क, आसियान, हिमतक्षेस) के साथ सहयोग और अधिक बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि इसी से इस क्षेत्र में बाह्य शक्तियों की भूमिका को सीमित व समाप्त किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जा सकता है।

क्योंकि हमारी सशक्त निगरानी एवं नौसेना ताकत ही हमें हिन्द महासागर की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाएगी। प्रस्तुतीकरण के बाद विभागीय शोध समिति, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ व प्राध्यापकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिनका शोधार्थी विकास कुमार ने संतुष्टिपूर्ण एवं उचित उत्तर दिया।

क्विक न्यूज

रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक हुई सम्पन्न

सोनभद्र। बुद्धवार को सोनभद्र रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक सम्मान हुई। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक राममनी सरस्वत व मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मिर्जापुर पूर्व राजेश प्रसाद के नेतृत्व में स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ स्टेशन पर हो रहे नव निर्माण व विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यों का जायजा लिया गया, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य राकेश मेहता, यादवेन्द्र द्विवेदी, भाजपा नगर अध्यक्ष बलराम सोनी, रमेश पटेल, रजनीश रघुवंशी के साथ बैठक हुई,जिसमें कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हुई और सभी सदस्यों के सुझाव पर कार्यों के कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें स्टेशन के पुनर्विकास की गति धीमी होने पर सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा सलाह दिया गया की विकास कार्यों में तेजी लाया जाये ताकि कार्य समय से पूर्ण हो सके,और पूर्व में सचालित गाड़ी संख्या 53351/52 बरवाडीह चुनार बरवाडीह पैसेंजर को पुन: चलाये जाने की मांग किया गया,और गेट नम्बर 37 एसपीएल पन्नूगंज मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर सुन्दर फ्लाइ ओवर बनाने की मांग किया गया। रेलवे स्टेशन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत तथा उस पर आधुनिक स्ट्रीट लाईट लगाने की सलाह दिया गया, बैठक में मुख्य टिकट निरीक्षक संयोगिता शुक्ला, मख्य माल प्रवेक्षक नन्द कुमार गिरि, एसआई, आरपीएफ राहुल यादव, एसएसई वर्क अभिषेक कुमार, एस एसई पॉवर सप्लाई मार्कण्डेय सिंह उपस्थित रहे।

मंडलीय चिकित्सालय में पेन क्लीनिक की शुरुआत

मीरज़ापुर। मंडलीय चिकित्सालय में बुधवार को पेन क्लीनिक की शुरूआत की गई। इस आशय की जानकारी मेडिकल कालेज के प्राचार्य विश्वजीत दास ने दी। मंडलीय कालेज के प्राचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले में स्थिति मंडलीय चिकित्सालय के कमरा नं0 106 में पेन क्लीनिक की सुविधा उपलब्ध कराकर जनता को सौपने का कार्य किया गया। पेन क्लीनिक की सुविधा सप्ताह में दो दिन बुधवार व शनिवार को ही मिलेगी। बुधवार को डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता व शनिवार को डॉक्टर अनुराग पटेल को लगाया गया है। यह सुविधा हो जाने के बाद मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। अभी तक लोगों को दूसरे जनपदो की ओर जाना पड़ता था और उंचे दाम की दवाइयों को सेवन करना पड़ता था लेकिन अब यह सुविधा हो जाने से लोगों को यह सुविधा निशुल्क दिया जायेगा। नये प्राचार्य के आने के बाद कार्य में तेजी देखने को मिल रहा है और तरह-तरह के नये कार्यो को रोज देखने को मिल रहा है। जो एक सराहनीय कार्य है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन

मीरज़ापुर। आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में आज गुरूवार को 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर मंडली चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में आईसीयू एवं इमरजेंसी में व्याप्त दुर्व्यवस्थाए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का पर्याय कनिष्ठ लिपिक अमित कुमार सिंह का स्थानांतरण के बाद कार्य मुक्त न किए जाने, एवं फर्जी ढंग से संचालित पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड एवं चिकित्सालयों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उन्हें ज्ञापन पत्र सौपा जाएगा आम आदमी पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी नगर पदाधिकारी नगर अध्यक्ष विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष गण अपनी इकाइयों के साथ एवं विधानसभा ब्लाक के अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारी के साथ 25 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके इन समस्याओं की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा इसके बाद कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बंधु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर भी इन्हीं मांगो को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

स्कूल बस पलटी, शिक्षिका सहित आधा दर्जन बच्चे घायल

चन्दौली। बबुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगहरा गांव में बुधवार को स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। इस दौरान बस में सवार आधा दर्जन बच्चों समेत दो महिलाएं व चालक घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने किसी प्रकार घायलों को बस से बाहर निकाला । इसके उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना घटी है। वही दूसरी तरफ चकिया एसडीएम समेत अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल लेने में जुटे रहे । वहीं चालक और एक अध्यापिका की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बबुरी थाना क्षेत्र के कमहरिया स्थित आरबीएस स्कूल की बस बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ने जा रहीं थी । इस दौरान बस जैसे ही गोगहरा गांव के समीप बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान बस में सवार आधा दर्जन बच्चों समेत दो महिलाएं व बस चालक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने बच्चों और महिलाओं समेत चालक को गाड़ी से बाहर निकाला । इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक घायलों के उपचार में जुट गए है। वहीं मौके पर पहुंची चकिया एसडीएम दिव्य ओझा घायलों का हाल जानने में जुटी रही।

चन्दौली मझवार स्टेशन पर जल्द होगा कई प्रमुख ट्रेनों का ठहराव

चन्दौली। राज्य सभा सदस्य साधना सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय मण्डल के कई विषयों को उनके संज्ञान में दिया। दिन दयाल नगर स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के अलावा स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण की अपार संभावना के बारे में बताते हुए सांसद ने मंत्री से कोविड काल से पूर्व की भाँति ट्रेन के ठहराव व परिचालन को बहाल करने हेतु पत्र भी सौंपा द्य इसके अतिरिक्त सांसद ने रेल के ख़ाली पड़े भूखंड पर व्यवसायिक मार्केट काम्प्लेक्स के निर्माण का भी आग्रह किया ताकि परिसर की भव्यता भी बढ़े साथ साथ लोगों को नये व्यापारिक परिसर मिलने के अलावा रेल की आय में भी वृद्धि हो सके। सांसद ने मुग़लसराय और चंदौली को जोड़ने वाली पुरानी पुल के संबंध में भी आग्रह किया कि इसके अलावा एक नया पुल का भी प्रावधान किया जाये ताकि आवागमन में सहूलियत बढ़ सके द्य सांसद द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पुराना पुल है जो की सँकरा है और अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है द्य नये पुल के निर्माण से स्टेशन के सामने लगने वाले जाम की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी।

माध्यमिक शिक्षक डीआईओएस कार्यालय पर भरेंगे हुंकार, कराएंगे ताकत का एहसास

संवाददाता। गाज़ीपुर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दर्जनों विद्यालयों का दौरा कर शिक्षकों की समस्याओं को सुना। प्रांतीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के निदान को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रांतीय नेतृत्व के आहवान पर माध्यमिक शिक्षक संघ आगामी 25 जुलाई गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय महामंत्री ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की और कहाकि संगठन पुरानी पेंशन, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं सम्मानजनक मानदेय, अद्यतन तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण आदि मुददों की लड़ाई अंतिम चरण में है।

बताया पिछले प्रांतीय बैठक में 14 प्रस्ताव प्रारित हुए। इसमें पुरानी पेंशन की बहाली, वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, एक अप्रैल, 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर नौकरी पाये शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ आदि मांगें हैं। जिलाध्यक्ष शिवकुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक व संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की। पूर्व जिला मंत्री राणा प्रताप सिंह ने कहा कि यदि समस्याओं का एक माह के भीतर निराकरण नहीं होने पर चरण वार संघर्ष किया जाएगा।

भ्रमण करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय, जिलाध्यक्ष शिवकुमार सिंह, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य राणा प्रताप सिंह तथा संयुक्त मंत्री सूर्य प्रकाश राय ने इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज बारा, इंटर कॉलेज गहमर, एसकेबीएम इंटर कॉलेज दिलदारनगर, राधा कृष्ण गुप्ता आदर्श इंटर कॉलेज दिलदारनगर, इंटर कॉलेज अतरौली में सम्पर्क कर धरने में शामिल होने की अपील की।

फरार चल रही अभियुक्ता के घर पर की गई कुर्की

सोनभद्र। बुधवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट सोनभद्र द्वारा अभियुक्ता रीमा उर्फ शीला उर्फ ममता पत्नी रामचन्दर निवासी ग्राम नकबई सतौहा थाना घोरावल सोनभद्र, वर्तमान पता ग्राम बभनौली थाना रावर्ट्सगंज सोनभद्र के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 558/23 धारा 363, 370 आईपीसी थाना रावर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में जारी धारा 82 सीआरपीसी का तामिला अभियुक्ता के मूल निवास ग्राम नकबई सतौहा थाना घोरावल सोनभद्र, वर्तमान पता ग्राम बभनौली थाना रावर्ट्सगंज, कचहरी परिसर जनपद सोनभद्र धर्मशाला चौराहा व बढौली चौराहा व अन्य स्थानों पर न्यायालय के आदेश की कापी चस्पा की गई। अभियुक्ता रीमा उर्फ शीला उर्फ ममता पत्नी रामचंद्र मानव तस्करी से संबंधित मुकदमे में फरार है के घर पर नोटिस चस्पा करते समय पास पड़ोस के कई लोग मौजूद रहे। अभियुक्ता को न्यायालय में हाजिर होने के लिए मुनादी भी कराई गई।

जिलाधिकारी ने 7 लाभार्थियों को बांटे आटोमैटिक मोटोराइज्ड दोना मशीन

सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित नि:शुल्क टूल किट्स वितरण योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के 7 लाभार्थियों को आटोमैटिक मोटोराइज्ड दोना मशीन का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से वार्ता किया और मशीन के संचालन, दोना के बनाने के सामग्री आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें इस उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस आटोमैटिक मोटोराइज्ड के माध्यम से दोना बनाकर बाजारों में बेचा जाये, जिससे रोजगार से जुड़ते हुए आमदनी बढ़ने के साथ ही आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर भी हो सके। इस दौरान जिला ग्रामोद्योग अधिकारी किरन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आटोमैटिक मोटोराइज्ड दोना मशीन के लिए कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके चयन के लिए विभाग द्वारा चयन समिति गठित की गयी थी, चयन समिति द्वारा कुल चयनित 7 लाभार्थियों को आटोमैटिक मोटोराइज्ड दोना मशीन हेतु पात्र पाया गया। उन्होंने बताया कि कु0 रुबी सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, आकाश सिंह अरविन्द सिंह सियाराम,राम मुरत पवन कुमार, जयराम, सन्त कुमार, बटेस्वर, सुनील सिंह चौहान, प्रमोद सिंह चौहान , तथा अरविन्द, कृपाशंकर को दोना बनाने हेतु आटोमैटिक मोटोराइज्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुभाष चन्द्र यादव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी किरन श्रीवास्तव , महेश मोर्या, रमेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ शुभारम्भ

सोनभद्र। जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर में मंगलवार को नवोदय विद्यालय समिति के लखनऊ की क्षेत्र स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारम्भ एसडीएम प्रमोद तिवारी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआद्य कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजरोपन तथा प्रतियोगिता उद्घाटन उद्बोधन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तत्पचत् दीप प्रज्वलन एव सरस्वती वंदना की प्रस्तुत की गई इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ व साल के माध्यम से स्वागत किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालय मिर्ज़ापुर के प्राचार्य डॉक्टर एस.पी. त्रिपाठी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिनका विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला तीरंदाजी फेडरेशन के सचिव बलराम कृष्ण यादव किया। अपने उद्बोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य व मंगलमय जीवन की कामना की तथा विद्यालय में आने वाले समय में विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई के साथ-साथ अन्य क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की आशा व्यक्त की, इस कार्य के लिए शिक्षकों द्वारा किए जा रहे हैं प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। विशिष्ट अतिथि नवोदय विद्यालय मिर्जापुर के प्राचार्य डॉक्टर एस पी त्रिपाठी ने अपने पुराने कार्याकाल में नवोदय विद्यालय सोनभद्र को खोलने के संबंध में किये गए प्रयासो एव अनुभवो को साझा किया तथा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य व नये कीर्तिमान की स्थापना के लिए मंगल कामना की।

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि एव अध्यक्ष द्वारा तीर चलाकर तीरंदाजी मीट का उदघाटन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया शिव तांडव नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।

क्रेशर प्लांट की अवैध ब्लास्टिंग के चलते ग्रामीणों में फैली दहशत

मीरजापुर। जनपद के मड़िहान विकासखण्ड के ग्राम सभा धनावल में स्थित क्रेशर प्लांट के अवैध ब्लास्टिंग के चलते ग्रामीणों में दहशत माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मोहन ब्रम्ह मंदिर के पास प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों से बताया कि हम सभी लोग ग्राम धनावल के केशर प्लांट के अवैध ब्लास्टिंग के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांट पर मनमानी तरीके से रात के अंधेरे में हो रही ब्लास्टिंग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बेलहरा गांव की महिलाओं ने बताया कि ज्यादातर घरों में अवैध ब्लास्टिंग से मकानों, घरों में दरारे आ जारही हैं। प्राथमिक विद्यालय भवन में जर्जर हो गयें हैं। जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। क्रेशर प्लांट द्वारा पहाड़ो को खोदकर बड़े बड़े गड्ढों तलाबों में तब्दील कर दिया गया है। अत्यधिक प्रदूषण धूल के चलते कई प्रकार की बीमारियां फैल रहीं हैं, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। जल का स्तर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। रात के अंधेरे में अत्यधिक ब्लास्टिंग से बच्चे डर जा रहें हैं।

अवैध ब्लास्टिंग व खनन के चलते कई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। व कई लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। ब्लास्टिंग के चलते उड़ने वाले पत्थरों से गांव के कई लोग घायल हो गए हैं, वन क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु गांव में पलायन कर रहे है। विंध्य सार्थक ग्रीन सिटी के मालिक अरुण दुबे ने बताया कि क्रेशर प्लांट के द्वारा मानक यह है कि खनन से हुए गड्ढे को घेर कर सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके चलते ग्रामवासी पीड़ित व प्रताड़ित हैं। शासन के समक्ष कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी दोषियों विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गयी एवं पीड़ित लोगो को न्याय नहीं मिल रहा इसके चलते लोग गांव में पलायन करने को मजबूर हैं। जिसमें मोहन बरम धाम के पुजारी आशीष द्विवेदी,उमाचरन दुबे,रविन्द्र दुबे उर्फ मुन्ना, महेंद्र दुबे, तालकेश्वर दुबे, परमेश्वर दुबे, अश्विनी दुबे निराला दुबे, प्रिंस दुबे अन्य सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

इफको फूलपुर में वृहद स्तर पर किया गया पौधरोपण

प्रयागराज। इफको घियानगर फूलपुर परिसर उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महाभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ एस सी शुक्ल क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज रहे। इफको परिसर में नीम आम जामुन सहित विभिन्न फलदार और औषधीय पौधे लगाये गये तथा सीमावर्ती गांवों में वृक्षारोपण हेतु पौधे दिये गये। कुल 3500 पौधे इफको कोलोनी इफको कोर्डेट तथा इफको संयंत्र में रोपित किये गये। आगामी एक दो दिन में 8500 पौधे और लगाये जायेंगे तथा सीमावर्ती गांवों में भी वृक्षारोपण हेतु पांच हजार पौधे वितरित किये जायेंगे। सभी ने पर्यावरण को बचाने का तथा एक वृक्ष अवश्य लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक ईपीसी उमेश कुमार शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक ए पी राजेन्द्रन संयुक्त महाप्रबंधक डॉ अनिता मिश्रा अरूण कुमार अरवेन्द्र कुमार विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी और महामंत्री स्वयम प्रकाश इफको इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय तथा बड़ी संख्या में इफको अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया।

आर्थिक सर्वेक्षण

उम्मीद से भरपूर

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की प्रगति व विकास के प्रति उम्मीदों से भरपूर है। हालांकि, केन्द्रीय बजट के एक दिन पहले पेश सर्वेक्षण में चिन्ताजनक क्षेत्रों की ओर संकेत करते हुए केन्द्र सरकार से इनमें प्राथमिकता से काम करने का अनुरोध किया गया है। बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परंपरा है क्योंकि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख कर इससे बजट का माहौल बनता है। इस वर्ष अच्छी आर्थिक वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.5-7.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण एक समग्र रिपोर्ट है जिसने पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की समीक्षा कर विभिन्न क्षेत्रों में तेज वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। इस आशावाद के अनेक आयाम हैं जिनमें मजबूत घरेलू उपभोग, बढ़ता निवेश तथा लाभदायक सरकारी नीतियां शामिल हैं। मजेदार बात है कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थायें जीडीपी का इससे काफी निचला स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सर्वेक्षण ने ढांचागत विकास पर सरकार की सक्रियता को रेखांकित किया है जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है। सड़क, रेल और बंदरगाह विकास की वर्तमान समय में जारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और क्षमता में वृद्धि होगी तथा सहज व्यापार एवं वाणिज्य में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास आर्थिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आलोचनाओं के बावजूद सर्वेक्षण का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, निर्यात व खासकर उच्च वृद्धि दर वाले फार्मास्यूटिकल्स, एलेक्ट्रानिक्स व टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने से भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्याग्रस्त क्षेत्रों की बात भी की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाने वाली कृषि प्राथमिकता बनी हुई है। सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों का सुझाव दिया है। तकनीकों में खोज तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने उचित ही विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया है जो अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल सकते हैं तथा राष्ट्रीय वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी बाधा मुद्रास्फीति है। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए बिना वृद्धि को प्रभावित किए मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई जा सकती है। बेरोजगारी एक और बाधा है जिसे प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण ने ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जो कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन दें तथा आर्थिक विकास के उपयुक्त परिवेश का निर्माण करें ताकि बढ़ती हुई युवा जनसंख्या की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के उपयुक्त परिवेश बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पुनः दुहराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण के अनेक सुझावों को शामिल किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकतायें परिभाषित की हैं। इनमें कृषि, रोजगार, मानव विकास, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण, खोज, ढांचागत संरचना तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। इनसे बेरोजगारी घटाने, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने तथा अर्थव्यवस्था को समावेशी व टिकाऊ बनाने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

छोटे उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा विलंबित भुगतान बड़ी समस्या है। इसके कारण कार्यकारी पूंजी में आने वाली कमी से उत्पादन प्रभावित होता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

वित्त कानून, 2023 के अंतर्गत आयकर कानून में संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गया है। इसमें वस्तुओं व सेवाओं के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों-एमएसएमई को 45 दिन से अधिक भुगतान के विलंब तथा कर छूट की मांग करने पर रोक लगाई गई है। एमएसएमई सहायक इकाइयां हैं जो बड़े उद्यमों या प्रमुख इकाइयों को वस्तुओं और अधिकांशतः सहायक वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में सहायता करती हैं। ये इकाइयां छोटे पैमाने पर काम करती हैं और इनको सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के रूप में पुनः परिभाषित किया जाता है जो उनके 'निवेश' और 'टर्नओवर' से तय होता है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम विकास कानून, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम का अर्थ ऐसा उद्यम है जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक न हो तथा उनका टर्नओवर 50 मिलियन रुपये से अधिक न हो। लघु उद्यम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 100 मिलियन रुपये से कम होना चाहिए तथा टर्नओवर 500 मिलियन से अधिक न हो। मझोले उद्यम के लिए यह सीमा निवेश हेतु 200 मिलियन तथा टर्नओवर 1000 मिलियन परिभाषित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत है। अखिल भारतीय विनिर्माण में विनिर्माण एमएसएमई का हिस्सा और अधिक लगभग 36 प्रतिशत है।

कामर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स महानिदेशालय-डीजीसीआईएस के अनुसार, अखिल भारतीय निर्यातों में एमएसएमइ-विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा पिछले दो वर्ष में 44 से 50 प्रतिशत के बीच रहा है। जहां तक रोजगार का सवाल है, मैक्किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट-एमजीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई का योगदान कुल में 52 प्रतिशत है। 'अनौपचारिक' क्षेत्र में एमएसएमई के अलावा पारिवारिक संपत्ति व साझेदारी वाले उद्यम शामिल हैं। इनका रोजगार में योगदान 75 प्रतिशत से अधिक है, जबकि जीडीपी में इनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। इस प्रकार एमएसएमई अर्थव्यवस्था की संभावनायें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही ये 'समावेशी' विकास में अपनी भूमिका अदा करते हुए खासकर रोजगार बढ़ाने, आय बढ़ाने व आय असमानता घटाने का काम करती हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में उन पर आर्थिक निर्णयों का बोझ पड़ा है।

इनमें 2016 में नोटबंदी, 2017 में वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी लागू करना तथा 2020 में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी का विनाशकारी प्रभाव शामिल हैं। सरकार ने इनकी समस्यायें दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिनमें 500,000 करोड़ रुपये की बिजनेसों व एमएसएमई के लिए आपातकालीन कर्ज गारंटी योजना-ईसीएलजीएस तथा एमएसएमई सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान शामिल है जिससे उनको सरकारी ठेके लेने में सहायता मिली है। इसके अलावा एमएसएमई के वर्गीकरण में रियायतें, गैर-टैक्स लाभों का 3 साल तक विस्तार, खुदरा एवं थोक व्यापारों को एमएसएमई में शामिल करना, उद्यम सहायता प्लेटफार्म-यूएपी शुरू करना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज योजना-पीएसएल के अंतर्गत लाभ दिलाना, ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों को शामिल करने वाले आनलाइन पोर्टल 'चैम्पिन्स' को शुरू करना तथा एमएसएमई की शिकायत निवारण व सहायता की व्यवस्थायें शामिल हैं।

इन सारी पहलों का उद्देश्य कर्ज की उपलब्धता, तकनीक के समावेशन, बाजार सहायता, आदि प्रदान करना है, पर इन उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा बकाया देर में भुगतान करने की समस्या बनी हुई है। सप्लाई की गई वस्तुओं का भुगतान न मिलने पर उनके पास कार्यकारी पूंजी की भारी कमी हो जाती है जिससे 'उत्पादन जारी रखने की क्षमता' पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 15 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लिखित अनुबंध की स्थिति में 45 दिन में भुगतान करना जरूरी है, जबकि लिखित अनुबंध न होने की स्थिति में यह अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। 2019 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विशिष्ट कंपनी आदेश जारी कर कहा था कि बड़ी फर्मों को हर 6 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही एमएसएमई को 45 दिन की सीमा में कोई भुगतान बकाया न हो। लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है और अनेक फर्मों को बंद करना पड़ा है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने आईटी एक्ट, 1961 के अंतर्गत समाधान खोजने का प्रयास किया। वित्त कानून, 2023 ने आईटी एक्ट, 1961 में नई धारा 43बीएच जोड़ी।

इसके अनुसार यदि बड़ी कंपनी लिखित अनुबंधों की स्थिति में 45 दिन में एमएसएमई को भुगतान नहीं करती है तो इस खर्च को उसके वित्त वर्ष की कर योग्य आय में काटा नहीं जा सकता है। एमएसएमई से खरीदी वस्तुओं का भुगतान खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसे राजस्व से काटा जा सकता है। यदि कोई बड़ी फर्म एमएसएमई को 45 दिन की निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करती है तो धारा 43बीएच के अनुसार वह इस धनराशि को कर योग्य आय से काट नहीं सकती है। इससे उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह एक बड़े प्रतिरोधक का काम करता है जिससे बड़े उद्यमों द्वारा एमएसएमई का भुगतान रोकना संभव नहीं होगा। लेकिन इस अतिरिक्त कर का कंपनी की बैलेंसशीट पर प्रभाव हमेशा के लिए नहीं पड़ता है। इस अतिरिक्त कर को अगले साल एडजस्ट किया जा सकता है जब कंपनी एमएसएमई को भुगतान करे।

इस प्रकार यह धारा सभी पक्षों के बीच अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इससे बड़े उद्यमों को एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता दने के साथ ही उनके वित्तीय स्वास्थ्य व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके साथ ही वह बड़े उद्यमों को अनावश्यक दंड नहीं देती है। लेकिन इस बीच कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2019 के आदेश में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में राहत दे दी है। 15 जुलाई, 2024 को जारी एक आदेश के अनुसार इसकी आवश्यकता केवल उन कंपनियों को है जिन्होंने किसी एमएसएमई को अनिवार्य 45 दिन के भीतर भुगतान न किया हो। इसका निर्धारण वस्तुओं या सेवाओं को स्वीकार करने की तिथि के आधार पर होगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 9 के अनुसार उस बड़े उद्यम को यह सूचना देनी होगी जिसने एमएसएमई से वस्तु एवं सेवा प्राप्त की है और उसे निर्धारित 45 दिन में भुगतान नहीं किया है।

लेकिन यह आदेश जारी होने के पहले बड़े उद्यमों को यह सूचना उस स्थिति में भी देनी होती थी, जब एमएसएमई को कोई भुगतान निर्धारित 45 दिन की अवधि में बाकी न हो। इससे बड़े उद्यमों को कानून के क्रियान्वयन से थोड़ी राहत मिली है और उन पर एमएसएमई भुगतान का दबाव घटा है। लेकिन इसके बावजूद उद्योगों और बिजनसों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आईटी एक्ट में संशोधित इस धारा का क्रियान्वयन एक साल यानी अप्रैल, 2025 तक टाल दिया जाए।

इसके साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बड़े उद्यम छोटी फर्मों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे एमएसएमई से कोई सप्लाई न लें। इसके बजाय वे केवल ऐसी एमएसएमई से व्यवहार करें जिनका पंजीकरण 'उद्यम पोर्टल' पर न हो या वे गैर-एमएसएमई से सामान खरीदें। 'उद्यम पोर्टल' केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई पंजीकरण के लिए बनाया गया है। बड़े उद्यमों के इन अनुरोधों को अस्वीकार कर सरकार को आईटी एक्ट की धारा 43बीएच को स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने देना चाहिए।

भारत में अस्तित्वमान तीन नये कानून

> **"जहां कुछ कानूनी निकायों ने नए कानूनों की आलोचना की है, वहीं अन्य इन कानूनों को आधुनिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखते हैं।"**

मनोज वर्घीस
(लेखक मीडिया जगत से जुड़े हैं)

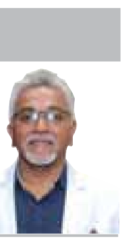

1 जुलाई को शुरू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, कुछ कानूनी निकायों और अन्य नागरिक संगठनों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि इसे संसद में 'बहुत चर्चा' के बिना पेश किया गया है। जबकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञ इसे एक 'नया अवतार' मानते हैं जो देश को पसंदीदा औपनिवेशिक कानूनों से समकालीन भारत में बदलाव करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कानूनों ने लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किए गए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के कानूनों की जगह ले ली है। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। करीब 20 नए अपराध जोड़े गए, 40 अपराधों में संशोधन किया गया, 83 नए जुर्माने लगाए गए और छह सामुदायिक सेवाएं शुरू की गईं, नए कानून जनहित में त्वरित न्याय देने के लिए तैयार हैं।

नए कानून 'नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले' की तर्ज पर बनाए गए हैं। आम धारणा यह है कि पुलिस को अब 'डंडे' की जगह 'डेटा' से काम करना होगा। सार्वभौमिक रूप से, किसी भी प्रणाली में बदलाव लाना और उसे लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे बढ़कर, कानूनी प्रणाली में बदलाव अनुकूलन के लिए एक जटिल तंत्र है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा कहते हैं, परिवर्तन अपरिहार्य है, और प्रगतिशील कानून किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे हैं।

पुलिस को यह समझने की जरूरत है कि वे अधिकार क्षेत्र की कमी या विवादित अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके लिए इसे व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामलों की संख्या उनके संबंधित पुलिस स्टेशन की बदनामी लाएगी। अब वे कानूनी रूप से (शून्य एफआईआर) दर्ज करने और ऐसे मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं। बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एल मेहता कहते हैं, कानून लोगों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा अनुकरण किए जाने वाले मानदंडों का एक समूह है। कानून कानूनी व्यवस्था के लिए प्रभावी उपाय है। कानूनी व्यवस्था में देरी अपरिहार्य तंत्र है। केवल 20 प्रतिशत मामले ही अदालत तक पहुँचते हैं, पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह एक कठिन कार्य है और इन लंबित मामलों का निपटारा करने में 300 साल से अधिक का समय लगेगा। बीएनएसएस के अनुसार, नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं, सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूरा करना सुनिश्चित करते हैं (धारा 193)। समन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते हैं (धारा 64, 70, 71)। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन दे सकते हैं (धारा 346)।

नए कानून में सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना (धारा 398) लागू करने का आदेश दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों (अध्याय 5) और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरूआत (धारा 4, 202, 209, 226, 303, 355, 356) के लिए विशेष रूप से बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, और पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सरकार ने कई दौर के अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नए शुरू किए गए तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में कानूनी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों के साथ प्रौद्योगिकी अनुकूलता की सुविधा के लिए मौजूदा सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पुलिस, जेलों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में तीन नए आपराधिक कानूनों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह नए कानूनों का मसौदा तैयार करने में शिक्षाविदों की भूमिका की सराहना करते हैं। उनका सुझाव है कि आने वाले दिनों में देश को पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, जितने अधिक नए कानून सामने आएंगे, उतनी ही अधिक इसकी कमियों के उजागर होने की संभावना है। क्या अपराध की बढ़ती घटनाएं पुलिस और वकीलों के लिए अच्छी हैं, यह एक बड़ा सवाल है!

आप की बात

राहत देने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 03 राहत देने और सबको साधने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर अत्यधिक जोर दिया गया जो कि आवश्यक था। महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी के बजाय उल्टे सात प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। यह फैसला उचित नहीं लगता है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र को भी और अधिक धन दिया जाना था क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युद्धग्रस्त परिस्थितियों और चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों के चलते रक्षा क्षेत्र में और अधिक सुधार कर सेनाओं को अत्याधुनिक तकनीक से लेस करना अब अत्यधिक जरूरी हो गया है। चांदी सोने की ड्यूटी में कटौती करने की कोई तुक नजर नहीं आई और शेयर बाजार में करों का बोझ बढ़ाना भी उचित नहीं है। इससे निवेशक अपना निवेश शेयर बाजार से निकलकर चांदी-सोने में करेंगे जो आर्थिक विकास की गति को धीमा करेगा। अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा बजट देना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन कुल मिला कर बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। सरकार के इस कदम से उम्मीद बढ़ी है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

रोजगारोन्मुख बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार रोजगार उन्मुख बजट पेश किया है जो कि देश की युवा शक्ति के लिए अत्यावश्यक था। रोजगारों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था एक अच्छा कदम है। लेकिन पहली बार नौकरी करने वालों को एक माह की पगार देना समझ से परे है। जिनकी नौकरी लग ही गई है, उन्हें एक माह की मुफ्त पगार देने के बजाए युवकों को नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए था। कृषि को भी महत्व दिया गया है। देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए जेनेटिक फसलों पर अधिक शोध कर और उन्हें मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाकर उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इससे दालों व खाद्य तेल के आयात पर लगाम लग सकती है। नौकरी व पेशेवर वर्ग को करों में जो राहत दी गई, वही राहत मध्य मार्ग के व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए थी। कर मुक्त टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया जाना था। शेयर का काम करने वालों के लिए पहले से ही लागू भारी टैक्स को और भारी बनाना शेयर होल्डर्स को निराश करेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त चिकित्सा और कारों में विशेष राहत भी दी जानी चाहिए थी। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाना चाहिए।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

इंटर्नशिप का स्वागत

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट को विपक्षी दलों ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। बजट का सबसे खूबसूरत पहलू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है। बजट में की गई पांच वर्ष में एक करोड़ इंटर्नशिप एवं छात्रों के लिए 10 लाख रुपए शिक्षा लोन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बिहार को 56 हजार करोड़ की और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की परियोजनायें हैं। लेकिन देखना होगा कि कहीं यह धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। बिहार में थोड़े ही समय में अनेक पुलों के गिरने की खबरें सुर्खियों में रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। इस बजट में विष्णुपद मंदिर एवम बौद्ध गया हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। इन महत्वपूर्ण स्थलों के विकास से अंतरराष्ट्रीय पर्यटक बिहार में बड़ी संख्या में आएंगे। इससे बिहार समृद्ध होगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा बजट व अपने राज्यों के लिए आबंटन पर खुशी जाहिर करने से उन मोदी-विरोधी विपक्षियों की उम्मीदें टूट गई हैं जो सरकार गिरने का राग अलाप रहे थे।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

सोना-चांदी सस्ता

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए सारी महिलाओं की प्रमुख चाहत पूरा करने के लिए साने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है। इससे अनेक महिलाओं को खुशी मिली है क्योंकि आभूषणों के प्रति उनका आकर्षण सभी जानते हैं। इससे जहां छोटे-बड़े सर्राफा कारीगरों को लाभ होगा, वहीं समाज के निम्न मध्य वर्ग व गरीब तबके को भी लाभ होगा जो शादी-विवाह या अन्य मंगल अवसरों पर घर की महिलाओं को कोई न कोई आभूषण देना चाहते थे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इसकी स्मगलिंग पर भी लगाम लगेगी तथा अमीर भारतीयों को विदेशों से सोना खरीद कर लाने का रास्ता खुलेगा। मध्यम वर्ग व सर्विस क्लास को खुश करने के लिए आयकर में राहत दी गई जिससे उन्हें 17,500 रुपये तक का लाभ हो सकेगा। निर्मला सीतारमण ने आठ महीने तक लागू होने वाले बजट में काफी नरमी दिखाई है। इस बजट से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी व देश भी प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले बजट जनता को और राहत देंगे।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

डीएम ने की सिंचाई व विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

संवाददाता। अमेठी

जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सिंचाई व विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर नहरों में पानी व रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने को लेकर समीक्षा किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में नहरों में पानी न आने तथा बिजली से संबंधित शिकायतें अत्यधिक प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से नहरों में पानी की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी दिया जाए जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए।

उन्होंने कहा कि नहरों में पानी दिए जाने के रोस्टर का जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए जिससे किसानों को जानकारी हो सके कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों में कब तक पानी आएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली एवं कहा कि वर्तमान समय में सिंचाई को लेकर ज्यादा शिकायतें आ रही हैं इसके दृष्टिगत जिन क्षेत्रों में नहरों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां सरकारी नलकूपों से सिंचाई हो रही है परंतु विद्युत कटौती तथा लो वोल्टेज के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी नलकूपों पर अनिवार्य रूप से विद्युत आपूर्ति की जाए तथा लो वोल्टेज की समस्या ना रहे। जिससे किसान भाइयों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके।

इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की विद्युत आपूर्ति का रोस्टर जारी किया जाए तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा जिससे जन सामान्य विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए विद्युत व सिंचाई विभाग को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने किया जागरूक सावधानी अपनाएं, जीवन बचाएं

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने जनपद के समस्त नागरिकों, ग्राम प्रधानों से अपील की है कि नदियों, तालाबों अथवा अन्य जल स्त्रोतों के पास बच्चों को न जाने दें। जल स्त्रोतों में डूबने के कारण जनहानि होती है। इसलिए सतर्कता बरतने और जागरूकता फैलाने का हरसंभव प्रयास करें। उन्होंने बताया है कि जल स्त्रोतों में डूबने व फंसने की स्थिति में राहत पाने के लिए एम्बुलेंस-108, पुलिस सहायता-112 व राहत आपदा कंट्रोल रूम-1070 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डूबने से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय के विवरण में बताया है कि यदि तैरना न आता हो तो नदी, नहर, नाले अथवा तालाब आदि में कदापि न जाएं एवं अपने स्वजन को भी जाने से रोकें। बच्चों को पुलिया एवं ऊंचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें। अति आवश्यक हो तो ही पानी में उतरें एवं गहराई का ध्यान रखें। ओवरलोडेड नौकाओं में न बैठें। कोशिश करें कि किसी नदी, पोखर, तालाब या जल स्त्रोत में सामूहिक रूप से स्नान करने जाते समय अपने साथ 10-15 मीटर लंबी रस्सी या धोती/साड़ी अवश्य रखें। नदियों, नहरों, जलाशयों या अन्य जल स्त्रोतों के पास लिखी हुई चेतावनी की अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों एवं जल स्त्रोतों के समीप न जाने दें। किसी के उकसावे में आकर पानी में छलांग न लगाएं। नदियों या अन्य जल स्त्रोतों के घाटों पर रीति-रिवाजों एवं संस्कारों का निर्वहन करते समय सावधानी बरतें। नदी या तालाब में तैरते/स्नान करते समय स्टंट न करें, सेल्फी आदि न लें। जल स्त्रोतों में डूबने के कारण मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये देने का प्राविधान है, जिसके लिए शारीरिक दिव्यांग होने पर 74 हजार से 2 लाख 50 हजार, मकान की क्षति होने पर 4 हजार से 1 लाख 20 हजार, पशु की मृत्यु होने पर 4 हजार से 37 हजार 500 देने का प्रावधान है।

साइबर क्राइम के शिकार 7 व्यक्तियों को 6 लाख 70 हजार 624 कराए गए वापस

संवाददाता। संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम व साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही हेतु साइबर थाना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 07 व्यक्तियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 6,70,624/- रुपया वापस कराया गया है।

पीड़ित रहमुल्लाह खान निवासी बंजरिया रोड खलीलाबाद द्वारा 4,10,000 रुपये, गंगाराम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गरथवलिया थाना खलीलबाद द्वारा 81,587 रुपये, उनि संजय राय निवासी रिजर्व पुलिस लाइन संतकबीरनगर द्वारा 94,539 रुपया, शफीउल्लाह पुत्र वाजिद अली निवासी सौरहा थाना बखिरा द्वारा 33998.52 रूपया, विशाल कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या निवासी चौरी पोस्ट उतरावल थाना खलीलाबाद द्वारा 10,000 रूपया, नीरज पाण्डेय निवासी नियर गैस गोदाम खलीलाबाद थाना खलीलाबाद द्वारा 30,000 रूपया, सूर्यभान निवासी गौरा थाना धनघटा द्वारा 10,000 रूपया साइबर फ्राड के माध्यम से कुल 6,70,624 रुपये अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकालने के संबंध में विभिन्न तिथियो में शिकायत किया गया था। जिस पर साइबर थाना संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी/ पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर पीड़ितों के रूपये वापस करने का प्रयास किया गया।

जिसमें टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए उपरोक्त आवेदक/पीड़ित रहमुल्लाह खान निवासी बंजरिया रोड खलीलाबाद का 4,10,000 रूपया, गंगाराम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गरथवलिया थाना खलीलबाद का 81,587 रूपया, उ0नि0 संजय राय निवासी रिजर्व पुलिस लाइन संतकबीरनगर का 94,539 रूपया, शफीउल्लाह पुत्र वाजिद अली निवासी सौरहा थाना बखिरा का 33998.52 रूपया, विशाल कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या निवासी चौरी पोस्ट उतरावल थाना खलीलाबाद का 10,000 रूपया, नीरज पाण्डेय निवासी नियर गैस गोदाम खलीलाबाद थाना खलीलाबाद का 30,000 रूपया, सूर्यभान निवासी गौरा थाना धनघटा का 10,000 रूपया कुल 6,70,624 रुपये /- रुपया विभिन्न तिथियो में वापस कराये गये। अपने रूपये वापस पाकर पीडित लोगों द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए साइबर थाना संतकबीरनगर पुलिस की प्रशंसा की गई तथा साइबर थाना के टीम का विशेष आभार ज्ञापित किया गया।

बलदेव एकेडमी स्कूल कौशलपुरी में जागरूकता शिविर का आयोजन

अयोध्या। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा बलदेव एकेडमी स्कूल कौशलपुरी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम-2013, विषय पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्या किरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सीमा श्रीवास्तव, रेखा सिंह व स्कूल की छात्रायें तथा पीएलवी प्रियंका त्रिपाठी उपस्थित रहीं। उक्त जागरूकता शिविर में प्राधिकरण सचिव द्वारा यह जानकारी दी गई कि कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। एक स्वस्थ वातावरण यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि लोग अपने काम को पूरा करने के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हालाँकि, आज भी ऐसे कारक हैं जो शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाते हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

ऐसा ही एक मुद्दा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का है। भारत में, हमारे पास कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पोश अधिनियम, 2013) नामक एक विशेष कानून है, जिसे हमारे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। दुर्भाग्य से 2013 में पोश अधिनियम लागू होने के लगभग एक दशक बाद भी यौन उत्पीड़न के मामले महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा बने हुए हैं।

एटीएस में तैनात हुए सीओ ब्रजेश सिंह को दी गई विदाई

संतकबीरनगर। जनपद में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ब्रजेश सिंह को सीओ खलीलाबाद से एटीएस मुख्यालय लखनऊ स्थानान्तरित होने पर रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा ब्रजेश सिंह को प्रतीक चिन्ह देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया तथा उनके सुखमय जीवन व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई व सम्मानपूर्वक सरकारी वाहन में बैठाकर विदा किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह, नवागत सीओ अजीत चौहान, सीआ मेंहदावल केशवनाथ, सीआ धनघटा अजय सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकांत ओझा, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद सतीश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

विद्युत कटौती को लेकर हाहाकार व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

लालगंज, रायबरेली। क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती व अन्य समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी व एक्सईएन से मिलकर उन्हे 4 सूत्रीय ज्ञापन सौपतें हुए उनके निराकरण की मांग की है। लालगंज उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राहुल भदौरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी नवनीत शुक्ला व विद्युत विभाग के एक्सईएन से मिलकर उन्हे ज्ञापन सौपा। जिसमें नगर व देहात क्षेत्र में हो रही अंधाधुध विद्युत कटौती को रोकने की मांग की है। अध्यक्ष ने बताया कि नगर में महज 12 से 15 घंटे भी विद्युत आपूर्ति ठीक ढंग से नही हो पा रही है। जिसके लिये सबसे अधिक जिम्मेदार जर्जर तार है जिन्हे क्रमबद्ध तरीके से बदलने की मांग की गई है। देहात क्षेत्र में भी कटौती से हाहाकार मच हुआ है। उमस व सूखे खेत लोगो की परेशानी बयां कर रहे है। युवा उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नगर के बदहाल मार्गो को ठीक नही किया गया जिससे आयेदिन जाम की समस्या बनी रहती है साथ ही उड़ रही धूल से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।

आरएसएम के ब्लॉक अध्यक्ष बने भानु प्रताप सिंह

रायबरेली। शिक्षकों के हित में कार्य करने वाले राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जगतपुर कार्यकारिणी का गठन किया गया। जगतपुर ब्लॉक में कार्यकारिणी के हुए चुनाव में भानु प्रताप सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है। संरक्षक आशुतोष मौर्य को घोषित किया गया। वहीं, महामंत्री विनोद पाल, कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति को चुना गया। गौरा ब्लॉक की कार्यकारिणी का चुनाव जिला कोषाध्यक्ष राजेश मौर्य, डलमऊ के ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह, संदीप सिंह निर्वाचन अधिकारी और जिला मंत्री वेद प्रकाश यादव की देखरेख में संपन्न हुआ।

जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ने बताया कि जगतपुर ब्लॉक कार्यकारिणी में दिनेश पाल को सर्वसम्मति से संगठन मंत्री, सुनील मिश्रा को कोषाध्यक्ष, शिवप्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार को मीडिया प्रभारी, प्रचार मंत्री लोकेश, नरेंद्र कुमार व शेर बहादुर, संयुक्त महामंत्री के पद पर रमाकांत द्विवेदी, चंचल शाह, शिवमोहन मौर्य तथा सत्येंद्र यादव को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया।

जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो, किसानों को उपलब्ध हो बिजली-पानीः वीरेन्द्र यादव

रायबरेली। समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं एवं खराब कानून व्यवस्था को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली को जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने से पूर्व कलेक्ट्रेट में जिला अध्यक्ष इं0 वीरेन्द्र यादव ने कहा कि किसानों की धान की फसल की रोपाई पानी के संकट के कारण बाधित हो रही है बिजली की अंधाधुंध कटौती एवं लो-वोल्टेज के कारण सिंचाई हेतु लगे ट्यूवेल चल नहीं पा रहे है बिजली की लो-वोल्टेज के कारण ट्यूवेल में लगी मोटरें जल रही है नहरों में निर्धारित मांग से बहुत कम पानी की आपूर्ति हो रही है बरसात कम होने के कारण जनपद सूखे की चपेट में है। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि धान की फसल रोपाई हेतु किसानों की सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से कम से कम 18 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाये एवं लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान तत्काल कराया जाय।

नहरों में मांग के अनुरूप किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाय। इस अवसर पर विधायक श्याम सुंदर भारती ने कहा कि जनपद की पुलिस निरंकुश है कानून व्यवस्था ध्वस्त है।

संयुक्त टीम ने दर्जन भर मदिरा की दुकानों में छापा मार कर चेकिंग की

संवाददाता। कालपी, जालौन

आगामी सावन मास, रक्षाबंधन के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस तथा आवकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा कालपी नगर, उसरगांव तथा जोल्हूपुर में दर्जनभर से अधिक देशी, अंग्रेजी शराब तथा मदिरा की दुकानों में छापा मारकर अभियान चलाया गया। टीम के द्वारा मदिरा की दुकानों की चेकिंग करके लाइसेंसधारकों तथा संचालकों को ओवररेटिंग में मदिरा न बेचने की की कठोर चेतावनी दी गई।

मंगलवार को उपजिलाधिकारी के साथ क्षेत्राधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार पचौरी, आवकारी अधिकारी मुकेश प्रताप सिंह, अतिरिक्त निरीक्षक मुहम्मद अशरफ की संयुक्त टीम में शामिल पुलिस कर्मियों तथा आवकारी कर्मचारियों ने कालपी नगर के मोहल्ला बाईपास, सब्जी मंडी, टरननगंज टॉकीज रोड, खोवा मंडी के अलावा जोल्हूपुर मोड़, उसरगांव आदि स्थानों में स्थित देशी तथा अंग्रेजी शराब की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। दुकानों में शराब के स्टॉक का निरीक्षण तथा गणना करके रजिस्टर तथा अभिलेखों से मिलान किया।

इस दौरान बोतलों तथा पैकेटों की सील की चेकिंग तथा टेस्ट किया गया। एसडीएम ने दुकानों तथा परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। वहीं आवकारी अधिकारी मुकेश प्रताप सिंह ने लाइसेंस धारकों को हिदायत दी कि दुकानों में रेट लिस्ट का साइन बोर्ड में मोबाइल नम्बरो को जरूर अंकित करें। उन्होंने बताया कि लाइसेंस की शर्तो तथा विभागीय नियमों के तहत शराब की बिक्री करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ओवर रेटिंग में बिक्री कर गड़बड़ी करने पर कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एनटीपीसी ऊंचाहार में हुआ संविदाकार सम्मेलन

ऊंचाहार। एनटीपीसी ऊंचाहार में एनटीपीसी एमएसएमई सेल व संविदा एवं सामग्री विभाग के सौजन्य से विशेष संविदाकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। परियोजना प्रमुख मनदीप सिंह छाबड़ा ने सभी संविदाकारों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि संविदाकार एनटीपीसी की प्रगति में सहभागी होने के नाते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और एनटीपीसी को विश्वस्तरीय कंपनी बनाने में संविदाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। श्री छाबड़ा ने संविदाकारों के सुझावों को सुना तथा यथासंभव क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इस सम्मेलन की विशेष बात यह रही कि इसमें एमएसएमई के तहत लघु उद्योगों के क्षेत्र में मिल रहे अवसरों पर प्रकाश डाला गया, जिसका लाभ सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे 70 संविदाकारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25 तथा 3 महिला संविदाकारों को भी मिला। जेम व आरएक्सआईएल द्वारा प्रेजेंटेशन देकर संविदाकारों को जागरुक किया गया।

चुर्खी-बाबई मार्ग में दो किमी तक गड्ढों की भरमार, राहगीर परेशान

जालौन, उरई। चुर्खी बाबई मार्ग पर देवनगर चौराहे से लगभग दो किमी मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी मरम्मत के लिए ग्रामीण ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के निस्तारण में लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड एक ने शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि जालौन-चुर्खी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) है, जिसकी लंबाई 10 किमी है। मार्ग के किमी एक व दो जालौन आबादी भाग है। यह क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत भी आता है। मार्ग के किनारे नाले का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा था। नगर पालिका द्वारा नाले की खुदाई की मिट्टी पूरे रास्ते में जगह-जगह फैला दी थी और कई स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यातयात सुचारू रखने के लिए पॉट होल्स फिलिंग का कार्य समय-समय पर कराया जाता है। किमी संख्या दो में कई स्थानों पर जल संस्थान की पाइप लाइन है। जिससे पानी बहकर मार्ग पर आ रहा है और मार्ग को खराब कर रहा है। जिसको ठीक करने के लिए जल निगम को पत्र लिख दिया गया है और नगर पालिका को भी सड़क के किनारे पड़े मलबे व मिट्टी आदि को हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

चौकीदार की हत्या के मामले में छह लोगों को किया गिरफ्तार

रायबरेली। दौलतखेड़ा गांव में बीते दिनों चौकीदार का हाथ पैर बंधा हुआ शव मिलने के मामले में पुलिस ने घटना में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है आपको बता दे कि आज दिनांक 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार को समय करीब 2 बजे रायबरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों से थाना क्षेत्र के दौलत खेड़ा गांव में यहां के रहने वाले शिवकुमार पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम उम्र 55 वर्ष निवासी बैंती निर्मला अधिनियम जल निगम की टंकी पर चौकीदारी करता था जिसकी हत्या करने के बाद हत्यारे ने उसके 100 को हाथ पैर बांधकर फेंक दिया था इस हत्याकांड में संलिप्त छह आरोपियों को शिवगढ़ थाने की पुलिस ने व एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय किरण हाल में लाकर खुलासा किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों में आयुष कुमार महेश प्रसाद विशाल कुमार हरगोविंद विपिन कुमार शुभम साहू है जो लखनऊ जनपद व बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं।

पूर्व प्रबंधक ने शिक्षा अधिकारियों पर लगाए नियमों की अनदेखी के आरोप

● मामला आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रबंध समिति प्रबंधक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर तैनाती का

संवाददाता। कालपी, जालौन

विद्यालयों की प्रबंध समिति में पदाधिकारी को किस तरह से बिना नियमों की परवाह किए पदस्थ और हटाए जाने की प्रक्रिया को कर दिया जाता है और हैरत की बात तो यह है कि इस कार्य को अंजाम देने वाले कोई और नहीं शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हो तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजिमी ही है यहां कालपी आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी में ऐसी ही एक बानगी देखने को मिली जब विद्यालय के पूर्व प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक पर नियमों की अनदेखी कर प्रबंध समिति का चुनाव कराए बिना समिति की चयनित मंत्री को हटाकर इंटर कॉलेज का प्रबंधक पद पर आसीन कर देने तथा सीनियर टीचर्स की अनदेखी कर कार्य वाहक प्रधानाचार्य के पद को भी इसी तरह से भर देने का आरोप लगाते हुए आपत्ति उठाई।

आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी के पूर्व प्रबंधक नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव संबंधी जानकारी मांगी तथा प्रमाणित कॉपी देने का अनुरोध किया जिला विद्यालय निरीक्षक ने मेरे पत्र के उत्तर में जवाब देते हुए केवल विद्यालय की समिति के चुनाव की कार्रवाई ही प्रदान की जिससे यह साफ हो जाता है की विद्यालय में प्रभावी प्रशासन योजना के तहत कॉलेज के प्रबंध समिति का चुनाव ही नहीं हुआ जो की बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। विद्यालय के सूत्रों की माने तो मामला कुछ और ही है नाम न छापने की शर्त पर कुछ सूत्रों ने बताया प्रधानाचार्य पद की योग्यता न होने के बाबजूद इसलिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया जिससे विद्यालय के विभिन्न खातों में जमा लगभग 70 लाख रुपया का बंदरबाट आसानी से हो सके विद्यालय के सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है उक्त बंदरबाट की रकम शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का भी हिस्सा बनती है लिहाजा इस कार्यवाही को अंजाम देने में सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है यदि मामले की जांच होती है तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी विभाग के उच्च अधिकारियों को भी सप्रेम भेंट में इसलिए दी जाएगी। उत्तर प्रदेश मध्यमिक चयन आयोग से चयनित प्रधानाचार्य श्रीमती नुसरत जहां जिन्होंने विद्यालय के पठन-पाठन एवं अनुशासन में पूरी जनपद में विद्यालय का नाम रोशन किया है इसीलिए यह विद्यालय जनपद में एक विशेष स्थान रखता है को इसी वजह से गैर कानूनी फर्जी ढंग से निलंबित कर दिया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की सात छात्रायें बीमार होकर पहुंचीं अस्पताल

जालौन, उरई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गूढ़ा न्यामतपुर की छात्राओं ने बुधवार की सुबह अचानक पेट दर्द होने और दस्त होने की शिकायत की। बीमार होने पर सात छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बीमार छात्राओं की तबियत में सुधार होने के बाद उन्हें वापस स्कूल भेज दिया गया।

बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में साफ-सफाई की विशेष आवश्यकता होती है। कक्षा सात की छात्रा ईशू को मंगलवार को बुखार आ गया था। बुखार आने पर उसे स्कूल में ही प्रथम उपचार दिया गया। बुधवार की सुबह कक्षा आठ की छात्राओं में डोली, सोनिया, आरती व रूचि, कक्षा सात की परिधि व कक्षा छह की नव्या ने पेट दर्द व दस्त आने की शिकायत वार्डन से की।

एक साथ अचानक सात छात्राओं के बीमार होने पर वार्डन गायत्री देवी व हिंदी शिक्षिका जयश्री छात्राओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। बीमार छात्राओं का डॉ. योगेश आर्या ने चिकित्सकीय परीक्षण किया और आवश्यक दवाएं दीं। प्राथमिक उपचार के बाद तबीयत में सुधार होने के बाद सभी छात्राओं को स्कूल भेज दिया गया।

जानलेवा हमले के आरोपी खुलेआम दे रहे धमकी, एसपी से शिकायत

उरई, जालौन। पिछले दिनों मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट कर युवक को मरणासन्न कर देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित के परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी न होने से आरोपी समझौते का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डकोर कोतवाली क्षेत्र के मुहम्मदाबाद गांव निवासी राहिल खान ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। बताया कि 17 जुलाई को गांव में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी गांव के ही नौशाद, राशिद व औरंगजेब ने अचनाक विवाद शुरू कर दिया। उसके भाई तालिब ने जब समझाने की कोशिश की। तो आरोपियों ने धारदार हथियार से उसको ही मारपीट कर मरणासन्न कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कर ली थी। लेकिन घटना के छह दिन बीतने के बाद भी आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जिससे वह घर आकर समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिससे वह व उनका पूरा परिवार भयभीत है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जिससे उसे न्याय मिल सके। एसपी ने उन्हें भरोसा दिया है।

सहाब के ग्रामीणों ने की कच्चे रोड पर सीसी डलवाने की मांग

जालौन, उरई। गांव में आम रास्ते पर सीसी रोड पड़ा है। आगे पीछे सीसी रोड होने से और बीच में कुछ रास्ता कच्चा होने से रास्ते में जलभराव हो जाता है। जिससे गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित ग्रामीणों ने कच्चे रास्ते पर सीसी रोड डलवाने की मांग एसडीएम से की है। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सहाव निवासी अखिलेश कुमार आदि ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके गांव में आबादी की जगह में गाटा संख्या 553 और 557 के सटा हुआ आम रास्ता है। इस आम रास्ते में एक जबह मोड़ है। इस मोड़ के आगे और पीछे सीसी रोड का निर्माण हो चुका है। मोड़ के कुछ पहले और कुछ बाद बाद तक के में रास्ते में सीसी रोड नहीं डलवाई गई और काम को रोक दिया गया। इस जगह पर सीसी रोड न होने से रास्ते का लेवल नीचे हो गया है। इस स्थान पर नालियों का पानी भरता है साथ ही बारिश होने पर जलभराव हो जाता है। गांव के लोगों को घुटनों तक पानी से होकर निकलना पड़ता है। ग्रामीणों ने एसडीएम से छोड़े गए कच्चे रास्ते पर भी सीसी रोड बनवाने की मांग की है। ताकि गांव के लोगों को बारिश में दिक्कत का सामना न करना पड़े।

साहब! पहले बेटी को भगाकर ले गये अब मांग रहे दहेज में बाइक

जालौन, उरई। लगभग एक वर्ष पूर्व युवक ने युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली। जब परिवार के लोग राजी हो गए तो युवती घर आ गई। पिता ने बेटी की विदाई में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर बेटी को विदा किया। लेकिन युवक और उसके परिजनों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग को लेकर युवती को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिला सड़क सुरक्षा समितिः डीएम ने ली बैठकए दिए निर्देश

● चालक परिचालकों के लिए लगवाएं नेत्र परीक्षण शिविर ●भीड़ भाड़ वाले एरिया में जमीन चिन्हित कर पार्किंग को ईओ बनाए व्यवस्थित ●मानक के अनुरूप संचालित हो स्कूली वाहनए कराए स्कूली वाहनों का फिटनेसः डीएम

लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं जाने, यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक का संयोजन, संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड (तृतीय) के अधिशाषी अभियंता अनिल कुमार यादव और एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने जिले में घटित दुर्घटनाओ का विश्लेषण करते हुए नए ब्लैक स्पॉट एवं बनरेबल लोकेशन चिन्हित करने के निर्देश दिए।

जेब्रा क्रॉसिंग का रंग जहां हल्का पड़ गया, वहा पुनः पेंट करवाएं। परिवहन विभाग ट्रांसपोर्टर के समन्वय से चालक परिचालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर लगवाएं। ईओ को निर्देशित किया कि भीड़.भाड़ वाले इलाकों में उपयुक्त जमीन चिन्हित कर पार्किंग को व्यवस्थित करने का काम करें। सीजन के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चीनी मिल वाहनों में रिफ्लेक्टरए लाल कपड़ा अनिवार्य रूप से लगाया जाए।

डीएम ने निर्देश दिए कि स्कूली वाहन मानक के अनुरुप होने पर ही संचालित हो। बीएसए .डीआईओएस विद्यालयों से समन्वय करते हुए शत प्रतिशत वाहनों का फिटनेस सुनिश्चित कराए। बैगर फिटनेस वाले वाहनों का संचालन कदापि न हो। जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट हैए वहां से सौ मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के दिशा निर्देश दिया। सुझाव दिया कि लिंक मार्ग, मुख्य मार्ग को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। बैठक में डीएम.एसपी ने जनपद में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषणए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (वनरेबल लोकेशन), स्कूली वाहनों के मानकों अनुरूप होने पर ही संचालन, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों की मरम्मत/गड्ढामुक्ति, वर्षात्रृतु से पूर्व कास ड्रेनेज वर्क (पुल, पलिया, रपटा आदि) एवं तटबंध की सड़कों की सुरक्षा संबंधी कार्यवाहीए विभिन्न चीनी मिलों पर वाहन प्रबन्धन की चर्चा, सकरे/जर्जर सेतुओं के संबंध में चर्चा, शहरी क्षेत्र में चौराहेध्तिराहों पर स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण एवं रोड साइड सुधार, सड़क सुरक्षा एवं गुड समेरिटन श्लाए के प्रचार.प्रसार एवं जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड तृतीय (पीडब्लूडी) अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में वर्ष 2024 में मात्र 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैए जिनका स्वामित्व निर्धारण किया जा चुका है। जिस पर सुधारात्मक कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

डीएम ने अफसरों की टीम संग तीन परिषदीय विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

लखीमपुरखीरी। परिषदीय विद्यालयों की शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तक एवं ड्रेस वितरण, आधार फीडिंग, विद्यालय परिसर की साफ सफाई का जायज़ा लेने के उद्देश्य से बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों की टीम संग ब्लॉक लखीमपुर के तहत संविलियन विद्यालय आधाचाट, पीएस चिमनी व यूपीएस पिपरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से डीपीआरओ विशाल सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, बीडीओ (सदर) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। डीएम ने शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में भी बच्चों से ही पूछताछ की। हेडमास्टर ने डीएम को विद्यालय में नामांकित बच्चों के सापेक्ष उपस्थित बताई। कक्षा में छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

सभी के विकाश से ही गांव का विकास संभवः मीणा

● संपूर्णता अभियान को लेकर पीरामल फाउंडेशन की ओर से बैठक आयोजित

फतेहपुर। किसी भी जेल का विकास तभी हो सकता है जब हम मिलकर किसी भी काम को आगे बढ़े सरकार की ओर से जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें पीरामल फाउंडेशन की अहम भूमिका है। जिले में चल रही संपूर्णता अभियान में भी फाउंडेशन की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। लगभग सभी पंचायत के प्रधान से भी सहयोग मिल रहा है। बातें मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा ने पीरामल फाउंडेशन द्वारा आयोजित संपूर्णता अभियान को लेकर हुई बैठक में कही। इस मौके पर 40 पंचायत के प्रधानों और सचिवों के साथ स्वास्थ्य पंचायत और उसके घटकों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी वीडियो प्रमोद सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, एडीपीआरओ, पिरामल से संजय सिंह, रोहिनी, स्मिता सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।

मीणा ने ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए गांव में आयुष्मान कार्ड सीएचएसएनडी और छोटे-छोटे उद्योगों को सभी सदस्यों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया उसके अलावा प्रधानों को आंगनबाड़ी गांव स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस और स्कूल का दौरा करने की सलाह दी ताकि सभी कार्यक्रमों का बेहतर कार्य सुनिश्चित हो सके। बैठक में सुजानपुर की प्रधान मिलता पटेल और टांडा के प्रधान ने अपनी सफलता की कहानियों को सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वीएचएसएनडी सत्र में 100 प्रतिशत परसेंट प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित की। बैठक में स्वास्थ्य पंचायत की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई ग्राम पंचायत के प्रधानों ने अपनी पंचायत में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने के विभिन्न उपायों पर अपने अनुभव साझा किया प्रधानों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन इकाइयों को शक्ति रूप से शामिल कर स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों टीकाकरण कार्यक्रम और पोषण सत्रों का सफल आयोजन किया है।

महिला ने यमराज के पंजे से बचाया अपना सुहाग

फतेहपुर। सुहाग बचाने के लिये एक महिला ने अपनी जान की परवाह किये बिना मौत के पंजे से अपने पति को वापस लाते हुए अपने ही सुहाग की रक्षा कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। किशनपुर थाना क्षेत्र के इटरौरा गांव निवासी पति पप्पू-पत्नी केसिया में मामूली बात को लेकर आपस मे झगड़ा हो गया। बात बिगड़ने पर पति हाई टेंशन की लाइन पर चढ़ गया। काफी देर मान मनव्वल के बाद भी जब पति टावर से नीचे नही उतरा तो पत्नी भी टावर पर चढ़ गई और पति को समझाकर आखिर नीचे उतरने में कामयाब हो गयी। पति और पत्नी के नीचे उतरने के बाद मौजूद गांव वालो के साथ साथ विद्युत व विद्युत विभाग के अफसरों ने भी राहत की सांस ली। महिला के जज़्बे की हर जगह जमकर सराहना हो रही है।

किशनपुर थाना क्षेत्र के संगोलीपुर मंडैयन गांव निवासी पप्पू निषाद अपनी ससुराल परान का डेरा मजरा लोधौरा गया था जहां किसी बात को लेकर पत्नी केसिया देवी से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद पप्पू ने जमकर शराब पी और नशे में इटरौरा बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और इन्सुलेटर पर बैठ गया। विद्युत लाईन चालू देखकर पत्नी केसिया पहले तो पति को समझाती रही इसी बीच गांव के और लोग भी आ गये और पप्पू को समझाने लगे। उधर पत्नी केसरिया भी रोती चिल्लाती मनुहार करती रही। काफी देर हाई वोल्टेज ड्रामा देख राहगीरो ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी काफी समझाती रही लेकिन पप्पू उतरने का नाम नही ले रहा था। शराब के नशे की हालात में पति को इंसुलेटर पर बैठा देखकर पत्नी केसिया से रहा नही गया और वह भी टावर पर चढ़ गई और पति पप्पू को समझाने लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ खागा सीओ बृजमोहन राय भी मौके पर पहुँचे व उतारने की कोशिश में लग गये।

मुख्यमंत्री से मिल विधायक ने अवैध भट्ठों के संचालन की करी शिकायत

● हिन्दू बहुल परिसीमित वॉर्डों में विकार्य कार्यों में अनदेखी का चेयरमैन पर लगाया आरोप

सीएम से मिल शिकायती पत्र सौंपती विधायक

संडीला (हरदोई)। क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र में चल रहे अवैध भट्ठों के संचालन और नगर पालिका परिषद द्वारा हिन्दू बहुल वॉर्डों में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से मिल लिखित शिकायत की है। क्षेत्रीय विधायक अलका अर्कवंशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय में 22 जुलाई को भेंट करके उनसे लिखित रूप से शिकायत की कि विधानसभा क्षेत्र संडीला में लगभग 100 से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं। इन ईंट भट्ठों के द्वारा पहले तो आसपास के इलाकों से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया गया जिससे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से वर्षा के मौसम में भीषण जलभराव के कारण तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैंए जिनके शिकार ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा इन भट्ठों की चिमनियां निर्धारित मानकों के अनुरूप ऊंचाई की नहीं हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है और लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा इन भट्ठों पर ईंट की सप्लाई लेकर अंधाधुंध भागती ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों के कारण क्षेत्र की सड़कों का भी कचूंमर निकाल दिया गया है। इनमें से कई सड़कें उन्होंनें स्वंय मुख्यमंत्री से मिल धनराशि जारी कराकर विभिन्न विभागों को दिलाईं थीए जिनसे इनका निर्माण हुआ था। उन्होंनें इन अवैध भट्ठों को तत्काल बंद कराने की मांग शिकायती पत्र में की। मुख्यमंत्री योगी से की दूसरी शिकायत में विधायक अलका अर्कवंशी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा परिसीमन वाले नवीन हिन्दू बहुल वॉर्डों में विकास कार्यों के प्रति पूर्ण उपेक्षा बरती जा रही हैए जबकि उनसे हर वर्ष मनमाना टैक्स वसूला जाता है। उन्होंनें नगर पालिका का दोबारा परिसीमन कराने और वॉर्डों में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

एएनएम के गलत इलाज से जच्चा-बच्चा की मौत एफआईआर दर्ज

फतेहपुर। सरकारी अस्पताल में सेवारत एएनएम के गलत इलाज के चलते जच्चा व बच्चा की मौत हो गई। प्रसूता के पति ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग किया है। नई तहसील के निकट स्थित पाल नगर निवासी कमलेश कुमार की पत्नी सोनी देवी 28 वर्ष 08 माह की गर्भवती थी। घर के पास स्थित श्रद्धा मेडिकल स्टोर पर दवाई ख़रीने के दौरान कोराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम गीता उत्तम के सम्पर्क में आने व प्रसव कराने की बात कही गयी। 22 जुलाई को प्रसूता सोनी देवी गीता उत्तम को दिखाने पहुंची जिस पर एएनएम गीता उत्तम ने प्रसूता की हालत नाजुक होने व तत्काल भर्ती करने को कहा। प्रसूता के पति कमलेश ने बताया कि एएनएम के कहने पर श्रद्धा मेडिकल स्टोर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 23 जुलाई को एएनएम ने आकर बताया कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है।

क्विक न्यूज

रिक्शाचालक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत

फर्रुखाबाद । बीती रात ट्रेन की चपेट में आनें से रिक्शा चालक की मौत हो गयी। पुलिस नें शव क पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहम्मदावाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लुकटपुरा निवासी 35 वर्षीय रंजीत उर्फरिंकू बीती रात ग्राम नगला अमृत के निकट पोल संख्या 1307/7 व 1307/8 के बीच ट्रेन की चपेट में आ गया। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो रंजीत का शव रेलवे के निकट पड़ा मिला। सुबह परिजनों को सूचना मिली। रंजीत फर्रुखाबाद में रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक की पत्नी अर्चना आदि परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। बीती रात रंजीत नशे की हालत में घर से विवाद करके निकला था। दारोगा चमन सिंह नें शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नाली में गिरने से शराबी की मौत

फर्रुखाबाद। शराबी की नाली में गिरने से मौत हो गयी। परिजनों में कोहराम मच गया। राजेपुरथाना क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर सोमवंशी 32 वर्षीय दुर्वेश पुत्र मंगली शराब पीने का आदी था। बीती रात वह अपनी ससुराल पलिया हरदोई से घर वापस लौटा था। उसने शराब के नशे में पड़ोसी सोनू पुत्र नेकराम से गाली-गलौज किया। जिसके बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पंहुची। वह समझाकर लौट आयी। मंगलवार सुबह से हो वह नशे में घूम रहा था। जिसके बाद नाली में गिरने से उसकी मौत हो गयी। मृतक की पत्नी रीना व माँ मुन्नी देवी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। दारोगा उदय सिंह बताया के तहरीर नहीं मिली है। सूचना आने पर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

चार ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन निश्चित, एक पर्चा खारिज

फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायत सदस्यों के उपचुनाव में नामाकंन पत्रों की जाँच में एक नामांकन पत्र निरस्त किया गया। चार के पर्चे बैध पाये गये। सहायक निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य रतनपुर पमारान के बार्ड संख्या चार सरस्वती, सबासी के वार्ड संख्या 6 से शिल्पी देवी, बार्ड संख्या 10 लज्जाराम, कमालुद्दीनपुर के वार्ड संख्या 5 से सुभद्रा के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए कमालुद्दीनपुर से मीना देवी पत्नी अमर सिंह के नाम निर्देशन पत्र में आधार कार्ड तथा फोटो संलग्न न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। अब प्रत्येक वार्ड से एक-एक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण इनका निर्विरोध निर्वाचित होना निश्चित हो गया है।

सर्प दंश से महिला की मौत

राठ (हमीरपुर)। बुधवार की तड़के कमरे में सो रही महिला को सर्प ने काट लिया। स्वजन इलाज के लिए पनवाड़ी तांत्रिक के पास झाड़.फूंक के लिए ले गए। हालत गंभीर होने पर सीएचसी पनवाड़ी ले गए। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। स्वजनों ने राठ में आकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। कोतवाली के मवई गांव निवासी जगतराम कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन कुशवाहा (38) बुधवार की सुबह करीब चार बजे कमरे में सो रही थी। तभी उसकी दाहिने हाथ की उंगली में सर्प ने काट लिया। जिसे आनन.फानन में झाड़.फूंक के लिए तांत्रिक के पास पनवाड़ी ले गए। जहां आराम न मिलने पर उसे सीएचसी पनवाड़ी ले। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया कि उसके पिता के पास 11 बीघा जमीन है। खेती व मजदूरी कर परिवार का भरण.पोषण करता है। मृतका अपने पीछे एक पुत्र दीपकए दो पुत्री दीक्षाए दीपिका छोड़ गई है।

करंट की चपेट में आकर वृद्ध की मौत

फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में पंखे में उतर रहे करंट की चपेट में आ जाने से 61 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर गांव निवासी रविकरन का पुत्र पिथरी लाल मंगलवार की रात लगभग नौ बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। तभी पंखा चालू करते समय वह करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के औरेई गांव निवासी प्रकाश नारायण की पत्नी सविता देवी अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौरइया माता मंदिर दर्शन के लिए गई थी। वापस लौटते समय जैसे ही वह बाइक से चलने लगी तभी तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को विच्छेदन गह भेज दिया।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

फतेहपुर। ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम ओती में मानसिक तनाव के चलते 40 वर्षीय युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। ओती गांव निवासी राम आसरे का पुत्र अशोक सिंह ने मंगलवार की देर शाम मानसिक तनाव के चलते घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

एक दर्जन ने अपहरण करके जरदोजी कारीगर को बुरी तरह पीटा, एक गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। जरदोजी कारीगर को घर से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेहरमी से पिटाई कर दी। पुलिस नें पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद खां निवासी सलीम पुत्र नसरुद्दीन जरदोजी कारीगर है। सलीम ने दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा है कि 21 जुलाई को अपने परिवार के साथ वह घर पर टीवी देख रहा था। उसी दौरान सुनार वाली गली निवासी जीतू यादव पुत्र राकेश, सूरज यादव, अन्नू तिवारी व टीना यादव निवासी निवासी कटरा बु अली खां, दीपू गुप्ता निवासी तिकोना मंडी, सिक्कू यादव बजरिया फिल्ड, अमित चौरसिया निवासी सुनार वाली गली व 8 लोग अज्ञात आ गये। पत्नी रौनक, भाभी अच्छी बेगम के साथ मारपीट की और सलीम का अपहरण करके आरोपी दीपू गुप्ता के घर तिकोना लेकर गये।

रेलवे क्रासिंग के ऊपर गाटर रखे जाने का काम शुरू हुआ

रूरा, कानपुर देहात। कडी मशक्कत व मैराथन प्रतीक्षा के बाद रूरा कस्बे की पश्चिमी क्रासिंग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज की दिल्ली-हावडा रेलवे लाइन के ऊपर भारी क्रेन मशीनों के माध्यम से गाटर रक्खे जाने का काम शुरू किया गया। रेलवे लाइन सीमा पर गाटर रक्खे जाने के दौरान चैयरमैन रामजी गुप्ता सहित भारी संख्या में स्थानीय व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

रूरा कस्बे में उत्तरी व दक्षिणी दिशा के मध्य में स्थित दिल्ली-हावडा व डीएफसी लाइनों पर करीब साढे चार वर्षों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम ने रेलवे सीमा के बाहर दोनों ओर करीब 90 फीसदी कार्य पूरा कर लिया है। रेलवे लाइनों के ऊपर रेलवे को निर्माण कार्य करना है। रेलवे लाइनों के ऊपर गाटर रक्खे जाने के लिये चार-पॉच दिन पूर्व ही भारी अत्याधुनिक क्रेन मशीनें आ गयी थी, वुद्धवार को रेलवे द्वारा ब्लाक मिलने पर गाटर रक्खे जाने का काम शुरू हुआ, वुद्धवार को दो गाटर रक्खे गये, शीघ्र ही शेष गाटर रख कर पुल के अवशेष कार्य कराये जायेगे, गाटर रक्खे जाने के बाद पश्चिमी केबिन क्रासिंग को भी आवागमन के लिये खोलने की शीघ्र सॅभावना बलवती हो चुकी है। गाटर रक्खे जाने के दौरान डीएफसी, रेलवे के अभियन्ता, अधिकारी सहित रूरा नगर पॅचायत के चैयरमैन रामजी गुप्ता, सभासद हिमॉशू गुप्ता, आशुतोष मिश्रा, सुरेश कुमार, नगर पॅचायतकर्मी राजेश रावत, सैनूर अहमद सहित भारी सॅख्या में स्थानीय व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

थाना अध्यक्ष समस्त पुलिस स्टाफ ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी को किया घायल

बांदा। प्रदेश के बांदा जनपद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बांदा के तत्वाधान में कल रात्रि तिंदवारी थाने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ लव जेहाद प्रकरण को लेकर बातचीत के दौरान तिंदवारी थाना अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी के साथ अभद्रता मारपीट की घटना के विरोध में प्रांतीय अधिकारियों की मौजूदगी में सैकड़ो की संख्या में मौजूद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान में एकत्रीकरण हुआ तत्पश्चात प्रांतीय पदाधिकारी के नेतृत्व में रामलीला मैदान प्रांगण से सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पैदल कूच किया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और अंदर घुसने को लेकर प्रशासन से गहमागहमी भी हुई तब अंदर प्रवेश मिला कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार नारेबाजी करते हुए तिंदवारी थाना अध्यक्ष पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया तदोपरांत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर तिंदवारी थाना अध्यक्ष सहित समस्त स्टाफको निलंबित करने तथा उनके विरोध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से तिंदवारी थाने के थाना अध्यक्ष सहित समस्त पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा उनके विरोध आपराधिक मुकदमा आज ही पंजीकृत करने का आश्वासन दिया गया है जांच 3 दिवस के अंदर पूरी कर निलंबन की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि हम लोग तब तक बांदा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे जब तक संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता और हमें थ्थ् की प्रति नहीं प्राप्त हो जाती साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि यदि हमारी जायज मांगों पर हिला हवाले की जाती है तो संगठन पुनरू तीन दिन बाद जोरदार आंदोलन को बाध्य होगा।

नाबालिग से झूठे बयान दर्ज कराने पर महिला एसआई व चौकी इंचार्ज पर दर्ज हुआ मुकदमा

अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान

कानपुर देहात। थाना सजेती क्षेत्र के एक मामले अनुसूचित जाति की एक 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व रेप के आरोपियों के साथ ही उन्हें बचाने में व रेप पीड़िता के जबरन झूठे बयान लिखने वाली थाना सजेती की महिला उप निरीक्षक व बीबीपुर चौकी इंचार्ज के खिलाफ न्यायालय ने मुकद्दमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की न्यायालय ने पीड़िता पक्ष की तरफ से धारा 156;3द्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र पर पारित किए है। यह जानकारी पीड़िता पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने दी।

अधिवक्ता जितेन्द्र चौहान ने बताया कि पीड़िता व उसके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप अनुसार लगभग 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपीगण आदर्श सचान उर्फ केशव शिव बदनएराजकिशोर व राजकुमार 23.4.2024 को रात उसके घर से जबरियां उठा कर अपहरण कर ले गए और उसके साथ आरोपी आदर्श सचान दो अज्ञात लोगों के साथ मिल जंगल में रेप करता रहा।जिसकी रिपोर्ट थाना सजेती में लिखने हेतु पीडिता के पिता ने प्रार्थना पत्र दिया किन्तु थाना पुलिस ने आरोपियों से मिल रिपोर्ट न लिख थाना सजेती की पूजा नाम की पुलिस सब इंस्पेक्टर व बीबीपुर चौकी इंचार्ज विनोद यादव ने पीड़िता को जातिसूचक गलियां देते व धमकाते हुए उसके जबरन झूठे बयान लिख बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर नारी निकेतन भिजवा दिया। पीड़िता ने नारी निकेतन से उसके माता पिता की सुपुर्दगी में आने पर उसके अपहरण के बाद की व उसके साथ लम्बे समय से हो रहे यौन उत्पीड़न की जानकारी अपने माता पिता को दी।जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखे जाने हेतु थानाध्यक्ष सजेती व पुलिस आयुक्त कानपुर को प्रार्थना पत्र देने के बवाजूद मुकदमा न लिखे जाने पर अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

विधायिका ने कार्यकर्ताओं का कोतवाली से कराया परिचय

● कोतवाली में बैठक लेकर सुनी भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्यायें

कार्यकर्ताओं को कोतवाल से परिचय करातीं विधायिका।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। बीते काफी समय से विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी समस्याओं को पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से न लेनें की शिकायत को संज्ञान में लेकर छिबरामऊ विधायिका अर्चना पाण्डेय नें स्थानीय कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुवे के साथ बैठक लेते हुये कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। साथ ही उनकी समस्यायें सुनी और निस्तारण के लिये निर्देर्शित किया। पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अनसुनी किये जानें से आहत भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां किया था। जिसपर बुधवार को स्थानीय कोतवाली परिसर में छिबरामऊ विधायिका अर्चना पाण्डेय नें प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुवे से परिचय कराया साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुननें व निस्तारण करनें के निर्देश दिये। वरिष्ठ भाजपा नेता रामकुमार पाठक, भाजपा नगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र कौशल, पूर्व नगर अध्यक्ष दीपू शर्मा, शिवमराज वर्मा, नीरज मिश्रा, डा. शरद दुवे, विजय दुवे, सुमित सक्सेना, भूरा कठेरिया, विकास गुप्ता, राकेश तिवारी, अनुराग गुप्ता, अजीत सिंह वर्मा, दीपक गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, संजीव गुप्ता उर्फ टीटू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गैर मान्यता प्राप्त मदरसो की जांच के नाम पर की खाना पूरी

● शासन के आदेश का नही किया गया पालन, मदरसों की वित्तीय सहायता कहा से प्राप्त होती है न दे सके संचालक कोई जवाब

मौदहा (हमीरपुर)। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी जिलाधिकारीयों को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिये थे जिस के सम्बन्ध में हमीरपुर मे जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है एसडीएम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लेकिन जब आज मौदहा क्षेत्र में जांच की गयी तो उस में उपजिलाधिकरी मौजूद नही रहे उनकी जगह नायब तहसीलदार व उनके साथ तीन सदस्यीय टीम के अतिरिक्त मदरसों के अध्यापक मौजूद रहे जिससे जांच प्रभावित होना स्वाभाविक है।

बुधवार को की गयी छह मदरसों की जांच मे कुछ छात्रों को छोड़कर ज्यादातर छात्रों का किसी सरकारी स्कूल में प्रवेश नही कराया गया जो शासन के आदेश की खुली अवहेलना है। आधा दर्जन मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित हैं, फैजाने बदरुल आलिया चिश्तिया निजामी मदरसा कम्हरिया, जामिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा बड़ा चौराहा कम्हरिया रोड, दाता गरीब नवाज मदरसा मकतब कमरिया रोड, फैजाने करीमिया अरबिया मदरसा चौधराना मौदहा, दावते इस्लामिया मदरसा कजियाना मौदहा व मदरसा माहिर उलूम काशीराम कॉलोनी छमोली रोड बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए गए किसी भी मदरसे में न कोई रिकार्ड है और न ही पंजीकरण और न ही बैंक खाता आदि जबकि मदरसों में देश विदेश से फंडिंग होती है जिसका कोई रिकार्ड मदरसा संचालक नही दिखा सके। मदरसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी कम्हरिया रोड मौदहा मौलाना सिद्दीक अमद एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी मौदहा हमीरपुर के अन्तर्गत अवैध रूप से चल रहा है उक्त संस्था का 1997 में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एंव चिटस झांसी में रजिस्टर्ड करायी गयी थी जिस का नवीनीकरण भी नही है। उक्त संस्था के नाम सन 1998 में रागौल में भूमी खरीदी गयी थी और 2010 में संस्था की भूमी पर लगभग 50 लाख रू की लागत की बिल्डिंग बनाई गयी।

पायनियर
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024

कानून की जानकारी न होना उसे तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता है : बंबई उच्च न्यायालय

भाषा। मुंबई

प्रतिबंधित सामग्री घोषित किए जा चुके एक रसायन का बिना जरूरी प्रमाणपत्र के कथित रूप से निर्यात करने को लेकर एक दवा कंपनी के निदेशक के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून की जानकारी नहीं होना उसे तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि इस अनभिज्ञता को बचाव के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए तो कानून प्रवर्तन मशीनरी ठप्प पड़ जाएगी। विवालविता फार्मास्यूटिकल्स नामक एक कंपनी के निदेशक अजय मेलवानी ने उच्च न्यायालय से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 2019 में दर्ज की गई प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया था।

अपनी अर्जी में आरोपी ने यह दावा करते हुए इस मामले को खारिज करने का अनुरोध किया कि 2018 में जारी की गई अधिसूचना में संबंधित रसायन को प्रतिबंधित सामग्री की सूची में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उनकी कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके निर्यात से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने 22 जुलाई को यह अर्जी खारिज कर दी और यह कहते हुए मामला रद्द करने से इनकार कर दिया कि यह स्थापित कानूनी रुख है कि कानून की जानकारी नहीं होना किसी आपराधिक आरोप के सिलसिले में बचाव नहीं हो सकता है। हालांकि इस पीठ ने मेलवानी के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में लगाए गए स्थगन को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, कानून की जानकारी नहीं होना उसे तोड़ने का कोई बहाना नहीं है, यह न्यायशास्त्र के आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि यदि अज्ञानता को एक बहाना मान लिया गया, तो किसी अपराध के आरोपी या उसमें शामिल व्यक्ति बस यह दावा कर अपनी जवाबदेही से बच निकलेगा कि उसे संबंधित कानून की जानकारी नहीं थी, भले ही वह कानून तोड़ने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ क्यों न हो। पीठ ने कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि दवा उत्पादों एवं संबंधित चीजों के आयात-निर्यात में लगी कंपनी को कारोबार से संबंधित नियमों एवं विनियमों की जानकारी नहीं है। मामला यह है कि रसायन बनाने वाली कंपनी सैम फाइन ओ केम लिमिटेड ने मेलवानी की कंपनी विवालविता के मार्फत बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के एक इतालवी कंपनी को 1000 किलोग्राम एन-फेनइथाइल-4 पिपेरिडोन (प्रतिबंधित सामग्री) का निर्यात किया था।

एसएनडीपी का न तो भगवाकरण होने दूंगा और न ही लाल रंग में रंगने दूंगा: वेल्लापल्ली नटेसन

तिरुवनंतपुरम। भाजपा पर श्री नारायण धर्म परिपालना (एसएनडीपी) के भगवाकरण की कोशिश करने का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद एसएनडीपी महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा है कि वह इसका न तो भगवाकरण होने देंगे और न ही इसे लाल रंग में रंगने देंगे। एसएनडीपी अच्छी खासी संख्या वाले इझावा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। एसएनडीपी योगम महासचिव ने माकपा पर पलटवार करते हुए यह आरोप भी लगाया कि वह आम आदमी को भूल गई जिसके कारण इस साल लोकसभा चुनाव में उसकी इतनी बड़ी हार हुई। नटेसन ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को तुष्ट करने के लिए माकपा जो कुछ कर सकती है, वह कर रही है और उसे तिहरा प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनके लिए पार्टी उससे भी बढ़कर कर रही है। उन्होंने दलील दी कि पार्टी के इन्हीं कृत्यों से उसके उन कार्यकर्ताओं के मन में निराशा की भावना घर कर गई जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया था। वह माकपा के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन की हाल की इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि भाजपा ने एसएनडीपी का राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया और उसका भगवाकरण करने का प्रयत्न किया। गोविंदन ने आरोप लगाया था, भाजपा की नीति जाति के आधार पर बांटने की है।

सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, एक जुलाई, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (एआर) में रिक्तियों की संख्या 10,45,751 की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 84,106 है।

राय ने कहा कि मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल परीक्षा में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। कांस्टेबल के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की खातिर कट-ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें (विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है)।

मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि बलों के आकार की तुलना में प्रभावी रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता। मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल पद पर जल्द भर्ती के लिए एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल, उप-निरीक्षक और सहायक कमांडेंट (सभी सामान्य ड्यूटी) के रैंक में भर्ती के लिए प्रत्एक को एक नोडल बल नामित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए, सभी सीएपीएफ और एआर को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैर-सामान्य ड्यूटी कैडरों में रिक्त पदों के लिए समयबद्ध तरीके से भर्ती करें और पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का समय पर आयोजन करें। जून 2022 में, सरकार ने सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है और उनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।

वाराणसी में गंगा प्रदूषण: अधिकरण ने उप्र के पर्यावरण सचिव को नोटिस जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीन साल के भीतर जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सचिव से जवाब मांगा है। अधिकरण वाराणसी में कई स्थानों पर गंगा नदी में सीवेज और घरेलू एवं अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने आठ जुलाई को एक नई रिपोर्ट दाखिल की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी नगर निगम के अंतर्गत आंशिक रूप से बंद किए गए तीन वे नाले हैं जो गंगा नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल गिराते हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य बंद नहीं किए गए नालों में चंदौली जिला पंचायत के अंतर्गत घुरहा नाला और नगर पालिका परिषद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली के अंतर्गत रेलवे नाले शामिल हैं।

रिपोर्ट के साथ संलग्न नालों की कुछ तस्वीरों पर गौर करते हुए अधिकरण ने कहा कि इनसे नालों की दयनीय स्थिति का पता चलता है, जहां वे गंगा नदी में अनुपचारित जलमल बहा रहे हैं। अधिकरण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तीन साल के भीतर सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं तथा निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव की है। इसने कहा, उच्चतम न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को उपरोक्त निर्णय पारित किया था और तीन वर्ष की समयसीमा समाप्त हो गई है। फिर भी कार्वाई पूरी नहीं हुई है।

नीतीश के फिर बिगड़े बोल: अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं होउ

भाषा। पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में अपना आपा खो बैठे और राजद की महिला विधायक रेखा देवी पर भड़कते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं होउ उनके बयान को लेकर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है... लोग जानते हैं कि उनके (नीतीश) मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने विधानसभा में जो कुछ किया है, वह सरासर एक महिला का अपमान है। जद(यू) नेताओं और राजग के अन्य गठबंधन सहयोगियों के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं का सम्मान केवल राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं में ही है। राजद विधायक रेखा देवी ने पीटीआई-भाषा से कहा, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में जो कुछ कहा, वह एक महिला का अपमान है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया... ए पहली बार नहीं हुआ है। हम आज यहां अपने नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद की वजह से हैं...नीतीश कुमार की वजह से नहीं। उन्होंने (नीतीश कुमार) ने आज (बुधवार) सदन में एक दलित विधायक का अपमान किया है। ऐसा लगता है कि उनका (मुख्यमंत्री) अपने दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं रहा।

बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करने के लिए उठे। उस समय राजद की मसौढी से विधायक रेखा देवी कुछ कह रही थीं। सत्तर वर्षीय मुख्यमंत्री ने रेखा देवी की ओर उंगलियां दिखाते हुए उंची आवाज में कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। इन लोगों (राजद) ने किसी महिला को आगे बढ़ाया था। क्या आपको पता है कि मेरे सत्ता संभालने के बाद ही बिहार में महिलाओं को उनका हक मिलना शुरू हुआ। 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। बोल रही हो, फालतू बात... इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। उनके इतना कहते ही सदन में हंगामा और बढ़ गया।

एक महिला विधायक से इस तरह मुखातिब होने का विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, अरे क्या हुआ... सुनोगे नहीं... हम तो सुनाएंगे और अगर नहीं सुनिएगा तो यह आपकी गलती है। बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री से आसन को संबोधित करने का अनुरोध किया तो नीतीश ने विपक्षी सदस्यों के बारे में कहा, आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक-एक चीज को लागू कर दिया है। हम चाह रहे थे कि यह लोग समझते एक-एक चीज को।

बाद में बिहार विधानसभा परिसर में राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कहा कि हम लोगों की मांग केवल आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर थी।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पता नहीं महिलाओं को क्या-क्या बोलने लगे। महिलाओं से उन्हें प्रेम या नफरत है, यह बात हमें समझ ही में नहीं आती। इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। अगर विजय कुमार चौधरी जी नहीं रोकते तो ना जाने वह और क्या-क्या बोल देते। इससे पहले भी नीतीश कुमार के कई बयानों को लेकर सियासी बवाल हो चुका है। पिछले साल बिहार विधानसभा में जातिगत गणना के दौरान हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला पुरूष के शारीरिक संबंधों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ए टिप्पणी आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं की बढ़ रही साक्षरता और प्रजनन दर के संदर्भ में की थी।

पाक से भारत लौटी गीता ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की आठवी कक्षा, सरकारी नौकरी मांगी

इंदौर (मध्यप्रदेश)। पड़ोसी देश पाकिस्तान से वर्ष 2015 में अपने देश भारत लौटी गीता ने आठवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। इसके बाद 33 साल की इस मूक-बधिर महिला ने सरकार से नौकरी की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं कक्षा की परीक्षा में गीता को 600 में से 411 अंक मिले हैं और उन्हें सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में विशेष योग्यता भी हासिल हुई है। इंदौर की गैर सरकारी संस्था आनंद सर्विस सोसायटी , पाकिस्तान से गीता की वापसी के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के जतन में जुटी है। संस्था के सचिव और सांकेतिक भाषा के जानकार ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया, अपने परीक्षा परिणाम से गीता बेहद उत्साहित हैं और अपने भविष्य की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। पुरोहित के मुताबिक वीडियो कॉल पर इशारों की जुबान में बातचीत के दौरान गीता ने उन्हें बताया कि वह सरकारी नौकरी करने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तय की गई है। इस लिहाज से गीता इस वर्ग की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की पात्र हो गई हैं। पुरोहित ने बताया कि गीता का असली नाम राधा है और वह इन दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अपनी मां मीना पांढरे के साथ रह रही हैं। गीता का परिवार गरीब है और वह आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए नौकरी करना चाहती हैं। पुरोहित ने कहा, गीता के मुताबिक अभी वह शादी नहीं करना चाहती। गीता बचपन में गलती से रेल में सवार होकर सीमा पार करने के कारण करीब 23 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गई थीं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गीता को लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेले बैठा हुआ पाया था। मूक-बधिर लड़की को पाकिस्तान की सामाजिक संस्था ईधी फाउंडेशनै की बिलकिस ईधी ने गोद लिया और अपने साथ कराची में रखा था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (अब दिवंगत) के विशेष प्रयासों के कारण गीता 26 अक्टूबर 2015 को स्वदेश लौट सकी थीं। इसके अगले ही दिन उन्हें इंदौर में एक गैर सरकारी संस्था के आवासीय परिसर भेज दिया गया था। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में अपने परिवार का पता चलने के बाद गीता इस राज्य में रह रही हैं।

संत कबीर नगर में डूबने से पांच लड़कियों की मौत

संत कबीर नगर। संत कबीर जिले में दो घटनाओं में पांच लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बुधवार को बताया कि पहली घटना बखिरा थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में हुई, जहां चार लड़कियां अर्चना (15), पायल (13), मीनाक्षी (17) और काजल (16) बखिरा झील में नाव से जा रही थीं। इसी दौरान नाव डगमगा कर अचानक पलट गई। अर्चना, पायल और मीनाक्षी की डूब कर मौत हो गई जबकि काजल को ग्रामीणों ने बचा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। दूसरी घटना थाना दुधरा क्षेत्र के खतियवा गांव की है जहां दो लड़कियां प्रमिला (18) और उसकी सगी बहन उर्मिला (15) की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें खेत जा रही थीं तभी रास्ते में उर्मिला का पैर फिसला और वह तालाब में गिर गई। प्रमिला ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह भी तालाब में गिर गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई। सिंह ने बताया कि पांचों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस साल 201 भारतीय हजयात्रियों की मौत हुई: मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि अधितर मौतें सांस संबंधी दिक्कत और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुईं। सजदा अहमद ने सवाल किया था कि इस बार हज में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई? रीजीजू ने कहा, 21 जुलाई 2024 तक, हज यात्रा-2024 के दौरान 201 भारतीय हजयात्रियों की मृत्यु हुई है। उनमें से अधिक मौतें सांस संबंधी कारणों और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुईं।

आरक्षित श्रेणी के 1195 उम्मीदवार पांच वर्षों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस नियुक्त किए गए

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में कहा पिछले पांच वर्षों में आरक्षित श्रेणियों के 1,195 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 233, 2019 में 231, 2020 में 223, 2021 में 250 और 2022 में 258 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में भर्ती प्रासंगिक नियमों के अनुसार यूपीएससी के माध्यम से की जाती है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है।

फैसला सार्वजनिक मंच से हटाने संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों में एक व्यक्ति के बरी होने के बाद मामले से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक मंचों से हटाने के उसके अधिकार से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हुआ। यह मुद्दा आरोपी के उस अधिकार से संबंधित है जिसमें सार्वजनिक मंचों से उसके नाम वाले फैसलों को हटाने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि फैसला हटाने के गंभीर प्रभाव होंगे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें उसने एक विधि पोर्टल को अपनी वेबसाइट से उस निर्णय को हटाने के लिए कहा था कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बरी हो गया है। सीजेआई ने कहा, फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और अदालतों की ओर से उन्हें हटाने के आदेश का गंभीर असर पड़ेगा।

पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि कोई व्यक्ति बरी हो गया है, उच्च न्यायालय उसे (विधि पोर्टल को) फैसला वापस लेने का निर्देश कैसे दे सकता है? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। उच्चतम न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ इंडिया कानून पोर्टल द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पोर्टल को अपनी वेबसाइट से फैसला हटाने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय ने कार्तिक थ्योडोर नामक व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला दिया था।

मुडा घोटाला को लेकर भाजपा कर्नाटक विधानसभा में दिन-रात धरना देगी

बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को घोषणा की कि वह मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में दिन-रात धरना देगी। भूखंड प्राप्त करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। विपक्ष को आज दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं। जब हम मुडा घोटाले में 4,000 करोड़ रुपए की लूट के बारे में स्थगन प्रस्ताव लाए, तो सरकार डर गई और चर्चा से भाग रही है। उन्होंने वित्त विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया है। यह सरकार डरपोक है, उनके पास सदन में मुडा के आरोपों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। यदि सरकार में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो उसे सदन में यह कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 14 भूखंड को कानूनी तरीके से लिया है और उनके समर्थकों ने भी ऐसा ही किया है। यह 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। दलितों की एक लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन लूट ली गई है.....हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई...सत्ता पक्ष के पक्ष में स्पीकर का आचरण निंदनीय है.. सत्ता पक्ष और स्पीकर द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के इस आचरण की निंदा करते हुए हम दिन-रात प्रदर्शन की घोषणा करते हैं। हमारे सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य इस सरकार के खिलाफ दिन-रात विरोध प्रदर्शन करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक बी वाई विजएंद्र ने भी विधानसभा और विधान परिषद में कहा, हम रातभर विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलितों के साथ अन्याय न हो, मुख्यमंत्री के परिवार को दी गई जमीन और 5,000 से अधिक अवैध रूप से आवंटित भूखंड को वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री पर मुडा घोटाले पर चर्चा का अवसर न देकर इस पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। यदि उनमें हिम्मत होती तो उन्हें स्पीकर से कहना चाहिए था कि चर्चा की अनुमति दें, चर्चा की अनुमति न देकर विपक्ष को दबाया जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा मुडा घोटाले को लेकर चर्चा कराए जाने पर जोर दिए जाने के शोरगुल के बीच, मुख्यमंत्री द्वारा पेश चार विधेयक 8573.72 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव संबंधी वित्त विधेयक, जीएसटी (संशोधन) विधेयक, सिंचाई (संशोधन) विधेयक और नगर पालिका एवं अन्य कानून विधेयक पारित कर दिए गए।

पेज 1 का शेष

बजट पर...

किए गए अंतरिम बजट या मंगलवार को संसद में पेश किए गए पूर्ण बजट में कई राज्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी योजनाएं राज्यों के लिए काम नहीं कर रही हैं। सीतारमण ने कहा कि वह कई अन्य राज्यों का हवाला दे सकती हैं जिन्हें बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, ताकि लोगों को यह आभास दिया जा सके कि 'ओह, हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है, यह केवल दो राज्यों को दिया गया है।' मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती दूंगी उनके द्वारा दिए गए सभी बजट भाषणों के लिए, क्या उन्होंने प्रत्येक बजट भाषण में देश के प्रत्येक राज्य का नाम लिया है? यह एक अपमानजनक आरोप है, जो स्वीकार्य नहीं है। जैसे ही विपक्षी दलों के सांसद सदन में लौटे, वित्त मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मंगलवार को बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ भी नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी को राज्य में लागू नहीं किया गया है। उनके बयान का टीएमसी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया, जिन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

केंद्र...

दिनों में जम्मू-कश्मीर में 28 आतंकी मारे गए हैं और दुर्भाग्य से कुछ सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के मुताबिक, 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में करीब 900 आतंकियों को मार गिराया है। 2004-2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए का शासन था, तब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुईं। राय ने कहा, 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी और इस साल 21 जुलाई को यह संख्या घटकर 2,259 हो गई। 2019 में, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। राय ने सदन को बताया कि 2004 से 2014 के बीच 2,829 नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई। 2014 के बाद से इस संख्या में 67 फीसदी की कमी आई है। इसके अलावा आतंकी घटनाओं में भी 69 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और सुरक्षा की पूरी गारंटी है।

बिहार...

वाला शब्द है, उन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चार साल तक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यहां तक कि संपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि ऐसी परीक्षा आयोजित करने की कुल लागत का एक हिस्सा दोषी सेवा प्रदाता से भी वसूला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक, 'लाखों युवा पुरुषों और महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी 'पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं होंगे।' गौरतलब है कि राज्य हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई 3.0) पेपर लीक मामले को लेकर खबरों में है। नया कानून केंद्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा लागू किए गए कड़े पेपर लीक विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि में भी आया है। वहीं बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। बिहार के ऊर्जा विभाग के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की ओर से यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। हालांकि, विपक्ष ने राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए बहिर्गमन किया।

शंभू बॉर्डर...

अन्य स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार पूरे साल राजमार्ग को बाधित नहीं रख सकती। मेहता ने कहा कि 500-600 से अधिक टैंक प्रदर्शन स्थल पर खड़े हैं जिन्हें , जिन्हें बख्तरबंद टैंकों के रूप में संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी तक आने की अनुमति दी गई तो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा आवागमन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अपनी अपील में नाकेबंदी के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से अवरोधक हटाने को कहा था और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। हरियाणा सरकार ने विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन की घोषणा किए जाने के बाद फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांग कर रहे हैं।

बाधा मुक्त...

ईटीसी और जीएनएसएस-आधारित ईटीसी दोनों एक साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर समर्पित जीएनएसएस लेन उपलब्ध होंगी, जिससे जीएनएसएस-आधारित ईटीसी का उपयोग करने वाले वाहनों को स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति मिलेगी। जैसे-जैसे जीएनएसएस आधारित ईटीसी अधिक व्यापक होता जाएगा, सभी लेन अंततः जीएनएसएस लेन में परिवर्तित हो जाएंगी। भारत में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही में सुविधा होगी और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को कई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जैसे बाधा रहित फ्री-फ्लो टोलिंग जिससे परेशानी मुक्त सवारी अनुभव और दूरी-आधारित टोलिंग होगी। जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से लीकेज को रोकने और टोल चोरों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में अधिक कुशल टोल संग्रह प्रणाली बनेगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) 'भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन' की देखभाल कर रही है। जीएनएसएस तकनीक नेविगेशन और पोजिशनिंग को बढ़ाती है, टोल संग्रह प्रणालियों को आधुनिक बनाने, निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने और हमारी सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमओआरटीएच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने, शासन को अधिक पारदर्शी बनाने और तेज सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

काठमांडू...

सौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी नेपाल में पांच पर्यटक स्थलों के लिए विमानों का संचालन करती है। उसके बेड़े में तीन बमबॉर्डियर सीआरजे-200 विमान शामिल हैं। हाल के वर्षों में खराब हवाई सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए नेपाल की आलोचना की गई है, लेकिन इन दुर्घटना की वजहों में मानवीय भूल के अलावा आंशिक रूप से अचानक मौसम परिवर्तन और दुर्गम चट्टानी इलाकों में स्थित हवाई पट्टियां भी शामिल हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन निकाय के अनुसार, अगस्त 1955 में पहली दुर्घटना के बाद से देश में हवाई दुर्घटनाओं में 914 लोग मारे गए हैं। पिछले साल जनवरी में, यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पांच भारतीयों सहित सभी 72 लोग मारे गए थे। दुर्घटना का कारण मानवीय भूल बताया गया।

आईएनएस...

नौसेना की ओर से कहा गया कि इस दुख की घड़ी में भारतीय नौसेना शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। इसने सोमवार को कहा था कि एक कनिष्ठ नाविक को छोड़कर सभी कर्मियों का पता लगा लिया गया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

आयकर की कम दर और छूट साथ-साथ नहीं चल सकते

भाषा। नई दिल्ली

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने बुधवार को कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है, जबकि छूट पुरानी व्यवस्था में ज्यादा है।

उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अच्छे वेतन वाली नौकरियां बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। सरकार का मकसद युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देकर बाजार के हिसाब से रोजगार के लिए तैयार करना है। बजट को लेकर सेठ ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है जबकि छूट पुरानी कर व्यवस्था में ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने और कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव किया। बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपए तक की कर बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुल करदाताओं में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई कर व्यवस्था में आ गए हैं, अन्य पुरानी कर व्यवस्था में है। यह पूछे जाने पर कि क्या पुरानी कर व्यवस्था को छोड़ने की तैयारी है, सेठ ने कहा, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। करदाताओं को जो व्यवस्था अनुकूल लगती है, वे उसे अपना सकते हैं। बजट में युवाओं के लिए किए गए उपायों के बारे में सचिव ने कहा, यह बजट रोजगार बढ़ाने वाला है। हमारा प्रयास है कि

युवाओं को प्रशिक्षण मिले। वे बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार हों और उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिले। यह पूछे जाने पर कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए बिना अच्छी नौकरियां सृजित होंगी, उन्होंने कहा, इन उपायों से यह सुनिश्चित करना है कि जो भी युवा एक स्तर तक पहुंच गया है, उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाए। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूंजी लाभ कर में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सेठ ने कहा, काफी समय से यह सोच रही है कि कर प्रणाली को सरल बनाया जाए। अलग-अलग तरह के निवेश हैं। कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं, कुछ इक्विटी शेयर में। उन्होंने कहा, इक्विटी में अलग कर, सूचीबद्ध संपत्ति में अलग और गैर सूचीबद्ध में अलग कर, यह ठीक नहीं है। कर को लेकर सभी संपत्ति वर्ग में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। बजट में उसे दुरुस्त किया गया है। साथ ही इंडेक्सेशन भी हटाया गया है। इससे पारदर्शिता भी आती है। बजट में प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, सूचीबद्ध शेयर, इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड और एक व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रतिभूतियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। निवेशकों को सालाना 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में एक लाख रुपए है। हालांकि, सूचीबद्ध बॉन्ड एवं डिबेंचर के मामले में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड एवं डिबेंचर के मामले में एलटीसीजी को वर्तमान में 20 प्रतिशत की एकसमान दर के मुकाबले लागू होने वाली स्लैब दरों के आधार पर लगाया जाएगा। इस मामले में भी एसटीसीजी दर अपरिवर्तित बनी हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में सेठ ने कहा, एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर) में वृद्धि एक संकेत है। नकदी और डेरिवेटिव (वायदा एवं विकल्प) बाजार में संतुलन के लिए यह कदम उठाया गया है...।

एनजीटी ने एम्स के पास कचरा फेंकने को लेकर केंद्र, एमसीडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पास कचरा फेंके जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया कि एम्स के गेट नंबर छह के सामने करीब 30 मीटर के क्षेत्र में कचरा फेंका जा रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हालिया आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि फेंका जा रहा कचरा एम्स के आसपास वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है और इस तरह खुले में कचरा डालने से आसपास के क्षेत्र में भारी वायु प्रदूषण हो रहा है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सचिव को पुनर्वास के लिए बैठक का निर्देश दिया

हल्द्वानी अतिक्रमण

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 से अधिक लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र और रेलवे के साथ बैठक करें। उच्चतम न्यायालय केंद्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसके पिछले साल पांच जनवरी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने हल्द्वानी में उस 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस पर रेलवे ने दावा जताया है।

याचिका में कहा गया कि रेलवे परिचालन को सुगम बनाने के लिए उक्त भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि पटरियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार पिछले साल मानसून के दौरान ढह गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्ईय पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह योजना बतानी होगी कि इन लोगों का कैसे और कहां पुनर्वास किया जाएगा। अदालत ने कहा कि, यह मानते हुए कि वे अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन वे

भी इंसान हैं और दशकों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने पक्के मकान भी बना लिए हैं, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। पीठ ने कहा, अदालतें निर्दई नहीं हो सकतीं और साथ ही लोगों को अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर सकतीं। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी देरी के राज्य सरकार को बुनियादी ढांचा विकसित करने और रेलवे लाइन के लिए आवश्यक जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया। उसने अतिक्रमण हटाने के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान करने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के शुरुआत में इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि रेलवे ने एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बेदखली का आदेश प्राप्त किया।

पीठ ने सवाल किया, क्या आपने अतिक्रमण करने वालों को कोई नोटिस जारी किया? आप जनहित याचिका की आड़ क्यों ले रहे हैं? अगर वहां पर अतिक्रमणकारी हैं तो रेलवे को अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करना चाहिए। रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत भी अतिक्रमकारियों के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। भाटी ने अदालत से क्रमिक आधार पर रोक हटाने या इसमें संशोधन करने का उनरोध करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे के कारण रेलवे की कई विस्तार योजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि मौजूदा समय में 1200 झोपड़ियों को हटाने की जरूरत है और स्पष्ट किया कि रेलवे के पास अतिक्रमकारियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भूमि पर अधिकार का दावा करने वालों को उचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही, उसने उत्तराखंड सरकार को ऐसी जगह का सुझाव देने का निर्देश दिया, जहां ऐसे प्रभाविता हटाए गए परिवारों का पुनर्वास किया जा सके। रेलवे के मुताबिक उक्त जमीन पर 4,365 अतिक्रमणकारी हैं जबकि जमीन पर काबिज लोगों का दावा है कि वे जमीन के मालिक हैं। विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों के लगभग 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को हल्द्वानी में रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि यह एक मानवीय मुद्दा है और 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता।

स्वदेशी जागरण मंच ने बजट को रोजगार-केंद्रित कृषि-समर्थक बताया

नई दिल्ली। (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्रीय बजट 2024-25 को रोजगार-केंद्रित, कृषि-समर्थक और कारोबार क्षेत्रों के अनुकूल बताते हुए बुधवार को सरकार से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपाय अपनाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जिसमें सरकार की नौ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। इसमें उत्पादकता, नौकरी, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधारों पर जोर दिया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने बयान में कहा, मंच बजट प्रस्तावों की सराहना करता है क्योंकि वे रोजगार-केंद्रित, कृषि-समर्थक और कारोबार खासकर एमएसएमई के अनुकूल हैं। इसके साथ ही एसजेएम ने उम्मीद जताई कि सरकार देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाएगी।

बजट में शिक्षित युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिए जाने की घोषणा पर एसजेएम ने कहा कि यदि इस योजना को ठीक से लागू किया जाता है तो यह युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकता है। एसजेएम के मुताबिक, बजट में निजी क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।

रियल एस्टेट पर एलटीसीजी में कमी से अधिकतर करदाताओं को पर्याप्त कर बचत होगी: आयकर

भाषा। नई दिल्ली

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) की दर में कटौती से अधिकतर करदाताओं को पर्याप्त कर बचत होने की उम्मीद है। बजट में दीर्घावधि तक रखी गई आवास संपत्तियों की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर की दरें कम कर दी गई हैं, लेकिन करदाताओं को मिलने वाला इंडेक्सेशन लाभ हटा दिया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एलटीसीजी को इंडेक्सेशन लाभ सहित 20 प्रतिशत से घटाकर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इंडेक्सेशन लाभों से तात्पर्य पूंजीगत लाभ कर की गणना के लिए सम्पति के मूल्य से मुद्रास्फीति को समायोजित करने की व्यवस्था समाप्त करना है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा, नाममात्र अचल संपत्ति रिटर्न आम तौर पर 12-16 प्रतिशत प्रति वर्ष के आसपास है, जो मुद्रास्फीति से बहुत अधिक है।

विभाग के अनुसार, मुद्रास्फीति के लिए इंडेक्सेशन चार से पांच प्रतिशत के आसपास है, जो संपत्ति को कितने समय के लिए अपने पास रखा गया उस अवधि पर निर्भर करता है। इसलिए, ऐसे करदाताओं में से अधिकतर को पर्याप्त कर बचत की उम्मीद है। अचल संपत्ति की अवधि के आधार पर लाभों की तुलना करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि बिना इंडेक्सेशन के नई कर दर अधिकतर मामलों में लाभकारी है। पांच वर्षों तक रखी गई संपत्ति के लिए नई व्यवस्था तब लाभकारी होगी जब संपत्ति का मूल्य 1.7 गुना या उससे अधिक बढ़ गया हो, जबकि 10 वर्षों तक रखी गई संपत्ति के लिए यह तब लाभकारी होगी जब मूल्य 2.4 गुना या उससे अधिक बढ़ गया हो। 2009-10 में खरीदी गई संपत्ति के लिए यदि मूल्य 4.9 गुना या उससे अधिक बढ़ गया है तो यह फायदेमंद होगा। आयकर विभाग ने कहा, उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि केवल उन क्षेत्रों में, जहां रिटर्न कम है (करीब 9-11 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम), वहां पहले की कर दर लाभदायक है, लेकिन रियल एस्टेट में इतना कम रिटर्न अवास्तविक तथा दुर्लभ है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में लाए गए बदलावों के अनुसार, सरकार ने 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली संपत्तियों पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ बरकरार रखा है। कर की दर में बदलाव 23 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं।

लोकसभा में भाजपा सांसद की टिप्पणी पर हंगामा

कांग्रेस ने माफी की मांग की

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की एक टिप्पणी पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया और सरकार तथा सदस्य से माफी मांगने को कहा। पश्चिम बंगाल के तामलुक से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सदन में बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए आर्थिक विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने टीका-टिप्पणी की तो गंगोपाध्याय ने कहा कि विद्वान सदस्यों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें सीखना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की जिस पर पलटवार करते हुए गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। तब कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय कहते सुने गए, न आप गांधी को जानते हैं, ना ही गोडसे को जानते हैं। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कहा कि आसन इस बारे में देखेगा और यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। गोगोई समेत विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदस्य ने यदि कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है तो आसन उस पर निर्णय लेगा, लेकिन गौरव गोगोई को भी बजट पर चर्चा के दौरान इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी।

नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का औचित्य नहीं: शिवकुमार

बेंगलुरु,। (भाषा) कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कांग्रेस सरकार द्वारा 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया और उसके हितों की रक्षा नहीं की गई। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा था कि राज्य की मांगों की केंद्रीय बजट में अनदेखी करने के खिलाफ यह फैसला लिया गया है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, जब कोई नीति ही नहीं है तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का क्या औचित्य है? कर्नाटक के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया है। राज्य को कोई

परियोजना नहीं मिली और उसके हितों की भी रक्षा नहीं की गई। हमने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इसके बजाय प्रदर्शन करेंगे। सिद्धरमैया ने कहा, कर्नाटक की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बजट में हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा, बैठक में शामिल हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों की चिंताओं की अनदेखी की। हमें नहीं लगता कि कर्नाटक वासियों की बात सुनी गई, लिहाजा नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, शासन और विकास को दलीय राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। भारत सरकार के शीर्ष जन नीति विचारक संस्था की बैठक का बहिष्कार करके मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 6.5 करोड़ कन्नड़ भाषियों और उनके द्वारा कांग्रेस को दिए गए जनादेश का अपमान किया है। अशोक ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कर्नाटक की जनता को आपसे थोड़ी हिम्मत, शासनकला में पारंगत होने और राज्य के हित को अपने कांग्रेस आलाकमान की तुच्छ राजनीति से ऊपर रखने की उम्मीद थी।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजएंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर खुद राज्य के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बजाय मुख्यमंत्री को उसमें शामिल होकर राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें राजनीति करने के बजाय बैठक में शामिल होना चाहिए था क्योंकि वह साढ़े छह करोड़ कन्नड़ भाषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बीच, वृहत बेंगलुरु शासन (जीबीए) विधेयक का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर शिवकुमार ने कहा, वे मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैंने केवल उसे सदन में रखा है। उन्हें इस पर विस्तृत बहस करने दें और उसके बाद फैसला किया जाएगा। बेंगलुरु का विस्तार अनियंत्रित तरीके से हो रहा है और यहां सुशासन की जरूरत है।

आयकर राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक: प्रधान आयकर आयुक्त

प्रयागराज (पीएनएस)। आयकर विभाग सरकार के लिए राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। क्योंकि कर ही राज्य को राजस्व प्रदान करते हैं। इसलिए यह किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा प्रशासन के किसी भी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। किसी अर्थव्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि कर प्रणाली कितनी अच्छी है। एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली किसी देश के आर्थिक विकास और उसकी समृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। यह बातें प्रधान आयकर आयुक्त आभा रानी सिंह ने आयकर दिवस पर कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1860 में आयकर के रूप में तीस लाख रुपए संग्रहित हुए थे। गत वर्ष सरकार द्वारा आयकर से संग्रहण का लक्ष्य रुपए 1945 लाख करोड़ रखा गया था जिसके सापेक्ष 19ण्58 लाख करोड़ का कर संग्रहण हुआ था। इलाहाबाद चार्ज का भी कर संग्रहण पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है। गत वर्ष जहां रुपए 818ण्22 करोड़ का शुद्ध कर संग्रहण हुआ था। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 326ण्72 करोड़ का कर संग्रहण आ चुका है। इसके लिए प्रधान आयकर आयुक्त ने प्रयागराज के करदाताओं को बधाई दी तथा अपेक्षा भी व्यक्त की है कि प्रयागराज के करदाता भविष्य में भी इसी तरीके देश के विकास में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे तथा देश के अर्थव्यवस्था की मजबूती में भागीदार बनेंगे। प्रधान आयकर आयुक्त आभा रानी सिंह ने बताया कि आज तकनीक का जमाना है। प्रत्येक करदाता पर विभाग की नजर है। आयकर के रूप में अर्जित राजस्व का उपयोग सरकार द्वारा जनता के लिए बेहतर सुविधाएं के लिए किया जाता है। सरकार की प्राप्तियों में 19 पैसा आयकर से तथा 17 पैसा निगम कर से आता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार की प्राप्तियों में आयकर विभाग एवं आयकर दाता का बड़ा योगदान रहता है। बुधवार को आयकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र शिव कुमार राय ने कहा कि 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 को आयकर लगाया गया था। उसे याद करते हुए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इस दौरान अपर आयकर आयुक्त ए के सिंह सहायक आयकर आयुक्त सौरभ गुहा आयकर अधिकारी सुब्रतो गुप्ता नन्दन कुमार सोनकर रवि कुमार मेहता आयकर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी योगेश्वर राय रविन्द्र कुमार गौर बृजेश कुमार भावेश कुमार रोहित सिंह एवं विजय कुमार आयकर निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव नन्हू लाल पाण्डेय भगवान प्रसाद पटेल राजेश कुमार गुप्ता पुरुषोत्तम शर्मा संजय कुमार मेहता अरूण कुमार शुक्ला यशवंत कुमार मौर्या सोनम केसरवानी श्रद्धा केसरवानी संगीता कुमारी कृष्णानन्द शर्मा यज्ञ नारायण सिंह सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे।

बजट में शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए धन का आवंटन : मनोहर लाल

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे जन-केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं एवं किसानों का ध्यान रखा है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि बजट में शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए भी धन स्वीकृत किया गया है।मनोहर लाल ने कहा, केंद्रीय बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान

दिया गया है। एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए आवंटन किया गया है। सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। सरकार के अनुसार, पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।शहरों के लिए बजटीय आवंटन पर मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई परियोजनाओं का प्रावधान किया है।

मेटा एआई हिंदी समेत सात नई भाषाओं में उपलब्ध: नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित कंपनी मेटा एआई अब हिंदी समेत सात नई भाषाओं में उपलब्ध है।कंपनी ने कहा कि यह कदम बहुभाषी खंड में मेटा के एआई असिस्टेंट की क्षमता बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता इन नई भाषाओं में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर मेटा एआई के साथ बातचीत कर सकेंगे।

राजकोट गेम जोन में फोम शीट, निर्माण सामग्री और वेल्डिंग के कारण निकली चिंगारी से भड़की आग

राजकोट। राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के कारण लगी थी, जिसने पूरी इमारत को तीन-चार मिनट के भीतर अपनी चपेट में ले लिया था। अपराध शाखा ने आरोपपत्र में यह बात कही है। इस साल मई के महीने में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एपी दवे की अदालत में बुधवार को गेम जोन के सह-मालिकों और राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के अधिकारियों सहित 15 आरोपियों के खिलाफ एक लाख से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया गया।

सैनिक पर हथियार से हमला, व्यक्ति गिरफ्तार

भाषा। लंदन

दक्षिण-पूर्वी ब्रिटेन में एक बैंक के पास मोटरसाइकिल सवार एक नकाबपोश हमलावर ने एक सैन्य अधिकारी पर धारदार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बुधवार को दी। केंट पुलिस ने बताया कि इस घटना के कुछ ही समय बाद 24 वर्षीय एक व्यक्ति को हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस हमले को हमलावर ने अकेले ही अंजाम दिया और यह हमला आतंकी कृत्य नहीं माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि क्या यह हमला संदिग्ध के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित था।

ब्रिटेन की सेना ने कहा कि पीड़ित अधिकारी की उम्र 40 साल के आसपास है और वह इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि अधिकारी की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर है। प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वह स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, हमारी सारी संवेदनाएं सैनिक, उसके परिवार और हमारे सशस्त्र बल समुदाय के साथ हैं, जो हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

रक्षा मंत्री जॉन हीली ने भी हमले को स्तब्ध करने वाला बताया। केंट पुलिस कहा कि मंगलवार शाम को लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गिलिंगम शहर में हमले की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। केंट पुलिस बल ने कहा कि अधिकारियों को मंगलवार शाम को लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गिलिंगम शहर में हमले की सूचना मिली थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्की मास्क पहने एक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया, उसने सैन्य अधिकारी पर हमला किया और फिर भाग गया। घटनास्थल के पास में रहने वाले एलेक्स रेनॉल्ड्स ने बताया कि जब वह अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि एक व्यक्ति सैन्य वर्दी में सड़क पर पड़ा हुआ है और उसमें कोई हरकत नहीं है।

रेनॉल्ड्स ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने हमलावर को बाइक पर तेजी से भागते देखा। पुलिस ने कहा कि आधे घंटे के भीतर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन की पुलिस संदिग्धों का नाम तब तक नहीं बताती जब तक उन्हें आरोपित नहीं किया जाता। पुलिस ने कहा कि जिस सड़क पर हमला हुआ, वह ब्रिटिश सेना के रॉयल स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग रेजिमेंट के मुख्यालय ब्रॉम्पटन बैरक के करीब है। बुधवार की सुबह, पुलिस की गाड़ियों और अपराध स्थल टेप से सड़क के दोनों छोर को घेर दिया गया।

सेना ने एक बयान में कहा, हमारी संवेदनाएं सैनिक और उनके परिवार के साथ हैं और हम अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान किया जाए। हम केंट पुलिस के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि यह समझा जा सके कि क्या हुआ और जांच का समर्थन किया जा सके। ब्रिटेन में सैनिकों पर हमले दुर्लभ हैं। 2013 में, अल-कायदा से प्रेरित दो लोगों ने लंदन की एक सड़क पर सैनिक ली रिग्बी की कार से कुचल कर और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। दोनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया भेजा गया कचरे से भरा गुब्बारा राष्ट्रपति कार्यालय परिसर में गिरा

सियोल। उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर कचरे से भरे गुब्बारे भेजे, जिसमें कम से कम एक गुब्बारा राष्ट्रपति कार्यालय परिसर में जा गिरा। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने एक बयान जारी कर कहा कि मध्य सियोल स्थित राष्ट्रपति कार्यालय परिसर पर गिरे गुब्बारे में कोई खतरनाक पदार्थ नहीं था और इसे कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया को अगली बार सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे गुब्बारों को मार गिराना होगा क्योंकि क्या पता उत्तर कोरिया भविष्य में इसमें खतरनाक वस्तुएं भेज दे। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को सियोल की ओर कचरे से भरे और गुब्बारे भेजे। सियोल के अधिकारियों ने भी बताया कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर संभवतः कचरे से भरे और गुब्बारे उड़ाए। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पर उत्तर कोरिया के संबंध में दुष्प्रचार संदेश प्रसारित किए थे। सुरक्षा सेवा ने यह बताने से इनकार कर दिया कि जब कचरे से भरा गुब्बारा परिसर में गिरा तो उस समय राष्ट्रपति यून सुक एओल कार्यालय में मौजूद थे या नहीं। यून के कार्यालय ने पहले कहा था कि बुधवार को उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से भेजे गए कचरे से भरे गुब्बारे बुधवार को सीमा पार करके सियोल के उत्तर में उड़ रहे थे। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

एससीओ में शामिल सभी सदस्य देशों ने पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया

भाषा। बीजिंग

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहले संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीन के जन सूचना मंत्रालय ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में हाल ही में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंटरैक्शन-2024 आयोजित किया गया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंगलवार को खबर दी कि यह अभ्यास पहली बार आयोजित किया गया और इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों की संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया।

ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक, आतंकवादी खतरे अक्सर दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं और दुनिया इससे अछूती नहीं है, इसलिए आतंकवाद विरोधी अभियानों में सदस्य देशों की क्षमताओं और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एससीओ संयुक्त अभ्यास का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। जन सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित एजेंसियों द्वारा संयुक्त अभ्यास के लिए एक नया मॉडल स्थापित किया गया है और इसने एससीओ सदस्य देशों के अधिकारियों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाया है।

मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के अहम खतरों की प्रतिक्रिया में, अभ्यास में आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियान शामिल थे। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में दिख रहा है कि सैनिक और पुलिस अधिकारी असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और दंगारोधी उपकरणों से लैस हैं। इस दौरान बख्तरबंद और अन्य वाहन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रोबोट कुत्तों को भी अभ्यास में तैनात किया गया था। एससीओ सदस्य देशों, एससीओ सचिवालय और एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों ने अभ्यास का अवलोकन किया। इस महीने की शुरुआत में बेलारूस आधिकारिक रूप से एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया, जिसमें पहले से ही चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

ताइवान ने तूफान से निपटने की तैयारी की, फिलीपीन में 13 की मौत

भाषा। ताइपे

शक्तिशाली तूफान की आशंका के मद्देनजर ताइवान ने बुधवार को पूरे द्वीप में कार्यालय, स्कूल और पर्यटन स्थल बंद कर दिए। इस तूफान के कारण फिलीपीन में मौसमी बारिश से हालात और खराब हो गए हैं और कम से कम 13 लोगों की जान चली गई जबकि छह लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान गेमी अभी ताइवान की मुख्य भूमि में दाखिल नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही ताइवान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा हो रही है। तूफान के बुधवार शाम को उत्तरी काउंटी यलान में सीधे दस्तक देने की आशंका है।

अशांत समुद्र के कारण मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर वापस बुला लिया गया, जबकि हवाई यात्री कई उड़ानों के रद्द होने के कारण तूफान आने से पहले विदेश जाने वाली उड़ानों को पकड़ने की जल्दी में दिखे। केंद्रीय मौसम प्रशासन ने बताया कि बुधवार सुबह तूफान ताइवान के पूर्व में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था तथा हवा की अधिकतम गति 183 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

राजधानी ताइपे में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन तेज हवाएं अभी तक नहीं चली थीं। फिलीपीन में इस तूफान को करीना नाम दिया गया है। गेमी हालांकि द्वीपसमूह में नहीं पहुंचा है लेकिन इसने मौसमी मानसून की बारिश को बढ़ा दिया। फिलीपीन की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बारिश के कारण पांच दिनों में कम से कम एक दर्जन भूस्खलन और बाढ़ आई, जिससे कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 600,000 लोग विस्थापित हो गए, जिनमें 35,000 लोग आपातकालीन आश्रयों में चले गए हैं।

बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रही है स्थिति

भाषा। ढाका

बांग्लादेश में एक सप्ताह से अधिक समय तक हिंसा के दौर के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। वहीं, बुधवार को देश में इंटरनेट उपयोग और कार्यालयों के समय को सीमित कर दिया गया। ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसने हिंसक रूप ले लिया था और इसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी। देश के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट शुरू नहीं किया गया, हालांकि अधिकारियों ने कर्फ्यू में सात घंटे की ढील दी, जिस दौरान राजधानी की सड़कों पर हजारों गाड़ियां नजर आईं।

बांग्लादेश में बुधवार को कार्यालय और बैंक कुछ घंटों के लिए खोले गए, जबकि अधिकारियों ने ढाका और दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव के कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल कर दिया। बंगाली भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र प्रथम आलो में बुधवार को प्रकाशित हुई खबर में बताया कि 16 जुलाई से अब तक हिंसा में कम से कम 197 लोग मारे गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस किसी भी आधिकारिक स्रोत से मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सका।

देश में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश में 15 जुलाई से आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी द्वारा छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन दिए जाने के बाद इसने हिंसक रूप ले लिया और पूरे देश में हिंसा फैल गई। ढाका में कई सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए।

बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने रविवार के अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं, पांच प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों तथा अन्य श्रेणियों के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएं। बांग्लादेश की सरकार ने बुधवार को परिपत्र जारी कर उच्चतम न्यायालय के सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार किए जाने वाले फैसले को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वह फैसले को लागू करने के लिए तैयार है।

डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा- सबकुछ ठीक हो जाएगा

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुक्रवार को होने वाली मुलाकाात का बेसब्री से इंतजार है और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए और भी अधिक तत्पर हूंउ इसके साथ ही उन्होंने अब्बास द्वारा उन्हें लिखा गया एक पत्र भी संलग्न किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान 13 जुलाई को हुए हमले के एक दिन बाद यह पत्र लिखा था। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 14 जुलाई को ट्रंप को लिखे पत्र में कहा, आप पर हुए हमले की खबर सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने इसका वीडियो भी देखा।

कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत नीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं: मुकेश अघी

वाशिंगटन। भारत केंद्रित अमेरिकी व्यापार एवं रणनीतिक पैरोकार समूह के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो उनके प्रशासन में भारत-अमेरिका नीति एवं रणनीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं लगता कि नीति में या रणनीति में कोई बदलाव होगा खासतौर पर भारत के संबंध में। राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनावी दौड़ से हटने के बाद कमला हैरिस तेजी से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के 50 घंटे से भी कम समय में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक धनराशि जुटाना उनके पक्ष में बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडन के चुनावी दौड़ से हटने से पार्टी में और पार्टी समर्थकों में ऊर्जा भर गई है। आप पिछले 24 घंटों पर नजर डालें तो 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का चंदा मिला है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े दानदाता अब फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी और उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। अघी ने कहा, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका-भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ? मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा....। चीन का उदय, चीन का आक्रामक रुख दुनिया के लिए खतरा है। यह अमेरिका के हितों के लिए खतरा है और भारत पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात से असहमति जताई कि हैरिस प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कमला हैरिस की आलोचनाएं हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वह एक समझदार महिला हैं, वह बुद्धिमान महिला हैं। उनके पास अनुभव है। उनके पास एक अच्छी टीम होगी जो सही मार्गदर्शन करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीति में या रणनीति में कोई बदलाव होगा, खासतौर पर भारत के संबंध में।

कमला हैरिस नेतन्याहू से मुलाकात में कहेंगी कि युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है: हैरिस के सहयोगी

वाशिंगटन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एक सहयोगी ने बताया कि हैरिस इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगी और उनसे कहेंगी कि युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है। हालांकि, वह नेतन्याहू द्वारा संबोधित किए जाने वाले अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हैरिस के एक सहयोगी ने पीटीआई से कहा, उपराष्ट्रपति इस सप्ताह व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर रही हैं। यह बैठक राष्ट्रपति बाइडन की नियोजित बैठक से अलग होगी। उपराष्ट्रपति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई को इंडियानापोलिस जा रही हैं और वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कांग्रेस के संयुक्त सत्र के पहले से निर्धारित संबोधन में भाग नहीं ले पाएंगी। हैरिस के सहयोगी ने कहा, अनुमान है कि उपराष्ट्रपति नेतन्याहू से कहेंगी कि युद्ध को इस तरह से समाप्त करने का समय आ गया है कि इजराइल सुरक्षित हो, सभी बंधक रिहा हों, गाजा में फलस्तीनी नागरिकों की पीड़ा का अंत हो और फलस्तीन के लोग सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का आनंद ले सकें। नेतन्याहू का बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। यह अमेरिकी संसद में नेतन्याहू का चौथा संबोधन है, जो किसी भी विदेशी नेता द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में सबसे अधिक बार दिया जाने वाला संबोधन होगा। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता आम तौर पर उपराष्ट्रपति करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस संबोधन में भाग न लेने के लिए हैरिस की आलोचना की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपने पहले सप्ताह में हैरिस इजराइली प्रधानमंत्री की वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के मद्देनजर अमेरिकी विदेश नीति में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा विभाजनकारी मुद्दे का सामना करेंगी।

चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों में पानी के अणु मिले

बीजिंग। चांग ई-5 मिशन द्वारा चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणु मिले हैं। यह जानकारी चाइनीज एकेडमी आफ साइंसेज ने दी। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार, यह अनुसंधान बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और सीएएस के भौतिकी संस्थान तथा अन्य घरेलू अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अनुसंधान रिपोर्ट 16 जुलाई को पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई। सीएएस ने कहा कि 2020 में चांग ई-5 मिशन द्वारा लाए गए चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों के आधार पर चीनी वैज्ञानिकों ने आणविक जल से युक्त एक जलयोजित खनिज पाया है। 2009 में, भारत के चंद्रयान-। अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं के रूप में जलयोजित खनिजों के संकेतों का पता लगाया था। इसके उपकरणों में नासा का मून मिनरलॉजी मैपर (एम3) भी शामिल था जो एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसने चंद्रमा पर खनिजों में पानी की खोज की पुष्टि करने में मदद की।

रूस से युद्ध समाप्त की वार्ता के लिए चीन के साथ साझा आधार तलाश रहे यूक्रेन के विदेशमंत्री

भाषा। बीजिंग

यूक्रेन के विदेशमंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अपने चीनी समकक्ष के साथ इस सप्ताह की बातचीत में साझा आधार तलाश रहे हैं। कुलेबा ने दक्षिणी चीन के प्रमुख वाणिज्यिक एवं विनिर्माण केंद्र ग्वांगझोउ में चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देश के विदेशमंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। यूक्रेन और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कुलेबा ने शुरुआती टिप्पणी की, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यूक्रेन में शांति चीन के सामरिक हित में है और शांति के लिए वैश्विक ताकत के रूप में चीन की भूमिका अहम है।

चीन के रूस के साथ मजबूत संबंध हैं और उसने दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया है। चीन के इस रुख से न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका भी असहमत है, जो किसी भी समझौते के आधार के रूप में रूस की यूक्रेन से वापसी की मांग कर रहे हैं। चीन पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति वार्ता में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि रूस को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

कुलेबा चीनी अधिकारियों को अगली शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। यह शांति वार्ता नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने की संभावना है। कुलेबा के दौरे से संकेत मिलता है कि यूक्रेन के पक्ष में कोई भी शांति समझौता चीन को भरोसे में लिए बिना संभव नहीं हो सकता। चीन के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगात्मक संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि को रेखांकित करते हुए वांग ने कहा कि जटिल और लगातार बदल रही अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के बावजूद दोनों देशों के संबंध सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुलेबा मंगलवार को चीन पहुंचे और उनके शुक्रवार को यहां से रवाना होने की संभावना है।

स्विट्जरलैंड में संघर्ष विराम वार्ता में शिरकत करेंगे सूडान के अर्धसैनिक बल प्रमुख

जेनेवा। सूडान के अर्धसैनिक बल प्रमुख ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा स्विट्जरलैंड में अगले महीने आयोजित संघर्ष विराम वार्ता में भाग लेने की घोषणा की है। सूडान की सेना से लड़ रही रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागालो ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर कहा कि यह वार्ता सूडान में शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। साथ ही उम्मीद जताई कि न्याय, समानता और संघीय शासन पर आधारित एक नया देश बनाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ देश भर में पूर्ण युद्धविराम हासिल करने और सभी जरूरतमंदों तक मानवीय पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को साझा किया है।

वार्ता 14 अगस्त को स्विट्जरलैंड में एक अज्ञात स्थान पर शुरू होने की उम्मीद है। अभी तत्काल सार्वजनिक तौर पर यह संकेत नहीं मिला है कि सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्दल फतेह बुरहान या सेना का कोई अन्य शीर्ष अधिकारी भी शिरकत करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वार्ता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच पिछले साल के अंत में सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। इसमें कहा गया है कि डागालो की सेना का समर्थन करने वाला अफ्रीकी संघ, सूडान का पड़ोसी मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, स्विट्जरलैंड में वार्ता का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी हिंसा को समाप्त करना, जरूरतमंद सभी लोगों तक मानवीय पहुंच को मजबूत करना और किसी भी समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी और सत्यापन तंत्र विकसित करना है। 2023 के मध्य में राजधानी खार्तूम में सूडान के सैन्य और अर्धसैनिक प्रमुखों के बीच तनाव शुरू होने और इसके दारफुर समेत अन्य क्षेत्रों में फैलने के बाद से सूडान संघर्ष में फंस गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 14 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और 33 हजार घायल हुए हैं। अधिकारिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।

इथियोपिया में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हुई, कई लापता

अदीस अबाबा। इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 229 लोगों की मौत हो गई है जिनमें से कई ऐसे लोग शामिल हैं जो पीड़ितों को बचाने की कोशिश में जुटे थे। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इसे भयानक क्षति बताया है। एक स्थानीय प्रशासक दागमावी आएले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी प्रांत में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। मलबे से कम से कम पांच लोगों को जीवित निकाला गया है।

गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबेयनेह ने बताया कि सोमवार को सबसे पहले 55 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी लेकिन बाद में मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इलाके में खोज अभियान जारी है। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक बयान में कहा कि उसे इस आपदा पर दुख है। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने फेसबुक पर एक बयान में कहा कि वह इस भयानक क्षति से काफी दुखी हैं। अहमद के बयान में कहा गया है कि खोज एवं बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए संघीय आपदा रोकथाम कार्य बल को तैनात किया गया है। अभी यह पता नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। गोफा में एक अन्य अधिकारी मार्कोस मेलीसे ने बताया कि ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए। उस समय बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। अन्य लोगों को बचाने की कोशिश करते वक्त भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से कई लापता हैं। कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट कर रो रहे हैं। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

ब्रिटेन के कारोबारियों, निवेशकों ने भारत के आम बजट को उत्साहजनक बताया

लंदन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट को ब्रिटेन के कारोबारी और निवेशक समुदाय ने उत्साहजनक करार दिया है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने और एंजल कर के संबंध में लिए गए निर्णय को सकारात्मक कदम करार दिया है। स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सीतारमण ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। भारत के राजकोषीय घाटे में कमी आने की घोषणा, जो इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, उन पहलुओं में से एक है जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। ग्रांट थॉर्नटन में साझेदार और दक्षिण एशिया के प्रमुख अनुज चंदे ने कहा, कुल मिलाकर, मैं कहूंगा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बजट है। कुछ बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, खास तौर पर बुनियादी ढांचे और कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के मामले में। यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल के सीईओ रिचर्ड मैक्कलम ने कहा, कॉर्पोरेट कर में कटौती ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के संबंध में एक स्वागत योग्य कदम है।

पेरिस आई ऑस्ट्रेलियाई महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की जांच कर रहे अभियोजक

भाषा। पेरिस

पेरिस घूमने आई एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले की अभियोजक जांच कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पेरिस में 2024 ओलंपिक की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पेरिस लोक अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में बताया कि 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला ने फ्रांस की राजधानी में अधिकारियों को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। बयान के अनुसार अभियोजक इस मामले की सामूहिक दुष्कर्म के तौर पर जांच कर रहे हैं।

फ्रांस की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पांच लोगों ने महिला से दुष्कर्म किया। बयान में पीड़िता के नाम का जिक्र नहीं किया गया लेकिन बताया गया है कि कथित घटना शुक्रवार 19 जुलाई देर रात को हुई। बयान के मुताबिक, महिला ने पेरिस के एक रेस्तरां में शरण ली, जहां अग्निशमनकर्मियों ने उसे आपात सहायता मुहैया कराई और बाद में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया।

ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि फ्रांस की राजधानी में उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को पेरिस में ऑस्ट्रिलयाई दूतावास ने राजनयिक मदद की पेशकश की है। बयान में कहा गया, हम जानते हैं कि यह एक बेहद दर्दनाक अनुभव है और हम सहायता मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पीड़िता की निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की खबर के मुताबिक, पीड़िता ने शुरू में तत्काल ऑस्ट्रेलिया लौटने की योजना बनाई थी लेकिन बाद में उसने फ्रांस में रुकने का फैसला किया। निजता कारणों से खबर में और अन्य जानकारियां नहीं उपलब्ध कराई गई हैं।

इमरान खान का पोलीग्राफ जांच कराने से इनकार

लाहौर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल नौ मई को हुए अप्रत्याशित उपद्रव से जुड़े दर्जनों मामलों की लाहौर पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तहत पोलीग्राफ (एक प्रकार की झूठ पकड़ने वाली जांच) और आवाज मिलान परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। बारह सदस्ईय फोरेंसिक टीम क्रिकेटर से नेता बने 71 वर्षीय इमरान खान का पोलीग्राफ परीक्षण करने मंगलवार को अडियाला जेल पहुंची थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को गिरफ्तार किया था तब नौ मई को देशभर में उपद्रव हुए थे। इमरान खान 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और वह पिछले साल अगस्त से जेल में हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि एक पुलिस उपाधीक्षक की अगुवाई में लाहौर पुलिस का एक दल (पोलीग्राफ और आवाज मिलान) परीक्षण करने आडियाला जेल पहुंचा था। इस अखबार के अनुसार उनके साथ पंजाब अपराध जांच विज्ञान एजेंसी (पीएफएसए) के विशेषज्ञ भी थे। इन पीएफएसए विशेषज्ञों को पूर्व प्रधानमंत्री का पोलीग्राफ, आवाज मिलान परीक्षण और फोटोग्रेमेट्री परीक्षण करने थे।

नेशन अखबार की खबर है कि पीटीआई संस्थापक ने 15 मिनट तक पुलिस के प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन उन्होंने पंजाब अपराध जांच विज्ञान एजेंसी के दल के पोलीग्राफ एवं अन्य परीक्षण से गुजरने इनकार कर दिया। इस अखबार के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा उनकी जांच की जा रही है और पिछली जांच के पूरा हो जाने के बाद ही वह पुलिस को समय देंगे। डॉन अखबार की खबर है कि पुलिस अधिकारियों ने उससे नौ मई के उपद्रव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की। नौ मई को इस उपद्रव के दौरान लाहौर कोर कमांडर के आवास, सैन्य प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। इस अखबार के मुताबिक जेल से लौटने के बाद, पुलिस टीम और पीएफएसए विशेषज्ञों ने लाहौर के डीआईजी (जांच) जीशान असगर को खान के असहयोग के बारे में बताया। अब अगले दौरे की रणनीति बनाने के लिए अभियोजन विभाग से परामर्श लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी।

भारतीय तीरंदाजों का लक्ष्य: ओलंपिक में पहला पदक जीतना

भाषा। पेरिस

स्थान भी अलग होगा और वर्ष भी और एक नया ओलंपिक होगा लेकिन भारतीय तीरंदाजों का लक्ष्य वही पुराना होगा, ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतना।भारत ने ओलंपिक में तीरंदाजी में पहली बार 1988 में भाग लिया था। तब से भारतीय तीरंदाज लगभग हर ओलंपिक खेल में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन अभी तक पोडियम तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज गुरुवार को लेस इनवैलिड्स गार्डन में क्वालीफिकेशन राउंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लंदन ओलंपिक 2012 के बाद यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम में सभी छह खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया जिसका मतलब है कि इस बार भारतीय तीरंदाज पांच स्पर्धाओं में भाग लेंगे।

अनुभवी तरुणदीप राय और दीपिका कुमारी अपने चौथे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। उनकी अगुवाई में टीम को पसंदीदा ड्रॉ हासिल करने के लिए क्वालिफिकेशन में कम से कम शीर्ष 10 में जगह बनानी होगी। प्रत्एक तीरंदाज 72 तीर चलाएगा और क्वालिफिकेशन दौर में भाग ले रहे 53 देश के 128 खिलाड़ियों के स्कोर के आधार पर रविवार से शुरू होने वाली मुख्य नॉकआउट प्रतियोगिता के लिए वरीयता तय की जाएगी। भारतीय टीम के लिए क्वालीफिकेशन दौर महत्वपूर्ण होगा जो अक्सर निचली वरीयता हासिल करती रही हैं और ऐसे में नॉकआउट चरण में उन्हें दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम का सामना करना पड़ता है। तोक्यो ओलंपिक में भारत के सभी पुरुष तीरंदाज शीर्ष 30 में जगह नहीं

बना पाए थे जिससे भारतीय टीम को नौवीं वरीयता मिली थी। भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज दीपिका ने नौवां स्थान हासिल किया था। भारत को तब अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया से हार का सामना करना पड़ा था। भारत को पुरुष टीम से काफी उम्मीद है जिसने इस साल शंघाई में विश्व कप के फाइनल में कोरिया को हराकर इतिहास रचा था। भारतीय टीम में राय और पिछले ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रवीण जाधव के रूप में अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं जबकि युवा खिलाड़ी धीरज बोम्मादेवरा एक महीने पहले अंताल्या विश्व कप में तोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता इटली के मौरो नेस्पोली को हराकर कांस्य पदक जीत कर उत्साह से लबरेज होंगे। महिला वर्ग में सभी की निगाहें दीपिका पर टिकी रहेंगी। उन्होंने मां बनने के 16 महीने के अंदर शंघाई में विश्व कप के पहले चरण में रजत पदक जीत कर शानदार वापसी की थी। महिला टीम में उनके साथ देने के लिए अंकिता भक्त और भजन कौर हैं। इन दोनों का यह पहला ओलंपिक होगा लेकिन वह वर्तमान ओलंपिक चक्र में भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। धीरज और दीपिका अगर रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहते हैं तो फिर रिकर्व मिश्रित टीम में उनसे पदक कीराउंड में शीर्ष पर रहते हैं तो फिर रिकर्व मिश्रित टीम में उनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय तीरंदाज ओलंपिक में अभी तक क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भारत तीरंदाजी में केवल सिडनी ओलंपिक 2000 में क्वालीफाई नहीं कर पाया था। इसके अलावा उसने सभी ओलंपिक खेलों में भाग लिया लेकिन अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक में पुरुष टीम का फाइनल सोमवार को जबकि व्यक्तिगत एलिमिनेशन मंगलवार को शुरू होगा। मिश्रित टीम का फाइनल अगले शुक्रवार को तथा उसी सप्ताहांत में महिला और व्यक्तिगत फाइनल होंगे।

विरोधी से डरना नहीं है, बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो

हाई जंपर सर्वेश ने नीरज से सीखा

भाषा। नई दिल्ली

गांव में चारे के मैट पर अभ्यास से पेरिस ओलंपिक तक का सफर तय करने वाले हाई जंपर सर्वेश कुशारे को अपनी तैयारियों और भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा से मिले इस मूलमंत्र पर यकीन है कि प्रतिद्वंद्वियों की ख्याति से डरे बिना बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो। कुशारे ओलंपिक उंची कूद के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अभ्यास के दौरान 2 . 30 मीटर का आंकड़ा पार कर रहे कुशारे को अपनी कड़ी मेहनत और तोक्यो ओलंपिक में भालाफेंक में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में भारत का खाता खोलने वाले नीरज की सलाह पर पूरा यकीन है।ओलंपिक में उंचे कद और भारी डील डौल वाले प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार पांच फुट नौ इंच के कुशारे ने पोलैंड के स्पाला से भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा , मेरा बस कद ही छोटा है लेकिन हम भी भीतर से बहुत मजबूत हैं। प्रतिद्वंद्वी की कद काठी देखकर कोई डर नहीं लगता। सही समय पर शीर्ष फॉर्म में रहना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के नाशिक से कुछ किलोमीटर दूर देवरगांव के रहने वाले 29 वर्ष के इस एथलीट ने कहा , अभी तो काफी समय से नीरज भाई से मुलाकात नहीं हुई है लेकिन जब पिछली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग पर फोकस करो और विरोधी खिलाड़ियों की ख्याति से डरना नहीं है। वह हमेशा टिप्स देते रहते हैं। उन्होंने कहा , हमारे आदर्श नीरज चोपड़ा ही हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक जीतकर हमारे भीतर भी आत्मविश्वास भरा। हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं और देश का मान बढाना चाहते हैं।

पंचकूला में जून में अंतर प्रांत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 2 . 25 मीटर की रिकॉर्ड कूद के साथ स्वर्ण जीतने वाले कुशारे ने क्वालीफिकेशन प्रक्रिया में 23वां स्थान हासिल करके पेरिस का टिकट कटाया। उन्होंने कहा , जून से पहले मेरी रैंकिंग 36 चली गई थी क्योंकि मई में जब पूरी दुनिया में स्पर्धाएं चल रही थी, मैं नहीं खेल सका था। मुझे डर लग रहा था कि ओलंपिक खेल सकूंगा कि नहीं। मैं काफी दबाव में आ गया था लेकिन फिर मलेशिया, कजाखस्तान और पंचकूला में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके क्वालीफाई किया। उन्होंने कहा , टखने की चोट के कारण बहुत दिक्कतें आई थी लेकिन अब लगातार अच्छा अभ्यास करके मेरा आत्मविश्वास बढा है। अभी फोकस क्वालीफिकेशन दौर पर है जो सात अगस्त को सुबह दस बजे होगा। पहला लक्ष्य फाइनल में जगह बनाने का है। उसके बाद की प्लानिंग बाद में करूंगा। स्पाला में अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच तैयारी कर रहे कुशारे ने जब खेलना शुरू किया तो गाय के चारे को मैट के रूप में इस्तेमाल करते थे।उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा , हमारे गांव में उंची कूद का मैट नहीं था तो गाय के लिए जो मक्के का चारा इकट्ठा होता था, उसका मैट बनाया जाता था। उसका एक ही पीस लैंडिंग एरिया की तरह बनाया था और हम उस पर अभ्यास करते थे। उन्होंने बताया, स्कूल के पीटी टीचर आर डब्ल्यू जाधव सर के मार्गदर्शन में खेलना शुरू किया। फिर सैन्य खेल संस्थान में गया और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट (ओजीक्यू) से भी सहयोग मिला जिन्होंने अमेरिका में अभ्यास के लिए भेजा।

जुबिन हमारी मदद कर रहे, श्रीलंका को भारतीय खिलाड़ियों के संन्यास का फायदा उठाना चाहिए

पाल्लेकल (भाषा)। श्रीलंका के अंतरिम मुख्य कोच सनथ जयसूर्या ने बुधवार को खुलासा किया कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक जुबिन भरूचा ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 श्रृंखला की तैयारी में उनके बल्लेबाजों की मदद की है और उन्हें उम्मीद है कि टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों के संन्यास का फायदा उठाएगी। रोहित, कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पिछले महीने भारत की विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था। श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला 27 जुलाई से यहां शुरू होगी। जयसूर्या ने खुलासा किया कि श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों के लंका प्रीमियर (एलपीएल) लीग से जुड़ा होने के बावजूद भरूचा के साथ छह दिन के शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होंने कहा, हमने एलपीएल के तुरंत बाद सत्र शुरू किया। अधिकतर खिलाड़ी

एलपीएल में खेल रहे थे इसलिए वे क्रिकेट में व्यस्त थे और हम चाहते थे कि वे अधिक से अधिक क्रिकेट खेलें। जयसूर्या ने कहा, हम राजस्थान रॉयल्स से जुबिन को लाए और हमने लगभग छह दिन उनके साथ काम किया। एलपीएल में खेलने बाद अन्य क्रिकेटर भी उनके साथ जुड़े। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने सीख लिया है कि आप (प्रबंधन) अभ्यास और तकनीक के मामले में उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, तैयारी अच्छी थी और टी20 शुरू होने से पहले कैंडी में हमारे पास दो दिन और हैं। जयसूर्या ने कहा कि भरूचा के साथ सत्र काफी गहन रहे और खिलाड़ियों ने उनसे काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए नई तकनीक, नए दृष्टिकोण और नए शॉट मारना सीखना महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी बन सकें। भारत को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए सूर्यकुमार यादव के रूप में नया कप्तान भी मिला है और जयसूर्या ने अपनी टीम से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने को कहा। एसोसिएटेड प्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयसूर्या के हवाले से कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा और उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसे देखते हुए हम सभी जानते हैं कि वे और जडेजा किस स्थान पर हैं।

भारतीय महिला टीम का सफलता सूत्र, एक बार में एक मैच पर ध्यान केंद्रित करना: दीप्ति

दाम्बुला। (भाषा) सीनियर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने कहा कि महिला टी20 एशिया कप में भारतीय टीम का सफलता का सूत्र एक बार में एक मैच पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब टीम पिछली बार यहां खेली थी तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।भारत ने ग्रुप ए के अंतिम मैच में मंगलवार को नेपाल को 82 रन से करारी शिकस्त दीजिए। इस मैच में शेफाली वर्मा ने 48 गेंद पर 81 रन की तूफानी पारी खेली थी जबकि दीप्ति ने 13 रन देकर 3 विकेट लिए थे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर

178 रन बनाए और इसके बाद नेपाल को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन पर रोक दिया था। दीप्ति ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, हम पहले मैच से ही प्रत्एक मैच और प्रत्एक परिस्थिति को लेकर काफी आश्वस्त हैं। अब हमारी निगाह सेमीफाइनल पर है। भारतीय टीम इससे पहले जून 2022 में यहां खेली थी और दीप्ति ने कहा कि तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं बदला है। हमने इसे सरल बनाए रखा है और हमारा ध्यान केवल अगले मैच पर केंद्रित रहता है। मैं पिछली बार भी यहां खेली थी और तब से कोई बदलाव नहीं आया है। हमें खुद पर भरोसा है और परिस्थितियां पहले जैसी हैं। इस ऑफ़ स्पिनर ने अभी तक तीन मैच में 8 विकेट लिए हैं और उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की स्थिति में गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहती हैं।

स्पेन, अर्जेन्टीना के फुटबॉल मैच के साथ पेरिस ओलंपिक में प्रतियोगिताएं शुरू

पेरिस। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को प्रतियोगिताओं की आधिकारिक शुरुआत हुई जब स्पेन और अर्जेन्टीना क्रमश: पेरिस और सेंट एटीने में अपने-अपने फुटबॉल मुकाबलों के लिए मैदान पर उतरे। स्पेन की टीम पश्चिम पेरिस के पार्स डेस प्रिंसेस स्टेडियम में उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी। स्टार खिलाड़ी काइलियान एमबाप्पे जब पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से खेलते थे तो यह उनका घरेलू मैदान था। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो ने इस मुकाबले से पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की। टूर्नामेंट का पहला गोल स्पेन के राइट बैक मार्क पुबिल ने 29वें मिनट में दागा। दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेस्सी के बिना ओलंपिक में खेल रही अर्जेन्टीना की टीम अपने पहले मुकाबले में मोरक्को के खिलाफ सेंट एटीने के ज्योफ्री गुइचर्ड स्टेडियम में उतरी।

फिर आईओसी सदस्य चुनी गईं नीता अंबानी

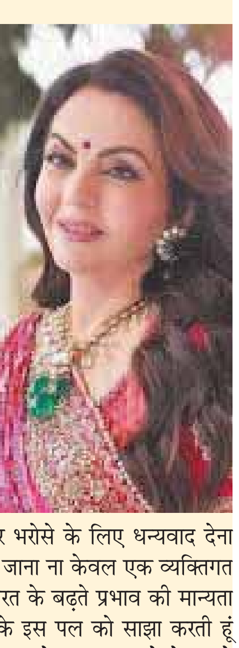

नई दिल्ली। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को बुधवार को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का सदस्य चुना गया। पेरिस में चल रहे आईओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता को शत प्रतिशत मत मिले। नीता ने पुन: आईओसी सदस्य चुने जाने के बाद विज्ञप्ति में कहा, मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं अध्यक्ष (थॉमस) बाक और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों को मुझ पर उनके विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने कहा, फिर से (सदस्य) चुना जाना ना केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव की मान्यता भी है। मैं हर भारतीय के साथ खुशी और गर्व के इस पल को साझा करती हूं और भारत तथा दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हूं। नीता को पहली बार 2016 में रियो डि जिनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल किया गया था। वह आईओसी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला हैं।

शीतकालीन ओलंपिक: फ्रांस को 2030 और अमेरिका को 2034 की मेजबानी

पेरिस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने बुधवार को 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया। फ्रांस को मेजबानी कुछ शर्तों के आधार पर सौंपी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आईओसी को आश्वासन दिया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के संपन्न होने के बाद जो भी सरकार गठित होगी वह आयोजन से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगी। इन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। फ्रांस में नई सरकार के गठन के बाद जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उन्हें इन शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। आईओसी ने इसके लिए एक अक्टूबर की समय सीमा तय की है।आईओसी के सदस्यों ने उनके आश्वासन को स्वीकार करके फ्रांस को मेजबानी सौंपने के पक्ष में मतदान किया। फ्रांस की मेजबानी के पक्ष में 84 सदस्यों ने जबकि चार सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। सात सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिय।

पेरिस ओलंपिक को निशाना बनाने की साजिश में गिरफ्तार लोगों में रूस का व्यक्ति भी शामिल

पेरिस। फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2024 ओलंपिक को बाधित करने की कई साजिशों को नाकाम कर दिया है जिसमें से एक में रूस के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने पेरिस में खेलों के उद्घाटन समारोह से कुछ दिन पहले बुधवार को यह जानकारी दी। ओलंपिक की मेजबानी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने के कारण पिछले कुछ हफ्तों से फ्रांस में हाई अलर्ट है। शुक्रवार को सीन नदी पर एक भव्य और उच्च सुरक्षा वाले उद्घाटन समारोह के साथ खेलों की आधिकारिक शुरुआत होगी। पेरिस के अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने ओलंपिक खेलों को अस्थिर करने की योजना बनाने के संदेह में मंगलवार को एक 40 वर्षीय रूसी व्यक्ति को पेरिस में उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया।

भारतीय ओलंपिक टीमों का विवादों से नाता, झगड़ों से लेकर डोपिंग तक

नई दिल्ली (भाषा)। काका पवार और पप्पू यादव को 1996 ओलंपिक तक ज्यादा लोग नहीं जानते थे, दोनों में सिर्फ दो चीजें समान थीं कि दोनों पहलवान थे और दोनों 48 किग्रा वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैट के अंदर और बाहर भिड़ंत को तैयार थे। लगभग 28 साल पहले दोनों के बीच भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए आईजी स्टेडियम में भिड़ंत हुई थी। यादव ने विवादास्पद ट्रायल जीत लिया था लेकिन अटलांटा में वजन मापने की प्रक्रिया में विफलता के बाद उन्हें ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय खेलों और विशेष रूप से कुश्ती ने अपने अतीत से कोई सीख नहीं ली क्योंकि हर चार साल में होने वाले इस महाकुंभ में भाग लेने से पहले हमेशा विवादों का बोझ बना रहता है। छह भारतीय पहलवान सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक जैसे नायकों की विरासत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाए हैं। लेकिन उन्हें पता है कि पेरिस जाने वाली टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ा है जिसमें एक साल तक विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, जिसके कारण उनकी तैयारियों में बाधा पड़ी। पवार और यादव इसी व्यवस्था के शिकार थे जो आज भी मौजूद है। दोनों 48 किग्रा वर्ग में अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संस्था द्वारा दिए गए वाइल्डकार्ड स्थान के लिए भिड़ रहे थे। राजनीतिक दिग्गजों ने दोनों पहलवानों का

समर्थन किया जिससे यह बड़ा विवाद बन गया जिसमें रेफरी को फिक्स करने से लेकर वजन मापने में धांधली करने के आरोप लगे। हालांकि यादव ने विवादास्पद मुकाबला जीत लिया और अटलांटा चले गए, लेकिन वे वजन मापने की प्रक्रिया में विफल हो गए और बिना प्रतिस्पर्धा के ही वापस लौट आए। ऐसा ही नरसिंह यादव के साथ 2016 रियो ओलंपिक से पहले हुआ था, हालांकि कारण अलग था। नरसिंह ने 74 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में भारत को ओलंपिक कोटा दिलाकर सभी को चौंका दिया था। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के भार वर्ग (66 किग्रा) को खत्म कर दिया था जिसके बाद इस पहलवान को 74 किग्रा वर्ग में खेलना पड़ा। सुशील ने ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में ट्रायल के लिए अनुरोध किया ताकि यह तय किया जा सके कि उनमें और नरसिंह में से किसे रियो जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरसिंह के चयन को चुनौती देने वाली सुशील की याचिका को खारिज कर दिया। इससे नरसिंह को खेलने की अनुमति मिल गई। हालांकि ओलंपिक से तीन सप्ताह पहले नरसिंह को प्रतिबंधित दवा के लिए पॉजिटिव पाया गया। पहलवान ने खुद को फंसाने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया। हालांकि ओलंपिक में भाग लेने का उनका सपना तब टूट गया जब खेल पंचाट ने नाडा द्वारा उन्हें दी गई क्लीनचिट के खिलाफ विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की अपील को बरकरार रखा। पेरिस ओलंपिक से पहले कुश्ती फिर से गलत कारणों से चर्चा में रही, जब छह शीर्ष पहलवानों ने तब डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय संस्था को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और खेल मंत्रालय दोनों ने अलग अलग कारणों से निलंबित कर दिया। अब नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक नया राष्ट्रीय महासंघ स्थापित हो चुका है। इस विरोध और अदालती मामलों ने भारतीय कुश्ती को जो नुकसान पहुंचाया है वह पेरिस के लिए क्वालीफाई करने वाले पुरुष पहलवानों की संख्या से साफ झलकता है। अमन सेहरावत एकमात्र पुरुष पहलवान हैं जो पेरिस में अपनी किस्मत आजमाएंगे। भारोत्तोलन ने भारत को ओलंपिक में काफी गौरव दिलाया है जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और मीराबाई चानू ने तोक्यो 2021 में रजत पदक जीता था। लेकिन सनमाचा चानू और प्रतिमा कुमारी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में डोपिंग के कारण भारत को बदनाम किया था जबकि इससे कुछ दिन पहले डबल-ट्रैप निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलों में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत रजत पदक दिलाया था। बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए एकमात्र भारोत्तोलक मोनिका देवी एनाबॉलिक पदार्थ के लिए पाजिटिव आने के बाद इसमें हिस्सा लेने से चूक गईं। राठौड़ के रजत पदक जीतने और 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा के देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के बाद से निशानेबाज भारतीय दल का गौरव रहे हैं। पिस्टल निशानेबाज विजय कुमार और राइफल निशानेबाज गगन नारंग ने 2012 लंदन में इसी परंपरा को बरकरार रखा। लेकिन भारतीय निशानेबाज 2016 रियो और तोक्यो 2021 में पदक जीतने में विफल रहे।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह।
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।